खण्ड-169, अंक-2
मंगलवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(20 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 169 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE
25 JUL 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २० मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री

जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री

मथुराप्रसाद पाँडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्रशर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन. श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री

वासुदेव मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनौत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २० मार्च, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

परगनाधीश घोसी, जिला आजमगढ़ के खिलाफ शिकायतें

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उन्हें एक पत्र दिनांक १७-९-५५ को भेजा था, जिसमें परगनाधीश घोसी, (आजमगढ़) पर आरोप लगाते हुए उन्होंने जांच कराने तथा अन्य कार्यवाही करने की प्रार्थना की थी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय सदस्य का दिनांक १७-९-५५ का कोई पत्र इस समय नहीं मिल रहा है, किन्तु एक पत्र दिनांक २०-१०-५५ का अवश्य आया था।

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय——यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि श्री बनवारीलाल का तबादला अलीगढ़ हो गया है इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई नियम है कि जिस अधिकारी या कर्मचारी का तबादला हो जाय, तो उसके किये गये अवैधानिक एवं पक्षपातपूर्ण कार्यों की जांच न की जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर उसका कोई खास अपराध हो तो जरूर की जाय, लेकिन शिकायतें तो इस किस्म की थीं कि वह प्रजा समाजवादी पार्टी से नाराज रहते हैं। यह एक ऐसी जनरल चीज है कि इसकी कोई जांच हो भी नहीं सकती और न जरूरत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि बनवारी लाल का तबादला उसके पहले दो बार और हो चुका था, जिसे कैन्सिल कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं जानता हूं कि उनका तबादला रोक दिया गया था, क्योंकि बाढ़ की वजह से खास परिस्थिति थी और वह उस हिस्से से काफी वाकिफ थे, इसलिए सोचा गया कि उन्हें वहां रोक देना चाहिए।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)——क्या सरकार, जो पत्र रामसुन्दर जी पांडेय ने भेजा है, उसकी मुख्य मुख्य शिकायतें सदन को बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी, वह खत मेरे पास है और उसमें जिस किस्म की शिकायतें हैं, उसका इसी से अन्दाज हो सकता है कि श्री बनवारीलाल जी को इस तहसील में ३ वर्ष से अधिक रहते हुए हो गये हैं और बराबर इस बात का जिक्र है कि वह पक्षपात करते हैं, आजमगढ़ में। दो पेज में थ्रू आउट इसी बात की शिकायत है कि हर मामले में वे प्रजा समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो आरोप मेरे द्वारा लगाये गये हैं, क्या उनकी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर किसी खास मुकदमे में आरोप हो कि पक्षपातपूर्ण और गलत फैसला कर दिया, तो जांच हो सकती है, लेकिन एक जनरल आरोप की जांच बहुत मुश्किल है।

तारांकित प्रश्न

दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ की पम्प कैनाल के सम्बन्ध में पूछताछ

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ की पम्प कैनाल नहर की खुदाई कितने मील तक हो चुकी है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—६७ मील लम्बी सारी मुख्य नहर पर खुदाई जारी है और लगभग दो तिहाई मिट्टी का काम भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ जिले में स्थित उक्त नहर की निम्नलिखित रजबहलों तथा माइनरों पर लगभग पूरी लम्बाई में काम हो रहा है।

(१) करोली माइनर
(२) सूरजपुर रजबहा।
(३) नाथूपुर रजबहा।
(४) इन्दौरा माइनर।
(५) सिकन्दरपुर रजबहा।
(६) पुर रजबहा।
(७) रटसारपुर रजबहा।
(८) सुखपुरा माइनर।

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर भेज देने के पश्चात् मुख्य इंजीनियर सिंचाई विभाग से एक और सूचना प्राप्त हुई। इसके अनुसार "दो तिहाई" के बजाय "लगभग ७० प्रतिशत" कार्य हो चुका है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट पम्प कैनाल नहर की शाखायें और उप-शाखायें आजमगढ़ और बलिया जिले के किन किन गांवों से होकर जायेंगी ?

श्री राममूर्ति—उपरोक्त मुख्य नहर तथा शाखायें व उप-शाखायें आजमगढ़ तथा बलिया जिलों के बहुत से ग्रामों से होकर गुजरेंगी। मुख्य ग्रामों की सूची मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५६—१५९ पर।)

३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बनाने की कृपा करेगी कि सितम्बर, सन् १९५५ तक निर्माण कार्य और खुदाई में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—३० सितम्बर, १९५५ तक दोहरीघाट कैनाल सिस्टम पर लगभग २३,००,००० रुपया व्यय हो चुका था।

फरवरी, १९५६ के अन्त तक दोहरी घाट की योजना पर लगभग ४४,००,००० रुपया व्यय हो चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य नहर से पानी कब तक मिलने लगेगा ?

श्री राममूर्ति—अभी तो ३० फीसदी खुदाई बाकी है। जब यह पूरी हो जाय-तब यह सवाल पैदा होगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि तालपुर की जो पम्प कैनाल है, वह दोहरीघाट कैनाल का भाग मानी जायगी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उसका भाग तो काहे को माना जायगा, हां, आजमगढ़ जिले को वह पानी अवश्य देगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नहर दोहरीघाट की आजमगढ़ जिले के पूर्वी जिले के किस स्थान पर लायी जा सकती है ?

श्री राममूर्ति—इसमें नम्बरवार गांवों की सूची दी हुई है, उसमें लिखा है कि कहां-कहां होकर जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९५६ तक जो रुपया व्यय हुआ है, उसमें से कितना रुपया निर्माण कार्य और कितना खुदाई में व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में खुदाई भी निर्माण कार्य में समझी जाती है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि सरकार की कोई ऐसी योजना है कि कोई नहर सूख जाने के पहले भी जो उसका पक्का हिस्सा बन चुका है, उसमें से सिंचाई का सिलसिला शुरू हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बात यह है कि यह नहर बिजली से चलेगी। पम्प से पानी घाघरा से उठायेंगे, तब नहर चलेगी, और सिंचाई करेगी। तो थोड़ा बहुत पानी टेस्टिंग के लिए सम्भवतः हम लेंगे, क्योंकि पूरी नहर तो तब चलेगी, जब पूरी तरह से बिजली मिल जायगी। सम्भवतः इस वर्ष के अन्त तक या अगले वर्ष के प्रारम्भ तक बिजली मिल जायगी, लेकिन उसका जितना पक्का हिस्सा है, उसमें थोड़ा-बहुत पानी उठाकर छोड़ देने की कोशिश करेंगे और टेस्टिंग करेंगे कि किस तरह से वह चल रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर की मुख्य नहर और शाखाओं, उपशाखाओं से कितने एकड़ सिंचाई हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सम्भवतः इसके लिए नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जहां तक मुझे याद है, करीब डेढ़ लाख एकड़ के ऊपर सिंचाई होती है।

पूर्वी यमुना, अपर तथा लोअर गंगा, आगरा और शारदा नहरों में पानी बढ़ाने की योजनायें

*४--**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी यमुना नहर, अपर तथा लोअर गंगा, आगरा नहर और शारदा नहर में पानी बढ़ाने की क्या-क्या योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं और कितना पानी बढ़ने की आशा है ?

श्री राममूर्ति--पूर्वी यमुना नहर की क्षमता २,२५० से ४,००० क्युसेक्स तक बढ़ाने के लिए उसका पुनः निर्माण हो रहा है जिससे उक्त नहर ताजेवाला हेड वर्क्स पर इसे प्रदेश का यमुना के पानी का पूरा हिस्सा यानी ४,५०० क्युसेक्स ले सकेगी। बढ़े हुए पानी से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, व मेरठ जिलों में खरीफ में धान की सिंचाई होगी। बचा हुआ पानी कल्सी इस्केप से यमुना नदी में बहा दिया जायगा, जो ओखला पर आगरा कैनाल में ले लिया जायगा।

अपर तथा लोअर गंगा नहर, आगरा नहर और शारदा नहर में पानी बढ़ाने की निम्न-लिखित योजनाओं को द्वितीय पैंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है:-

(१) नानक सागर प्रोजेक्ट।
(२) सारदा सागर (स्टेज २) प्रोजेक्ट।
(३) राम गंगा रिवर प्रोजेक्ट।

नानक सागर प्रोजेक्ट और शारदा सागर प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने पर शारदा नहर की क्षमता २,५०० क्युसेक्स (१,००० क्युसेक्स नानक सागर व १,५०० क्युसेक्स सारदा सागर से) बढ़ जायेगी। रामगंगा जलाशय के पूर्ण हो जाने पर पानी में ५,००० क्युसेक्स की वृद्धि होगी। उसके भिन्न-भिन्न नहरों पर उद्योग के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया है, परन्तु इस जलाशय के बन जाने के बाद लोअर गंगा कैनाल को पानी उससे मिलेगा और इस कैनाल के लिए जो पानी हरद्वार में गंगा में जाने दिया जाता है, वह अपर गंगा कैनाल में दिया जा सकेगा।

१५ मई से वर्षा आरम्भ होने तक गंगा में पानी की वृद्धि होती है, इस बढ़े हुए पानी को लेने के लिए अपर गंगा नहर की क्षमता ८,००० क्युसेक्स से १०,१०० क्युसेक्स बढ़ायी जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अधिक सिंचाई हो सकेगी और खरीफ की सिंचाई में काफी वृद्धि होगी।

आगरा कैनाल का हेड से १०० मील तक पुनः निर्माण हो रहा है जिससे उसकी क्षमता २,००० से ३,२५० क्युसेक्स हो जायगी। बढ़े हुए पानी से खरीफ की सिंचाई में वृद्धि होगी और मथुरा तथा आगरा जिलों में पलेवा नहरों द्वारा सिंचाई हो सकेगी।

*५--**श्री श्रीचन्द्र**--प्रत्येक योजना में कितना-कितना रुपया सरकार का व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति----उक्त प्रोजेक्ट्स पर अनुमानित व्यय निम्नलिखित है :---

प्रोजेक्ट्स	अनुमानित व्यय रुपयों में
(१) पूर्वी यमुना नहर	६९.४ लाख
(२) नानक सागर	२.८३ करोड़
(३) सारदा सागर (स्टेज २)	९.८४ करोड़
(४) राम गंगा रिवर प्रोजेक्ट	१७.९८ करोड़ (पावर अंश की लागत छोड़कर।)
(५) अपर गंगा नहर	१५.४४ लाख
(६) आगरा कैनाल (हेड से मील १०० तक)	५३.२१ लाख

*६---श्री श्रीचन्द्र---इन योजनाओं से प्रत्येक नहर पर कितने एकड़ की अधिक सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति---भिन्न-भिन्न नहरों पर उक्त योजनाओं से अधिक सिंचाई के आंकड़े क्षेत्रवार अभी नहीं निकाले गये हैं किन्तु इन योजनाओं से निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ---

योजना	भूमि एकड़ों में
(१) पूर्वी यमुना नहर	१५,०००
(२) नानक सागर प्रोजेक्ट	९६,७५०
(३) सारदा सागर (स्टेज २) प्रोजेक्ट	३,१९,०००
(४) राम गंगा रिवर प्रोजेक्ट	७,००,०००
(५) अपर गंगा नहर	१,१२,०००
(६) आगरा नहर	३६,२०७

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जमुना नहर में अब तक क्या प्रगति हो गई है और यह कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति---जहां तक कि जमीन की खोदाई और मिट्टी वगैरह के कार्य का सम्बन्ध है वह कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन जो पुल सड़सठवें मील तक हैं वह पूरे नहीं हो पाये हैं। उम्मीद की जाती है कि अगली दिसम्बर तक पूरे हो पायेंगे ।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जमुना नहर से ४ हजार क्यूजेक्स पानी की क्षमता की जा रही है क्या उससे कोई ऐसी तरकीब की जायगी जिससे उससे साढ़े ४ हजार क्यूसेक्स पानी मिल सके ?

श्री राममूर्ति---यह अंतिम लिमिट है जब यह नहर तैयार हो जायेगी और उसके फाटक वगैर तैयार हो जायेंगे उसके बाद इतना पानी मिल सकेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह पानी रबी की फसल में कितना बढ़ जायगा खरीफ की फसल को छोड़कर ?

श्री कमलापति त्रिपाटी---रबी में तो ज्यादा पानी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जमुना नहर के सम्बन्ध में पंजाब सरकार एक समझौते के मुताबिक हमको पानी देती है और उस समझौते के सम्बन्ध में यहां दो एक बार पहले उत्तर भी दिया जा चुका है और खास अनुपात है कि इतने हजार क्यूसेक्स पानी जमुना नहर में होगा तो इतना पंजाब सरकार लेगी और इतना पानी हमको देगी। अभी एक नया समझौता हुआ है कि जो पानी बढ़ेगा वह भी उसी अनुपात से चलेगा । जमुना नदी में जो पानी रहता है उसमें इतनी वृद्धि नहीं रहती है कि उस अनुपात से ज्यादा हमको मिल सके इसलिये रबी में बहुत ज्यादा वृद्धि की सम्भावना नहीं है ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नहरों में जो पानी बढ़ाने की योजना है उसके द्वारा जो नहर

आलरेडी हैं उन्हीं के कमान्ड एरिया से पानी ज्यादा मिलेगा या नहरें अलग से खुदवाई जायेंगी, जिनके द्वारा अलग से जमीन सींची जा सकेगी ?

श्री राममूर्ति---दोनों बातें ठीक हैं। कुछ नई भी बढ़ाई जायेंगी और जो मौजूद हैं उनका विस्तार भी किया जायगा।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार अपर गंगा नहर में और पानी बढ़ाने के लिये सोलानी नदी में बांध बांध कर उसमें रिजरवायर बनाने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति---अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कल्सो एस्केप से जो पानी जमुना में डाला जायगा वह बरसात को छोड़ कर शेष मौसम में देहली की आवश्यकता की वजह से पानी जमुना कैनाल में नहीं जा सकेगा ?

श्री राममूर्ति---यह पानी बरसात में ही बचता है तभी मिल सकेगा। रबी में तो पानी बचता ही नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा जलाशय से ५ हजार क्युसेक्स जो पानी लिया जायगा, वह किन-किन नहरों को दिये जाने का विचार है ?

श्री राममूर्ति---लोअर गंगा की जो नहरें हैं उनके लिये वह पानी दिया जायगा।

"श्री सिरोही बनाम राज्य सरकार" नामक मुकदमे में हाईकोर्ट का फैसला

*७---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार का ध्यान श्री बी० एस० सिरौही बनाम राज्य सरकार (रिट नं० ४३५) नामक केस में हाईकोर्ट के बेंच द्वारा किये गये फैसले की ओर आकर्षित हुआ है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां, रिट नम्बर ४३५/१९५५ श्री बी० एस० सिरोही बनाम राज्य सरकार के फैसले की सूचना सरकार को दे दी गई है और तय हो गया है कि इसमें अपील दायर नहीं की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस रिट में हाईकोर्ट की बेन्च ने क्या फैसला किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---हाईकोर्ट का फैसला तो छप जाता है, उसको माननीय सदस्य जानते होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सैयद अली जहीर---उसमें लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ यह बहस आयी थी कि आया उसको दूसरी अपार्चुनिटी दी गयी या नहीं। महज एक्सप्लेनेशन देना अपार्चुनिटी है या नहीं ? उन्होंने यह फैसला किया कि महज एक्सप्लेनेशन मांगना सेकेंड अपार्चुनिटी देना नहीं समझा जायगा। इसी बुनियाद पर सरकार समझती है कि फैसला सही है, लिहाजा और कोई कार्यवाही

करने की जरूरत नहीं है और आयन्दा जो सेकेन्ड अपार्चुनिटी दी जाय उसमें खाली एक्सप्लेनेशन न मांगा जाय बल्कि उसको सबूत भी पेश करने का मौका दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार समझती है कि श्री सिरोही बनाम राज्य सरकार के मुकदमें में हाई कोर्ट के फैसले से जो सरकार ने टेम्पोरेरी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लिये जाने के सम्बन्ध में निकाला है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गयी है?

श्री सैयद अली जहीर—अभी इस तरह का कोई सवाल मेरे खयाल में तो आया नहीं। अगर जरूरत होगी तो किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस अहम फैसले को देखते हुये और यह देखते हुये कि यह फैसला केवल सिरोही साहब से ही नहीं बल्कि राज्य के समस्त टेम्पोररी कर्मचारियों से सम्बन्ध रखता है, वह नोटिफिकेशन बदलवाने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने कहा कि इस पर विचार किया जायगा और अगर जरूरत समझी जायगी, तो बदला जायगा?

बनारस-गाजीपुर सड़क पर क्षति-ग्रस्त पुलों की मरम्मत

*८—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर-बलिया रोड पर देवकली और मुहम्मदाबाद से ४ मील पच्छिम जो एक पुराना पुल था, टूट गया है जिससे आवागमन का मार्ग बन्द हो गया है? यदि हां, तो इन पुलों के बनवाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

निर्माण उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—देवकली के पास बनारस-गाजीपुर सड़क पर गांगी नदी का पुल है जो पिछले वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे पुल के किनारे की एक दीवार बह गई थी। बल्ली और बालू से एक क्रिब की दीवार तत्काल निर्मित कर दी गई और कुछ ही दिनों में पुल यातायात के लिये खुल गया। किनारे की दीवाल के पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और वर्षा ऋतु के पूर्व ही कार्य के समाप्त हो जाने की आशा है। मुहम्मदाबाद के ४ मील पश्चिम में एक दूसरा पुल है जो बेसू नदी पर पड़ता है। यह पुल भी टूट गया था। इसका निर्माण कार्य भी आरम्भ किया जा रहा है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी देवकली और मुहम्मदाबाद के जो पुल बनाये जा रहे हैं उनके खर्च का क्या ऐस्टीमेट है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एक पुल में तो केवल मरम्मत का काम है जो गांगी नदी पर है, उसके बनाये जाने का प्रश्न नहीं है और दूसरा पुल जो बेसू नदी पर पड़ता है, उसका अंदाजा ४,२०,००० रुपये है।

श्री कमलासिंह—क्या मंत्री जी को मालूम है कि अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरी सूचना तो यह है कि एक पुल पर कार्य प्रारम्भ हो गया है और इस पुल पर यातायात कभी बन्द नहीं हुआ। इस पर क्रिब दीवाल बना दी गई है और चल रहा है। दूसरे पुल का ऐस्टीमेट तैयार हुआ है और वह फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास भेजा जायगा और वहां से आने पर कार्य होगा।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि अभी तक वहां कोई कार्य शुरू नहीं हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे खयाल से तो कार्य शुरू हो गया है, लेकिन इसके संबंध में, अगर आप कहते हैं तो, जरूर इंक्वायरी कराई जायगी ।

*९-१०---श्री कमलासिंह---[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१२---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी की जन-संख्या तथा नगर में पानी सप्लाई की व्यवस्था

*१३---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर की इस समय कितनी आबादी है तथा वहां पर जो म्युनिसिपल बोर्ड का वाटरवर्क्स है वह प्रति मनुष्य कितना पानी सप्लाई करता है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार झांसी नगर की जन-संख्या १,०६,२२६ है परन्तु इस समय जल वितरण केवल ६५,००० व्यक्तियों में ही सीमित है । इस तरह झांसी नगरपालिका ७.६५ गैलन प्रति मनुष्य प्रति दिन के हिसाब से जल प्रदान करता है ।

*१४---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि जिस बांध से पानी सप्लाई होता है वह प्रति मनुष्य कितना पानी सप्लाई कर सकता है ?

श्री कैलाशप्रकाश---पाहुज बांध से अधिक पानी मिल सकता है परन्तु सिंचाई विभाग अधिक से अधिक १२·९ लाख गैलन प्रतिदिन देने को इस शर्त पर तैयार हुआ है कि Intake नीचा कर दिया जाय । इस प्रकार जलकल के पुनः संगठन के पश्चात अधिक से अधिक १२ गैलन पानी प्रतिदिन प्रति मनुष्य सारे नगर की जन-संस्था को दिया जायेगा ।

*१५---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पानी की उक्त कमी को पूरा करने के लिये सरकार के पास कोई ऐसी योजना आई है जिसके द्वारा माताटीला बांध से रेलवे छावनी व शहर को पानी सप्लाई हो ? यदि हां, तो वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---ऐसा सुझाव आया था परन्तु लागत और रख-रखाव पर व्यय अधिक होने के कारण इस सुझाव को क्रियात्मक रूप न दिया जा सका ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी किफायत की दृष्टि से माताटीला के बजाय झकुआ-ढकुआ से पानी की सप्लाई की योजना पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह प्रस्ताव तो विचाराधीन था नहीं । जब म्युनिसिपल बोर्ड कुछ लिखेगा तो इसकी जांच की जायेगी ।

जिला देवरिया में पडरौना से भागी पट्टी, समऊर और कसया से पिपराघाट की सड़कों की खराब दशा

*१६---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में पडरौना से भागी पट्टी, समऊर और कसया से पिपराघाट की सड़कों की हालत को देखते हुये उसें पक्की कराने का वह विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि पडरौना से भागी पट्टी समऊर सड़क बिलकुल खराब हो गई है और बरसात में गाड़ियों का आना जाना बन्द हो जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बिल्कुल खराब तो नहीं हुई, लेकिन यह और सड़कों की तरह अच्छी नहीं है यह सम्भवतः ठीक है । मेरी सूचनाओं के अनुसार गाड़ियों का आना-जाना बन्द नहीं हुआ ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसके पास इस सड़क को बनाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सम्भवतः आया हो ।

जिला देवरिया में कठकुइयां–छठियांव सड़क का निर्माण

*१७—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार को ज्ञात है कि कठकुइयां—छठियांव वाली सड़क कब आरम्भ की गई थी और कब तक बन कर तैयार हो जायेगी और उसमें कितने रुपये व्यय होंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सड़क के केवल कठकुइयां गढ़इया भाग पर सीमेंट कांक्रीट ट्रैक बिछाने का कार्य सन् १९४७ में आरम्भ किया गया था, परन्तु वहां के निवासियों के विवाद के कारण यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है । यदि जनता का सहयोग मिला तो यह कार्य डेढ या दो साल में पूरा होने की आशा की जाती है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन विवादों के कारण यह सड़क रुकी हुई थी वह विवाद समाप्त हो गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सिकतर ग्राम के निवासियों ने बाधा डाली थी जिस समय कार्य हो रहा था उन्होंने नहीं होने दिया । बाद में पुलिस की सहायता से कार्य होने दिया ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के लोगों ने किस बात पर विवाद ठाना था ।

श्री अध्यक्ष—उसका तो उन्होंने जवाब दे दिया है ।

*१८–२०—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) [२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

मुबारकपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*२१—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार को गत २३ नवम्बर, ५५ का भेजा मुबारकपुर टाउन एरिया में अनियमितता एवं टैक्सों में ज्यादती के विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, ए० डी० एम० आजमगढ़ के नाम २३ नवम्बर, १९५५ में लिखे पत्र की एक प्रति सरकार को भी मिली थी ।

*२२—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उसकी ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस शिकायती पत्र के, अतिरिक्त टाउन एरिया कमेटी, मुबारकपुर के विरुद्ध कई अन्य शिकायतें भी सरकार के पास आईं, जिन सब पर जिलाधीश द्वारा उचित जांच करवाई गई। जिलाधीश की उक्त जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बतलायेंगे कि मुबारकपुर टाउन एरिया के विरुद्ध कई अन्य प्रकार की शिकायतें जो आई हैं वह किन के जरिये आईं और वह किस प्रकार की हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस टाउन एरिया के खिलाफ शिकायतें कई जगह से आई हैं। मुख्य शिकायतें यह है कि यह अपनी कर सूची समय के अनुसार नहीं बना सका, इनकी सफाई का प्रबंध ठीक नहीं हुआ, जिस सफाई के नायक को इन्होंने मुकर्रर किया है वह कोई हिस्ट्री-शीटर है और स्वयं सदस्य जो हैं वह भी टैक्स अदा नहीं करते, इत्यादि, इत्यादि।

श्री झारखंडेराय---माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश की जांच रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसकी तारीख के लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि टाउन एरिया मुबारकपुर के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं, जिलाधीश की रिपोर्ट उन शिकायतों की तस्दीक करती है ?

श्री अध्यक्ष---जब यह प्रश्न विचाराधीन है तो उसके ऊपर मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिये।

*२३-२४---**श्री उमाशंकर**---[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२६---**श्री ब्रजविहारी मिश्र**---[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हाथरस में मजदूरों के लिये घरों का निर्माण

*२७---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस में मजदूरों के घरों के बनाने की स्वीकृति कब हुई थी और उनके लिये सरकार ने जमीन प्राप्त कर ली है ?

श्री कैलाशप्रकाश---हाथरस में मजदूरों के लिये घरों के बनाने की स्वीकृति जुलाई, सन् १९५५ में हुई थी। जमीन प्राप्ति के लिये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और उस पर कब्जा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मकानों पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन कब तक प्राप्त हो सकेगी और मकान कब तक बनना शुरु हो जायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---जैसा मैंने निवेदन किया विज्ञप्ति निकल चुकी है और उसके अनुसार कुछ समय दिया जाता है अधिकार लेने के लिये। वह समय जब समाप्त हो जायेगा तो उस पर अधिकार कर लिया जायेगा और कार्य जारी हो जायेगा।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड के सफाई कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मकान तो, जो लोग फैक्ट्री आदि में काम करते हैं, उनके लिये बनते हैं और उन्ही के लिये यह बन रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---यह जो मकान बन रहे हैं इसमें कितने क्वाटर्स बनेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---२१६ ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंग कि यह मकान किस शर्त पर मजदूरों को दिये जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो किराये पर दिये जाते हैं, वैसे ही दिये जायेंगे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इस जमीन की बाबत काश्तकारों ने सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र दिया है यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---एक जमीन पहले ली गयी थी, वह तो छोड़ दी गयी थी। अब यह दूसरी जमीन ली जा रही है। शायद आप पहली की बाबत कह रहे हैं।

*२८---**श्री व्रज भूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)---[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२९-३०---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर दीवानी कचहरी के लिये नये भवन की आवश्यकता

*३१---**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार को विदित है कि दीवानी कचहरी, फतेहपुर की इमारत इतनी छोटी और खराब है कि न तो सब अदालतों के लिये उपयुक्त स्थान ही है और न सुविधापूर्वक अदालतें ही लग पाती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, सरकार को यह विदित है कि दीवानी कचहरी फतेहपुर के लिये एक नई इमारत की आवश्यकता है।

*३२---**श्री अनन्तस्वरूप सिंह**---अगर हां, तो क्या सरकार दीवानी कचहरी फतेहपुर के लिये नई इमारत बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार दीवानी कचहरी फतेहपुर के लिये एक नयी इमारत बनवाना चाहती है किन्तु अभी तक इस इमारत के बनवाने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका है।

*३३---**श्री अनन्तस्वरूप सिंह**---अगर हां, तो क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि वह नई इमारत कलक्टरी, कचहरी के बिलकुल समीप हो ताकि जनता और वकील साहबान को सुविधा पहुंच सके ?

श्री सैयद अली जहीर---अभी यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह---क्या माननीय न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दीवानी कचहरी फतेहपुर की नयी इमारत बनाने के लिये सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सैयद अली जहीर---धन की कमी है और तो कोई खास कठिनाई नहीं है।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह---क्या यह सही है कि पारसाल जब न्याय मंत्री जी फतेहपुर तशरीफ ले गये थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र यह इमारत बन जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, इमारत जरूर बनेगी, लेकिन यह कब बनेगी यह सवाल है ।

*३४-३५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला खीरी की कुछ सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने पर विचार

*३६--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार जिला खीरी की उन सड़कों को जो मध्यवर्तियों ने बनवाई थी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं ।

*३७--श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार को जिला बोर्ड खीरी द्वारा इस विषय में कोई पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं ।

श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खीरी में पुराने ताल्लुकेदारों की कुछ पक्की सड़कें जनता के आम इस्तेमाल में रही हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सही है कि आम इस्तेमाल में रही होंगी ।

*३८--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३९-४०--श्री रामलखन मिश्र--[५ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४१-४३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[२ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५३-५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गाजीपुर नगरपालिका को पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिए सरकारी सहायता

*४४--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका में पीने का पानी का प्रबंध करने के लिये नगरपालिका को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां । ऋण १,७५,००० रु०, अनुदान ५८,००० रु० ।

श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब सहायता दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह कर्जा १९५० में ९० हजार रुपया, सन् १९५३ में ७५ हजार रुपया और अनुदान १९५३ में ५० हजार रुपया, सन् १९५५ में ८ हजार रुपया दिया गया ।

श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसकी बाबत क्या काम हुआ और कितना खर्चा हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश---वह काम हो रहा है जिस काम के लिये रुपया लिया गया ।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या यह सत्य है कि समाजवादी सरकार के होते हुये भी गाजीपुर शहर में पानी पर कंट्रोल है ?

श्री सैयद अली जहीर---कंट्रोल तो हर चीज पर है सिवाय हवा के । मेरे ख्याल में रोशनी पर भी कंट्रोल है और अनाज पर तो है ही ।

श्री कमलासिंह---२ साल पहले जब रुपया मंजूर हुआ था तो अभी तक नल का इंतजाम क्यों नहीं किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो रुपया दिया गया है उसे वे काम में ला रहे हैं । वहां के नल का इंतजाम का सवाल है ।

इलाहाबाद में बांध व संगम के बीच की भूमि को कटाव से रोकने का प्रबन्ध

*४५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद में त्रिवेणी पर जहां पर गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम होता है, वहां पर एक टीला (धुस) बहुत पुराना बनाया गया था वह कट गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां ।

*४६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान पर सुरक्षा का प्रबंध शीघ्र करने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बांध और संगम के बीच की भूमि को गंगा की धार से कटने से बचाने के लिये सुरक्षा कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---वे सुरक्षा कार्य क्या होंगे और उनमें क्या व्यय होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय तो ब्रेडलिंग प्रोसैस से कुछ थोड़े से क्रिब वाल्स बनाये गये हैं, यानी वुडेन इस्ट्रक्चर बनाकर कटाव को रोकने का काम किया गया है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरस्वती नदी गंगा में कहां मिलती हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---हम लोगों को तो दिखायी नहीं देती । माननीय सदस्य ने देखा हो तो बतला दें ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---वह कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जनवरी और फरवरी में हुआ और अब भी चल रहा है ।

भगौतीगंज बाजार को बलरामपुर नगरपालिका में शामिल करने का प्रस्ताव

*४७---**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)---क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या भगौतीगंज बाजार को बलरामपुर नगरपालिका के क्षेत्र में शामिल करने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश---भगौतीगंज बाजार बलरामपुर नगरपालिका के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगौतीगंज बाजार की नुमाइन्दगी बलरामपुर नगरपालिका में किस तरह से होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्रतिनिधित्व तो नियम के अनुसार होगा।

न्याय पंचायतों के पंचों की नामजदगी

*४८---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्याय पंचायतों के पंचों की नामजदगी कब तक हो जायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्रश्न विचाराधीन है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या मंत्री जी ने कोई सर्कुलर जिला मैजिस्ट्रेटों के पास इस सम्बन्ध में भेजा है और क्या वह अब भी उसी स्थिति में हैं या पूरी तरह से बदल दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---एक सर्कुलर गया था, लेकिन जैसा कहा गया है अभी मामला विचाराधीन है।

जिला इटावा तहसील भर्थना के अन्तर्गत ऊमर खेड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान को उनके पद का चार्ज दिया जाना

*४९---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में भर्थना तहसील के अन्तर्गत ऊमर खेड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव हुये करीब १ वर्ष के व्यतीत होने को है परन्तु प्रधानी का चार्ज नये प्रधान को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। ऊमरखेड़ा गांव पंचायत के प्रधान को उनके पद का चार्ज दिला दिया गया है।

जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के मझौआ ताल के पानी के निकास की योजना

*५०---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के मझौआ ताल के पानी के निकास की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति---इस कार्य के हेतु एक नाला बनाने की योजना मंजूर की जा चुकी है।

*५१---श्री विश्रामराय---यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री राममूर्ति---नाले की खुदाई का काम बहुत कुछ हो चुका है और आशा है कि कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।

डोगनी नाले के पुल का निर्माण

*५२---श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ताल सलोना पम्प नहर के समीप स्थित ध्वस्त डोगनी के पुल का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कब तक सम्पन्न होगा ?

श्री राममूर्ति---डोगनी नाले पर एक पुल तथा रेगुलेटर का निर्माण हो रहा है। आशा है यह कार्य शीघ्र समाप्त हो जायेगा।

*५३---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की यादगार में स्मारक बनाने का तथा उनके लेखों आदि के प्रकाशन का सुझाव

*५४–श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)––क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की यादगार सदा ताजी बनाये रखने के लिये वह कानपुर में कोई स्मारक बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो यह योजना कब तक कार्यरूप में परिणत हो सकेगी और उसकी रूप रेखा क्या है ।

सूचना मंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)––जी नहीं, अभी ऐसा कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*५५–श्री रामदुलारे मिश्र––क्या सरकार अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के चुने हुये लेखों उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं तथा उनका प्रामाणिक जीवन परिचय अपनी ओर से प्रकाशित करने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव––जी नहीं । सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामदुलारे मिश्र––क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न को सुझाव समझ कर इसे कार्यान्वित करने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––माननीय सदस्य ऐसा कोई सुझाव भेजें तो गवर्नमेंट उस पर कुछ विचार करे ।

जिला बलिया के अन्तर्गत सुरहा ताल में जल-कुम्भी द्वारा धान को क्षति

*५६––श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)––क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत सुरहा ताल जलकुम्भी (एक प्रकार की जल घास) से पूर्ण रूपेण आच्छन्न है, जिसके कारण हजारों मन धान की क्षति प्रति वर्ष होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––सुरहा ताल का जल क्षेत्र लगभग ९,००० एकड़ है, जिसमें से लगभग ५०० एकड़ जलकुम्भी से आच्छन्न है । जलकुम्भी वायु के साथ चलती है और धान के खेतों को हानि पहुंचाती है ।

*५७––श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)––क्या यह सही है कि कैथवली ग्रामवासियों (बलिया) द्वारा समर्पित मान-पत्र में सिंचाई मंत्री से जलकुम्भी के उन्मूलनार्थ प्रार्थना की गयी थी ? यदि हां, तो मंत्री महोदय इस दिशा में क्या कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––सुरहा ताल से जलकुम्भी निकालने के लिये प्रार्थना की गयी थी । जांच-पड़ताल की जा चुकी है । अनुमानतः जलकुम्भी निकालने में लगभग ५०,००० रु० व्यय होगा यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

उन्नाव जिलान्तर्गत गांव-सभाओं के चुनाव

*५८–श्री देवदत्त मिश्र––क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में कितनी गांव-सभाओं के चुनाव सम्पूर्ण सम्पन्न हो गये तथा कितनी गांव सभाओं के चुनाव अभी कराने हैं ?

श्री कैलाशप्रकास––उन्नाव जिले की समस्त गांव सभाओं के चुनाव सम्पन्न हो गये हैं । परन्तु ६३६ गांव सभाओं में अब भी ४,१९२ सीटें भरनी बाकी है ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये चुनाव कब तक हो जावेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसमें चुनाव का प्रश्न अभी नहीं उठता है, क्योंकि प्रविधान यह है कि चुनाव होगा और यदि उपचुनाव के पश्चात् कोई सीट खाली रह जायगी तो नामजदगी होगी।

जिला उन्नाव की न्याय पंचायतों के लिए सदस्यों का मनोनयन

*५९--श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायतों के लिये सदस्यों का मनोनयन कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न विचाराधीन है।

श्री देवदत्त मिश्र--इन न्याय पंचायतों के बनने के समय तक जो पंचायतों की परिधि में आने वाले मुकदमे हैं उनकी क्या स्थिति है ?

श्री कैलाशप्रकाश--वे अभी स्थगित हैं।

*६०--श्री रघुराजसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)-- [१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला गोंडा में परसपुर-नवाबगंज सड़क को पक्का करने का कार्य

*६१--श्री रघुराज सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में परसपुर से नवाबगंज जाने वाली सड़क को पक्का बनाने का कार्य कब से आरम्भ होने जा रहा है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--अगले वित्तीय वर्ष में।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलियों पर "वाटर वे" के विस्तार की योजना

*६२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन पांच जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुलियों पर "वाटर वे" के विस्तार की योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह योजना १५ जिलों में है जिनके नाम ये हैं :
फर्रुखाबाद, हमीरपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा, इलाहाबाद, जौनपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, सीतापुर तथा खीरी।

*६३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक "वाटर वे" पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सूचना सदस्य की मेज पर रख दी गई है--

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६०-१६५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये काम जो १५ जिलों में होने वाले हैं क्या ये बरसात आने के पहले पूरे हो जावेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, उन पर कार्य प्रारम्भ होने की आज्ञा हो चुकी है।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पूरी योजना में सरकार का कुल कितना व्यय होगा ?

† श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पुलियों की वाटर वे के विस्तार की दो योजनायें फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी थीं। प्रथम योजना की अनुमानित लागत ७,६८,८०० रु० है तथा दूसरी योजना की अनुमानित लागत ६,९९,४५० रु० है। इस प्रकार दोनों योजनाओं का कुल व्यय १४,६८,२५० रु० है।

बनारस के घाटों का पुर्ननिर्माण

*६४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस के घाटों के पुर्ननिर्माण की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—घाटों की प्रगति निम्नलिखित है :—

	घाटों के नाम	प्रगति
(१)	चेत सिंह घाट	कार्य समाप्त हो चुका है।
(२)	गुलरिया घाट	४० प्रतिशत
(३)	विजयनगरम् घाट	३० प्रतिशत
(४)	त्रिपुरा भैरवी घाट	३५ प्रतिशत
(५)	मीर घाट	
(६)	मीर घाट और ललिता घाट के बीच का भाग	
(७)	शीतला घाट और दशाश्वमेध घाट ..	३५ प्रतिशत
(८)	दुर्गा घाट और ब्रह्मा घाट	१५ प्रतिशत
(९)	बूंदी परकोटा घाट	

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस के ९ घाटों में जो अब तक कार्य हुआ है उसमें प्रत्येक में कितना खर्चा हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके तो मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि जब कि कुछ घाटों पर ४० प्रतिशत कार्य हुआ है तो कुछ घाटों पर १५ प्रतिशत कार्य ही क्यों हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, इस संबंध में कई प्रकार की कठिनाइयां हुईं। घाटों के लिये लोहे की चादरों की आवश्यकता थी। ख्याल यह किया जाता है कि टाटा आयरन कंपनी से वह मिल जायंगी लेकिन उनको जर्मनी से मंगाना पड़ा। कहीं-कहीं पुराने टूटे हुए घाटों और पत्थरों के टुकड़ों को निकालने में कठिनाई हुई। इन कारणों से कहीं काम अधिक हुआ और कहीं कम हुआ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वाराणसी के घाटों पर कुल कितना रुपया खर्च होने वाला है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बिल्कुल निश्चित तो नहीं बता सकता, लेकिन करीब १ करोड़ रुपया के व्यय होगा।

जिला गाजीपुर में वेसों नदी के पुल के पास निर्मित पुलिया पर व्यय

*६५—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला में बिरनो पक्की रोड पर वेसों नदी के पुल के पास ही एक पुलिया बन रही है ? सरकार का कितना रुपया इसमें खर्च होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, इसका अनुमानित व्यय ९,००० रुपये है।

---

† २२ मई, १९५६ को निर्माण उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

गाजीपुर के पीपे के पुल को स्थानान्तर करने पर व्यय

*६६—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के पीपे के पुल को नये स्थान से पुराने स्थान पर लाने के लिये सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—११,००० रुपये।

किन्तु श्रीमन्, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार शायद यह धन कम है। कुछ गलत आंकड़ों के कारण यह धन ११ हजार दिखा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष— तो क्या अब आप सही उत्तर दे रहे हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय तो नहीं दे सकूंगा। बाद में दे दूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि पहले यह पुल जिस जगह बना था उस जगह न बनाकर किसी अन्य जगह बनाया गया। फिर दूसरी जगह से हटा कर उसी जगह बनाया गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो उस पुल का पुराना स्थान था वहां पर उस समय नदी का फाट अधिक था इसलिये उसका दूसरे कम फाट वाले स्थान पर बनाया गया, लेकिन फिर जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिर उसको उसी स्थान पर लगाया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे लगे फलदार वृक्षों से आय

*६७—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले से सन् ५५ ई० में पी० डब्ल्यू० डी० के सड़कों के किनारे के फलदार वृक्षों से कितने रुपये की आमदनी हुई?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे लगे फलदार वृक्षों से सन् १९५५ ई० में २,०८७ रुपये की आमदनी हुई।

जौनपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कच्ची, पक्की सड़कों का निर्माण

*६८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में कितनी कच्ची तथा कितनी पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जौनपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १२ मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। युद्धोत्तरकालीन सड़क निर्माण योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत इस जिले में ८२ मील कच्ची सड़कों का निर्माण सन् १९४६ और अगस्त, १९५२ के बीच में हुआ।

*६९—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सड़कों पर सरकार ने कितना धन व्यय किया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिले में पक्की सड़कों के निर्माण में ७,५६,४७१ रुपये तथा कच्ची सड़कों के निर्माण में ३.०५ लाख रुपये व्यय हुआ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ८२ मील कच्ची सड़कें निर्माण हुई हैं उनको पक्का करने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो क्रम के अनुसार और जब धन उपलब्ध होगा तभी यह कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ८२ मील की सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा बनाई गई है या पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा बनाई गई है यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्माणार्थ ली गई थी और बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गई ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़कें कहां से कहां तक बनाई गईं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस सूची में कई सड़कें हैं माननीय अध्यक्ष यदि आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---मैं सूची पढ़ने की इजाजत नहीं देता आप माननीय सदस्य के पास सूची भेज दें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ८२ मील की सड़कें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कच्ची बनी थीं उनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस प्रकार का प्रश्न कई बार सदन के सामने आ चुका है और बताया जा चुका है कि जिस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो यह देखा गया कि किस जिले में कितनी सड़कों की आवश्यकता है और वहां उनकी कितनी उपयोगिता और लाभ है यह विचार किया गया और उसके बाद ही इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों को शामिल किया गया।

जिला झांसी में कच्ची सड़कों का पक्का किया जाना

*७०---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जिला झांसी में पहली पंचवर्षीय योजना में कितनी कच्ची सड़कें पक्की बनवाईं तथा अगली योजना में कितनी बनवाने वाली है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिला झांसी में पहली पंचवर्षीय योजना में १९ मील ५ फर्लांग कच्ची सड़कें पक्की बनाई गईं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस जिले में ३५ मील कच्ची सड़कों को पक्का करने का विचार है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ३५ मील प्रति वर्ष के औसत से सड़कें बनेंगी या ५ साल में कुल ३५ मील सड़कें बनेंगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---५ साल में कुल ३५ मील कच्ची सड़कें पक्की की जायंगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी जिले के विस्तृत क्षेत्र का विचार करके वहां का माइलेज बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——यह तो धन का प्रश्न है, माननीय सदस्य कहीं से धन दिलायें तो अवश्य विचार किया जायगा।

आजमगढ़ और मऊ नगरपालिका में जल वितरण के हेतु आर्थिक सहायता

*७१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**——क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ और मऊ नगरपालिका में पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिये नगरपालिकाओं को कोई आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हां, तो कितनी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश——आजमगढ़ नगरपालिका को जल वितरण के हेतु ५,१४,००० रुपये का कर्ज देने का निश्चय किया गया है और इस समय तक ३,००,००० रुपया दिया जा चुका है। शेष धन इसी वित्तीय वर्ष में दिया जायेगा। मऊ नगरपालिका को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है। अभी तक नगरपालिका की जल वितरण योजना का आंक (project) नहीं बनाया गया है क्योंकि नगरपालिका ने म्यूनिसिपल मैनुअल के पृष्ठ ३७७ पर छपे नियम ९ (१) के अनुसार आंक बनाने के हेतु मुख्य इंजीनियर की फीस जमा नहीं की है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय——क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगरपालिका में जल वितरण की योजना समाप्त हो चुकी है और क्या उसका उद्घाटन शीघ्र ही मंत्री जी द्वारा होने वाला है?

श्री सैयद अली जहीर——यह ख्याल है कि वह शायद ३१ मार्च तक समाप्त हो जाय, लेकिन अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सब काम खत्म हो गया है या अभी बाकी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय——क्या यह सही है कि इस जल वितरण योजना के लिए बिजली का कनेक्शन नगरपालिका को नहीं मिल रहा है?

श्री सैयद अली जहीर——इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

जिला आजमगढ़ की पंचायती अदालतों द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध अपीलें

*७२—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील की अदालत पंचायतों द्वारा किये गये निर्णयों के विरुद्ध जनवरी, सन् ५३ से जनवरी, सन् ५५ तक परगनाधीशों के यहां अलग-अलग कितनी-कितनी अपीलें दाखिल हुईं ?

श्री कैलाशप्रकाश——परगनाधीशों के यहां अपीलें नहीं दाखिल होती हैं, बल्कि निगरानियां दाखिल होती हैं जिनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६६ पर)

*७३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक परगनाधीश के यहां से कितनी अपीलें बहाल हुईं और कितनी खारिज हुईं ?

श्री कैलाशप्रकाश——खारिज एवं बहाल निगरानियों की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६७ पर)

बलिया जिलान्तर्गत तुर्तीपुर से श्रीनगर तक रक्षार्थ बांध की दागबेल बदलने के विषय पर आवेदन-पत्र

*७४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास बलिया जिले के अन्तर्गत तुर्तीपुर से सिकन्दरपुर के आगे तक बनने वाले बांध के सम्बन्ध में सिकन्दरपुर पश्चिमी के लगभग दो सौ यक्तियों के हस्ताक्षरों से कोई आवेदन-पत्र मानचित्र के साथ बांध का पथ बदलने के लिये मिला है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति--एक प्रार्थना-पत्र तुर्तीपुर स श्रीनगर (सिकन्दरपुर नहीं) तक रक्षार्थ बांध की दागबेल बदलने के विषय में प्राप्त हुआ था। प्रार्थियों के प्रस्तावों पर अच्छी तरह विचार किया गया और विस्तृत जांच-पड़ताल की गई, जांच पड़ताल से ज्ञात हुआ कि बांध की दागबेल जो पहले से निश्चित थी जनता के अधिक हित में है। उसमें किसी प्रकार का हेरफेर करने से रक्षार्थ बांध को खतरा हो सकता है और मंशा के अनुसार रक्षा नहीं मिल सकेगी।

कानपुर में कलेक्टरगंज गुड शेड पर तौलने की मशीन का व्यय

*७५--श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)--कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जो तौलने की मशीन कलेक्टरगंज गुडशेड के फाटक पर लगाई गई है उसका कुल लगाने का व्यय तथा नवम्बर माह की आमदनी क्या है? प्रारम्भ में वहां कितने कर्मचारी मशीन पर काम करते थे और आजकल कितने कर्मचारी मशीन पर हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--मशीन लगाने का कुल व्यय ७,५५५ रु० ६ आने है। मशीन बिगड़ जाने के कारण नवम्बर माह में कोई आमदनी नहीं हुई। प्रारम्भ में उस पर ३ कर्मचारी काम करते थे मगर इस समय संभव है कि दो ही कर्मचारी काम कर रहे हों।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस मशीन के सामने म्युनिसिपल बोर्ड ने अपनी ही जगह पर एक दूसरी मशीन थोड़े से किराये पर लगाने की इजाजत दे दी है और वह लगी हुई है?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनारस के विश्वनाथ मन्दिर हरिजन-प्रवेश कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण जी का जो कामरोको प्रस्ताव था और उसमें उस समय एक कानूनी प्रश्न भी उठाया गया था। उस संबंध में मैंने यह कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री कल नहीं थे तो आज इस पर विचार होगा, लेकिन आज श्री राजनारायण जी नहीं हैं। वे मुझसे प्रार्थना कर गये हैं कि उस पर आज विचार न किया जाय, क्योंकि वे बनारस जा रहे हैं, कल बुधवार को वे आ जायेंगे तो कल इस पर विचार होगा? इसमें कोई मुख्य मंत्री जी को आपत्ति तो नहीं है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--अगर सत्याग्रह करते वक्त वे गिरफ्तार हो गये तो क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—अगर वह गिरफ्तार हो गये होते तो यह खत्म हो गया होता, लेकिन गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है।

शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने जो शाहजहांपुर की बिजली कम्पनी के मजदूरों की हड़ताल के संबंध में कामरोको प्रस्ताव दिया था उसके संबंध में वित्त मंत्री जी ने आज सदन के सामने अपनी मालूमात रखने के लिये कहा था। अतएव उनको जो जानकारी हो वह सदन के सामने रख दें।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक लिखित वक्तव्य पढ़ कर सुना दूं। शाहजहांपुर की बिजली कम्पनी के मजदूरों ने एक हड़ताल का नोटिस १२ मांगें रख कर दिया। इस नोटिस के मिलते ही रिजनल कंसिलियेशन आफिसर बरेली ने दोनों दलों से बातचीत की और समझौता कराने का प्रयत्न किया, परन्तु इस दिशा में विशेष सफलता इसलिये प्राप्त न हो सकी कि मजदूर इस बात पर जिद करते थे कि रेजीडेंट इंजीनियर श्री मखीजा का वहां से तबादला कर दिया जाय, क्योंकि वह मजदूरों को बहुत परेशान करते थे। १२-३-५६ को श्री प्रसाद, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तथा श्री हैकरवाल, रीजनल कंसिलियेशन आफिसर बरेली से शाहजहांपुर गये और मजदूरों के प्रतिनिधियों से तथा श्री पेरी पर्सनल आफिसर (हेडआफिस) से बहुत लम्बी वार्ता की। मजदूरों ने इस बात को माना कि अगर उनके तीन बरखास्त किये हुये साथी फिर से काम पर रख लिये जायं तो वे इस समय हड़ताल पर नहीं जायेंगे। श्री पेरी तथा श्री मखीजा दोनों ने बात को निजी तौर पर मान लिया परन्तु यह कहा कि वे अंतिम उत्तर अपने प्रधान कार्यालय, कलकत्ता से राय लेने के बाद दे सकेंगे। प्रधान कार्यालय ने अपने इन अधिकारियों की सलाह को इस विषय में नहीं माना इस कारण बातचीत खत्म हो गई और मजदूर १४ मार्च को सुबह से हड़ताल पर चले गये। हड़ताल होने के कारण रौजा शुगर फैक्ट्री आंशिक रूप से बन्द हो गयी है क्योंकि इस फैक्ट्री के कुछ भाग इस बिजली कम्पनी द्वारा लगायी गयी शक्ति से चलते थे। अनुमानतः शहर के अन्य छोटे कारखाने जैसे आटा चक्की, तेल मिल इत्यादि जो कि बिजली से चलते थे वह भी बन्द हो गये होंगे। सरकार की ओर से अब भी इस झगड़े को सुलझाने का प्रयत्न हो रहा है और आशा की जाती है कि जल्दी ही यह हड़ताल वापस हो जायगी। इस विषय में प्रधान कार्यालय से आये हुये कुछ अधिकारियों से अभी बातचीत चल रही है और बातें की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—नारायणदत्त जो, जब इस विषय पर कल श्रम अनुदान आने वाला है तो आप किस तरह से यह उचित समझते हैं, इस जानकारी को हासिल करने के बाद भी कि आज ही इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि जो समझौते के प्रयत्न हो रहे थे वह मिल मालिकों के प्रधान कार्यालय से समझौते की शर्त न मानी जाने के कारण, इस हड़ताल की नौबत आयी। अब १४ मार्च से यह हड़ताल चल रही है और इस बीच में जितने भी समझौते के प्रयत्न किये गये असफल रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री ने कहा है कि आंशिक रूप में मिल बन्द हो गयी है। आंशिक रूप में मिल बन्द कैसे हो सकती है? बिजली बन्द होने से पूर्ण रूप से मिल बन्द हो सकती है। आंशिक रूप से बन्द होने का कोई महत्व नहीं रखता। किसानों का हजारों मन गन्ना जो कट रहा होगा या कट गया होगा वह सब नष्ट हो रहा होगा। उस जिले के और आसपास के जिलों से जो गन्ना वहां पर आता है वह आना बन्द हो गया होगा। और वहां पर विशेष प्रकार की परिस्थिति

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उत्पन्न हो गयी है। कामरोको प्रस्ताव अर्जेंट पब्लिक इम्पार्टेंस के लिये होता है। यह अर्जेंट भी है क्योंकि समस्या लगातार चल रही है, और दिन प्रति दिन गम्भीरता पकड़ती जा रही है। पब्लिक इम्पार्टेंस का भी है। इसलिये अगर इसमें एक दिन की भी देर वादविवाद में हो जाय तो इसमें हजारों व्यक्तियों की आमदनी का सवाल है। इसलिये मैं समझता हूं कि कल तक के लिये स्थगित करना उचित नहीं होगा। फिर श्रम अनुदान में बहुत सी बातें कहनी पड़ती हैं केवल इसी बात पर केंद्रित नहीं हो सकते। उसमें हमें दस बातें कहनी पड़ती हैं। इस प्रकार उन पचीसों बातों में मिलजुल कर इस विशेष बात का महत्व समाप्त हो जायगा। केवल इसी विषय पर वाद-विवाद करने की आवश्यकता को देखते हुये मुझे आप इसको पेश करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष——मैं आपको इसे सदन की अनुमति के लिये उपस्थित करने की इजाजत देता हूं। इसको आप क्योंकर महत्व का समझते हैं यह आप कह सकते हैं। बहुत सी बातें स्वीकृत भी हो चुकी हैं जहां तक वाकयात का संबंध है। अब आप सदन की अनुमति के लिये प्रार्थना करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करने के हेतु सदन की अनुमति चाहता हूं।

"यह सदन निम्न कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

विगत १४ मार्च से शाहजहांपुर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजदूरों ने अपनी मांगें मंजूर न होने के कारण पूर्ण हड़ताल कर दी। परिणामस्वरूप——

१——कल से वहां की गन्ना मिल बिलकुल बन्द हो गयी है तथा शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जिलों के हजारों काश्तकारों का गन्ना न पेले जाने के कारण भारी नुकसान हो जाने की संभावना है, तथा

२——शहर के सभी बिजली से चलने वाले छोटे बड़े अन्य उद्योग-धंधे उदाहरणार्थ १०० बिजली से चलने वाली चक्कियां भी बन्द हो गयी हैं, जिससे शहर की खाद्य स्थिति पर असर पड़ रहा है तथा

३——हजारों परीक्षार्थी विद्यार्थियों को जिनके इम्तहान शुरू हो चुके हैं, पठन-पाठन में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है

एवं,

४——अंधकार होने से चोरियों व डकैतियों की तादाद भी वहां एकदम बढ़ गई है।"

श्री अध्यक्ष——आप तो यह कह चुके हैं जो कुछ परिस्थिति है। अब विशेष कहने की बात नहीं है। मैं सदन की राय लिये लेता हूं।

जो लोग अनुमति देने के पक्ष में हों कि इस कामरोको प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाय वे कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल २० सदस्य खड़े हुये। गिनती के बीच में श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि एतराज तो किसी ने कुछ किया नहीं। इस पर वित्त मंत्री, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने कहा कि एतराज तो कल ही कर दिया था।)

श्री अध्यक्ष——अनुमति देने के पक्ष में २० की संख्या है और कम से कम ३६ की संख्या होना चाहिये। जब यह समझा जायगा कि सदन की अनुमति है। इसलिए सदन की अनुमति नहीं है।

विश्वनाथ मन्दिर, बनारस में तीन हरिजनों के प्रवेश की सूचना

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं एक सूचना चाहता था। विश्वनाथ मंदिर के सामने सत्याग्रह के संबंध में समाचार पत्रों में एक खबर छपी है कि वहां पर हरिजन प्रवेश हो गये हैं। तो इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ निश्चित सूचना हो तो वह स्पष्ट हो जाय तो अच्छा है। मुमकिन है कि इसीलिये श्री राजनारायण वहां गये हों।

श्री अध्यक्ष---वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी सत्याग्रह के संबंध में कल सूचना देने वाले हैं। लेकिन अगर आज भी वह कोई सूचना देना चाहें, तो मैं समझता हूं कि यह महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं इजाजत दे दूंगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, एक अखबार में ऐसी खबर छपी थी कि तीन हरिजन सज्जनों का विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रवेश हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि किसी को इस बात की जानकारी नहीं हुई कि वह कौन लोग हैं और इस तरीके पर प्रवेश हो गये। बहरहाल ऐसा हुआ और कुछ पंडितों की तरफ से कल दरख्वास्तें पड़ीं मैजिस्ट्रेट के यहां कि इन लोगों ने कानून को तोड़ा, इंजेक्शन को, इसलिये इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय और मैजिस्ट्रेट ने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया कि महज अखबार में छपा है इसलिये मैं उस पर कोई ऐक्शन नहीं ले सकता। इतनी ही सूचना देनी है।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक पर वाद-विवाद की मांग

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---जनाबवाला, एक दरख्वास्त करना चाहता हूं पेश्तर इसके कि आज का काम शुरू हो। कई रोज से अखबारों में पढ़ा कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन बिल गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यहां भेज दिया है। तो मैं समझता हूं कि सभी यह जानना चाहेंगे कि वह बिल मेज पर कब रखा जायगा और किस तारीख को बहस होगी ताकि उसके हिसाब से मेम्बरान अपने प्रोग्राम बना सकें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अभी हमारे पास बिल नहीं आया। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि कब विचार होगा और होगा भी या नहीं।

१९५६-५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव आयेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, बिजली से संबंधित जितने अनुदान हैं जैसा कि अनुदान संख्या २४, २५ और ४७ यह एक साथ ले लिये जायं और इनके लिये ३ घंटा रखा जाय और अनुदान संख्या ५१ पर एक घंटा रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---यानी ४ बजे तक अनुदान संख्या २४,२५ और ४७ खत्म हो जायं और फिर उसके बाद ५ बजे तक अनुदान संख्या ५१ लिया जाय।

माननीय वित्त मंत्री को स्वीकार है?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)---मंजूर है।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत योजनायों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१-क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

वित्त मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४-विद्युत योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, लेखा शीर्षक-४१ के अन्तर्गत २ करोड़ ४८ लाख ४२ हजार ६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५-विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय, लेखा शीर्षक-४१ और ८१-क के अन्तर्गत १ करोड़ ३५ लाख ४ हजार २०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) (लेखा शीर्षक ८१-क) के अन्तर्गत १३ करोड़ २० लाख ४७ हजार रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन अनुदानों का संबंध है इसमें जो ग्रांट नम्बर २४ है वह उन कार्यों के लिये है जो कार्य इस स्टेट में पहले से चले आते हैं। जो कार्य पहले से चले आते हैं उसमें मेंटिनेंस इत्यादि है और इस अनुदान को हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले में कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें मेंटिनेंस, डेप्रिशियेशन, डाइरेक्शन और मैनेजमेंट इत्यादि के आता है उसके लिये १४,५२७ हजार रुपया रखा गया है। दूसरे इसी के साथ में इसी अनुदान के अन्तर्गत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स के लिये जो कि गंगा ग्रिड्स के नाम से हैं जिसमें पावर जनरेशन सब स्टेशन इत्यादि हैं, उसके लिये ६७ लाख ३० हजार रुपया रखा गया है। तीसरा इसी अनुदान में शारदा हाईडिल स्कीम के लिये भी है जिसमें जनरेशन, सब स्टेशंस और ट्रांसमीशन लाइन्स इत्यादि हैं, इसके लिये भी ५ लाख ६५ हजार रुपया रखा गया है। और चौथे में शाहजहांपुर का पावर हाउस, गोरखपुर का पावर हाउस, आजमगढ़ का पावर हाउस और सोहावल इत्यादि के पावर हाउसेज हैं जिनके लिये ३० लाख २० हजार ६ सौ रुपये रखे गये हैं। ग्रांट नम्बर २५ में १ करोड़ ३५ लाख ४ हजार दो सौ रुपये की मांग की गई है। यह रुपया इस्टैब्लिशमेंट से संबंधित है। इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं छोटे से लेकर बड़े तक उन पर खर्च करने के लिये यह है। उसमें आफिसर्स की तनख्वाह है, ट्रैवलिंग एलाउन्सेज हैं और इस तरह के जितने भी खर्चे हैं वह सब इस ग्रांट नम्बर २५ से संबंधित हैं।

जहां तक ग्रांट नम्बर ४७ का संबंध है जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजना के संबंध में स्कीमें हैं वह सब इसमें सम्मिलित हैं। बहुत सी स्कीमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में थीं जो सन् १९४७ से इसमें सम्मिलित हैं। जहां तक एलेक्ट्रिसिटी विभाग का संबंध है मैं नहीं चाहता कि अधिक समय सदन का लूं लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लेने जा रहे हैं। हमने प्रथम

१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों क लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ११३ २४—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१ और ८१–क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१–क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

पंचवर्षीय योजना में बहुत से कार्य किये हैं, मैं सदन के सम्मुख उन सबको रखूंगा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर हम क्या क्या करना चाहते हैं इन सब बातों को भी मैं सदन के सम्मुख रखूंगा। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी विभाग का संबंध है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है और जहां तक उद्योग धंधों का सवाल है उसमें बिजली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना बिजली के बहुत से कार्य नहीं हो सकते। यदि हमें अपने देश में उद्योग धंधों को बढ़ाना है, यदि हमें अपने ट्यूबवेल्स इत्यादि को इलेक्ट्रिफाई करना है तो उसके लिए यह जो अनुदान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध है हमारे यहां वे बहुत से उद्योग धंधे बिजली की कमी के कारण नहीं पनपने पाये। हमने इस बात की कोशिश की है कि हम टाउन्स को इलेक्ट्रिफाई करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां तक उद्योग धंधों का संबंध है हम उन तमाम बातों के लिये बिजली का प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं।

अब मैं आपके सम्मुख संक्षेप में यह रखना चाहता हूं सन् १९४७ से लेकर के जिस बजट को आज हम यहां पर पास करने जा रहे हैं जो कि सन् ५६–५७ का बजट होगा उसके अन्तर्गत क्या क्या खर्च हुये हैं और उनसे क्या क्या काम हुये हैं और इसके साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम क्या क्या काम करना चाहते हैं, यह सब मैं थोड़े में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मार्च, सन् १९४७ के अन्दर ७ हाइड्रो पावर स्टेशन, ३ थर्मल पावर स्टेशन और ६ डिजेल के पावर स्टेशन थे। इस तरह से मार्च, सन ४७ के अन्त तक कुल १६ पावर हाउसेज थे। मार्च, ५६ के अन्त तक ये हाइड्रो पावर हाउसेज ७ से बढ़कर ११ हो गये, थर्मल तीन से ६ हो गये और डिजेल के पावर हाउसेज ६ से १७ हो गये। इस तरह से जो इनकी संख्या मार्च, सन् ४७ में १६ थी वह अब ३४ के करीब हो गई। यह जो बजट हम आज पास करने जा रहे हैं इस बजट वर्ष के अन्त तक इनकी संख्या ३७ के करीब हो जायगी। जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे, जो बजट आपके सामने रखा हुआ है इसमें बहुत सा रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है। तो हाइड्रो थरमल और डीजिल स्टेशन में हाइड्रो जोकि सन् ४७ में ७ थे वह जाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १५ हो जायेंगे और थरमल स्टेशंस जो तीन थे वह बारह हो जायेंगे और डीजेल के स्टेशंस जो ६ थे वह १८ हो जायेंगे। इस प्रकार सन् ४७ में जो पावर हाउसेज की संख्या १६ थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ४५ हो जायेंगे।

इसके आगे जितनी हमने बिजली पैदा की है, जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी किलोवाट्स में पैदा की है उसका थोड़ा सा ब्योरा मैं बतलाना चाहता हूं। हाइड्रो में सन् ४७ में १९,९०० किलोवाट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी थी, थरमल में २१,५०० और डीजेल में १,८००। कुल मिलाकर ४३,२०० किलोवाट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी थी। मार्च, सन् १९५६ के अन्त तक हम १,४०,३१५ किलोवाट पैदा कर चुके हैं और सन् ५७ तक टोटल १,८५,३१५ किलोवाट तक पहुंचने की आशा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५,५२,३१५ किलोवाट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी हमारी हो जायेगी। इसमें हाइड्रो की ४,०२,६५० किलोवाट और थरमल की १,२७,२२५ किलोवाट और डीजेल की २२,४४० किलोवाट बिजली शामिल है। कुल मिलाकर ५,५२,३१५ किलोवाट होती है जो हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पैदा करना चाहते हैं।

इसी दौरान में जब बिजली पैदा हो गयी तो प्रश्न यह उठता है उसको ले जाने के लिये ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता है। मार्च, १९४७ के अन्त तक हमारे पास ४,८९९ के रूट माइल्स की लाइन्स बनीं और मार्च, १९५६ के अन्त तक ११,२९३ रूट माइल्स की लाइन्स बनीं।

[श्री धर्म सिंह]

मार्च, सन् १९५७ के अन्त तक १२,९४३ मील बनाने का इरादा रखते हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उन सबको मिलाकर १७,१६७ के करीब रूट माइल्स हो जायंगी।

अब आगे मैं आपका ध्यान उन सब स्टेशंस की तरफ ले जाना चाहता हूं जो एक तरफ पावर स्टेशंस बनते हैं और एक तरफ सब-स्टेशन और ट्यूबवेल्स के लगाने के लिये बिजली की आवश्यकता पड़ती है। सन् १९४७ के अन्त तक १,८४७ इलेक्ट्रिफाइड ट्यूबवेल्स थे। सन् ५६ के अन्त तक ५,४९५ हो गये और मार्च, १९५७ के अन्त तक ५,९९५ ट्यूबवेल बनाने का इरादा रखते हैं और वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६,९९५ ट्यूबवेल हमारे पास हो जायेंगे, सबको बिजली देनी है जहां तक सब स्टेशंस का संबंध है सन् ४७ के अन्त तक २,३९० थे और मार्च, सन् ५६ तक ५,२०७ हो गये। मार्च, सन् ५७ के अन्त तक ५,७३७ सब स्टेशंस बनाने का इरादा रखते हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वह ८,२५७ हो जायेंगे।

जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी विभाग का संबंध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या काम किये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम क्या-क्या करना चाहते हैं, उसको मैं आपके सम्मुख रख देना चाहता हूं। गंगा ग्रिड का जहां तक संबंध है, अभी कुछ दिन पूर्व वहां पर पथरी पावर हाउस का माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया था। यों तो गंगा ग्रिड पर ५–६ पावर हाउसेज हैं, लेकिन मुहम्मदपुर हाइडेल पावर स्टेशन की इंस्टाल्ड कैपेसिटी ९,३०० किलोवाट है और पथरी हाइडेल पावर स्टेशन की २०,४०० किलोवाट है। यह दोनों पावर हाउसेज कम्पलीट हो चुके हैं और उनसे बिजली दी जा रही है। हमने पिछले वर्ष कहा था कि जो भी इनसे बिजली लेना चाहते हैं वे बिना किसी कठिनाई के १० हार्स पावर और १५ हार्स पावर तक की बिजली सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रुड़की को प्रार्थना-पत्र देकर प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों पावर स्टेशंस प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले ही लग गये थे और जो हमारा खास मंशा था वह पूरा हो गया है। इस तरीके से हम देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, इटावा और बरेली के कुछ हिस्से को बिजली दे सकने का इरादा रखते हैं।

अब मैं आपके सामने यह रखता हूं कि इस दौरान में आखिर कितने प्रार्थना-पत्र इस ग्रिड एरिया में हुये। हमने कितने लोगों को बिजली दी और कितनों को आगे देने का इरादा रखते हैं। हमको २१,१११ के करीब प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये और १३,८१४ पावर कनेक्शन्स हमने स्वीकृत किये, ४,३०७ के करीब नामंजूर हो गये और ३,००० के करीब पत्र विचाराधीन हैं जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के यहां है। इसके अतिरिक्त लाइट और फैन के नाम से ५०,९१७ प्रार्थनापत्र स्वीकार हो चुके हैं और २२,०३० खारिज कर दिये गये हैं और एक हजार के करीब ऐप्लीकेशंस विचाराधीन हैं। इसके बाद खटीमा हाइडिल पावर स्टेशन से अल्मोड़ा, सीतापुर, हरदोई आदि शहरों को बिना किसी रुकावट के बिजली पूरे तरीके से मिल सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां से कंट्रोल पूरे तरीके से बिजली से उठा लिया गया है।

साथ ही साथ जहां ये पावर स्टेशंस बने वहां मैं हरदुआगंज का भी जिक्र कर देना चाहता हूं। उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि पथरी पावर हाउस और मुहम्मदपुर पावर स्टेशन के बनाने के बाद भी जो पश्चिमी जिलों को कमी थी वह पूरी नहीं हो पायी है। इसलिये इस तरीके से हमने उसको पूरा करने की चेष्टा की है। साथ ही साथ हमने शाहजहांपुर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार पर बिजली बढ़ाने की व्यवस्था की है। उसके साथ-साथ जो रामपुर का आपका पहले से पावर स्टेशन था उसमें एक हजार किलोवाट के करीब बिजली पैदा की है और वहां की इंस्टाल्ड कैपेसिटी ३००० किलोवाट के करीब है। गोरखपुर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्दर ३,०९० किलोवाट बिजली गोरखपुर, बस्ती, देवरिया को देने की व्यवस्था है। सोहावल में भी एक्सटेंशन किया गया है और वहां पर दो ऐडीशनल जेनरेटिंग सेट लगाये गये हैं और वहां ४,५०० किलोवाट के करीब बिजली पैदा होती है।

जहां तक ईस्टर्न एरिया पावर प्रोजेक्ट का संबंध है उसमें मऊ, गोरखपुर और सोहावल के थरमल पावर स्टेशन आते हैं। हालांकि यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखा गया था, लेकिन उसका ५० प्रतिशत काम समाप्त हो चुका और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले या दूसरे साल में यह काम पूरा हो जायगा और हम देखेंगे कि उससे ४५,००० किलोवाट के करीब बिजली हमको मिल सकेगी। इसके साथ साथ पहाड़ी जिलों में भी हमने बहुत से कामों को टेक अप किया। मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अतर्गत आपको बता सकूंगा कि क्या-क्या कार्य किये गये हैं। लेकिन वहां पर एक स्माल हाइडेल स्कीम कम्पलीट हो चुकी है, जोकि बागेश्वर का हाईडल पावर स्टेशन कहलाता है और जिसकी इंस्टाल्सड कैपेसिटी २५ किलोवाट है। उससे बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में बिजली देने की आशा की है।

रिहंड डैम के पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी बहुत से कार्य हुये हैं, मैं डिटेल में तो जाना नहीं चाहता, वह तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बता सकूंगा, लेकिन वहां पर हमको एक चीज मिलती है कि वहां सड़कों का निर्माण किया गया। एक तो ५० मील लम्बी सड़क और एक सोन नदी पर पुल का निर्माण सामान आदि ले जाने के लिये किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने ३६ टाउंस के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये भी कार्य किया। भारत सरकार से उसके लिये पैसा मिला था। इस तरीके से हम देखते हैं कि फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, हरदोई, प्रतापगढ़, बहराइच, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर इन जिलों में ३९ प्रतिशत के करीब काम पूरा हो चुका है और इस तरह से ३६ टाउन्स में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रख दिया गया है और हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी बहुत से टाउन्स को इलेक्ट्रफाई किया है। टनकपुर को हमने इलेक्ट्रफाई किया है। पहाड़ी जिलों में हमारे यहां ट्यूबवेल्स की कमी थी। हम बड़े-बड़े पावर हाउसेज तो नहीं बना सकते थे इसलिये १५,४२५ किलोवाट इंटेरिम डीजेल पावर स्टेशंस फार पार्वरिंग आफ स्टेट ट्यूबवेल्स बनाने की व्यवस्था की गई है। इनमें से देवरिया डीजेल पावर स्टेशन से ६ सौ किलोवाट, मऊ डीजेल से ६०० किलोवाट, मऊ थरमल से १,६०० किलोवाट, सोहावल डीजेल से १,७५० किलोबाट, मैनपुरी डीजेल से ७५० किलोवाट, नीबकरोड़ी डीजेल से २,७५० किलोवाट, गुसाईगंज डीजेल से १,५०० किलोवाट, गोरखपुर थरमल से १३,१२५, बहराइच डीजेल से ७५० और भदोही से २,००० किलोवाट। इस तरह से कुल १५,४२५ किलोवाट बिजली पैदा की गई है। इसके साथ-साथ इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूबवेल्स को हमने इलेक्ट्रफाई किया। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि अन्न की जो समस्या है वह दूर तभी हो सकती है जब अधिक से अधिक पानी हम किसानों को दे सकें और उसके लिये अधिक से अधिक ट्यूबवेल्स तैयार हों। हमने उनको इलेक्ट्रफाई किया। मैं नहीं चाहता कि आपको अधिक डिटेल्स में बतलाऊं लेकिन जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार ५,९९५ के करीब प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रफाई किया है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने पावर स्टेशंस, कितने ट्रांसमिशन्स सब स्टेशंस बने तो मैं हर एक जिले का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शाहजहांपुर में ११ के करीब इस तरीके से सब स्टेशंस बने, खेरी में ४, बरेली में ११, बाराबंकी में १, लखनऊ में १, हरदोई में १०, पीलीभीत में ५, अल्मोड़े जिले में २, नैनीताल में १३ और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में १९। उसके बाद जैसा मैंने आरम्भ में कहा था। हमने बहुत सी स्कीमों को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया था। उनको हम पूरा नहीं कर सके उनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये इस तरीके से रख दिया गया है।

अब आपके सामने हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या काम करने वाले हैं उसको मैं रखना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहां जमुना हाइडेल स्कीम स्टेज वन ऐंड

[श्री धर्मसिंह]

ट्यूब है। इसमें दो स्टेजेज में बिजली पैदा हो सकती है। पहली स्टेज १९६० में होगी जिसमें २३ हजार किलोवाट के करीब बिजली पैदा होगी और दूसरी स्टेज सन् १९६५ में होगी, जिसमें जाकर ६० हजार किलोवाट के करीब बिजली पैदा होगी। तो हमारा सब का सब धन १९५९·३० लाख के करीब खर्च होगा और १९५७ में यह कार्य आरम्भ हो जायगा। इसीलिये जहां तक ५६–५७ के बजट का संबंध है उसमें ५० लाख के करीब रखा गया है। जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध है उसके लिये आगे चलकर मैं आपसे निवेदन करूंगा।

इसके साथ ही हरदुआगंज को जैसा मैंने अभी बताया हमने इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की थी लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम वहां पर एक और नया पावर स्टेशन लगाने का विचार रखते हैं। उसकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी करीब ३० हजार होगी और तीन करोड़ के करीब की वह स्कीम है और इसमें हमने ५६–५७ में तीन लाख के करीब रुपया रखा है पहली अप्रैल, सन् १९५६ से इस स्टेशन को बनाने का कार्य आरम्भ हो जायेगा।

आगे चलकर के गंगा कैनाल ट्रांसमिशन और एक्सटेंशन स्कीम है वह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है। जब हम इटावा, आगरा, बदायूं और मथुरा जिलों की तरफ देखते हैं तो वहां पर बिजली तो अधिक पैदा होती है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर बिजली ले जाने के लिये यह आवश्यक है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स बढ़ें और हमारी ट्रांसमिशन लाइन सहारनपुर जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मेरठ जिले में भी बढ़ रही है। गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर इत्यादि टाउन्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत पीठासीन हुये।)

इसलिये यह आवश्यक समझा गया है कि हम वहां पर १३२ के० बी०, ६६ के० बी०, ३७.५ के० बी० और ११ के० बी० की लाइन बनायें। तो यह भी हमारे सामने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखा गया है। इसमें २०० लाख रुपये तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान में और १०० लाख रुपये थर्ड फाइव ईयर प्लान में मांगे गये हैं। तो सन् १९५६–५७ के बजट में द्वितीय योजना के अन्तर्गत ९९,८०० रुपये व्यय करने की मांग है।

इसके साथ ही साथ बुन्देलखंड में बिजली की बहुत कमी है। वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिये वहां पर एक स्कीम लागू की गयी है जो झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिलों को बिजली देगी और १५ हजार किलोवाट के करीब का वहां पर पावर हाउस बनाने का इरादा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि १९५६–५७ के बजट में २५ लाख रुपये के करीब रखा गया है और १९६० तक वह बन कर तैयार हो जायगा। इससे वहां बहुत पैदावार बढ़ेगी। वहां के टाउन्स और देहातों को भी बिजली दी जायगी।

इसके साथ साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इरीगेशन डिपार्टमेंट १५०० के करीब ट्यूववेल्स बना रहा है। उन सब को इलेक्ट्रिफाई करने का इरादा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने बिजली को तो पैदा कर लिया, लेकिन देहातों में नहीं ले जा सके। इसी के आधार पर हमने प्लानिंग कमीशन को एक योजना भेजी जिसमें उनसे प्रार्थना की गयी कि हम ३१८ टाउन्स और ७,४६३ गांवों को इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमको जितना पैसा मिलना चाहिये था उतना न मिल कर ५ करोड़ के करीब मिला। इस तरह से आप देखेंगे कि २३५ स्थानों को जिनमें से २०० देहाती स्थान होंगे और बाकी शहरों में होंगे हम इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर। उसके बाद रामगंगा प्रोजेक्ट का जहां तक संबंध है, हमने प्रार्थना यह की थी कि उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले लिया जाय लेकिन वह नहीं लिया जा सका और न हमको उतना पैसा

मिल सका लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत शुरुआत वहां करना चाहते हैं और इसके लिये थोड़ा सा रुपया मांगने की व्यवस्था की गयी है।

इसके बाद नयार घाटी के थर्मल स्टेशन का जहां तक संबंध है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है, लेकिन एक हजार रुपये की टोकेन ग्रांट मांगी गयी है।

तो आप देखेंगे कि हमने बहुत बिजली पैदा की और इस बात की कोशिश की कि हम उसको इधर-उधर पहुंचायें लेकिन उसके लिये रुपये की आवश्यकता पड़ती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १९५५ तक हमने बहुत से टाउन्स और विलेजेज को इलेक्ट्रिफाई करने की कोशिश की है। मुरादाबाद में हमने बिजली देने की कोशिश की है जिसमें ७५ गांव हैं। जहां तक "केसा" का संबंध है वहां बहुत बड़ी तादाद में बिजली पैदा होती है। वह कानपुर को बड़ी मेहनत के साथ बिजली देता चला आ रहा है। जितनी बिजली हमारे सारे उत्तर प्रदेश में पैदा होती है उसके आधे से कुछ कम वहां जेनरेट होती है।

तो इन अनुदानों को पेश करते हुये हमारे सामने आज समस्या है कि हम देहातों में बिजली ले जायं और शहरों में भी ले जायं लेकिन रुपये की कमी है। अब मैं सदन का अधिक समय न लेकर माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे अपने सुझाव दें जिन पर विचार किया जाय और बाकी बातें जो हैं वे बाद में बतला दी जायंगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे इन अनुदानों को पास करें।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २४, २५ और ४७ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

बिजली जिसको शक्ति कहते हैं और अंग्रेजी में पावर कहते हैं बिजली, शक्ति तथा पावर इसमें दोनों शक्तियां हैं। एक तो बिजली के कारण उत्पादन होता है जिससे देश की समृद्धि बढ़ती है और दौलत बढ़ती है और दूसरे बिजली में डिस्ट्रक्टिव पावर है, यह दोनों चीजें हैं। आज हम देखते हैं कि बिजली के डर से सदन में भी कुछ कमी आ गई है और दूसरे वयोवृद्ध वित्त मंत्री जी जो बिजली के भी मंत्री हैं, शायद इस दृष्टिकोण से भी बिजली पर क्या कहा जाय, क्या न कहा जाय और मैंने प्रस्ताव किया है कि इसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया जाय। यद्यपि यह विकास का काम है और बढ़ना चाहिये और इसमें विकास होना चाहिये ऐसी लोगों की भावना होगी और है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक रुपये की कटौती कर दी जाय। (एक सदस्य--आप बल्ब फोड़ कर प्रकाश करना चाहते हैं) जी हां, प्रकाश होना चाहिये लेकिन कहीं तो अधिक प्रकाश हो जाता है और कहीं नहीं होता है। एक ओर अंधेरा रहता है और दूसरी ओर उजाला रहता है। दुनिया का यह सिस्टम है कि प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे को फालो करते हैं। कभी प्रकाश है तो अंधेरा जरूर होगा और अंधेरा है तो प्रकाश जरूर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही मैं खड़ा हुआ वित्त मंत्री जी ने गढ़वाल की ओर इशारा किया इसलिये मैंने कहा कि अब अंधेरे से प्रकाश होगा।

अनुदान संख्या २४ दो करोड़ रुपये का है और अनुदान संख्या २५ में १ करोड़ ३५ लाख रुपया स्टाइपेंड्स पर खर्च होगा। इसी प्रकार से रेवेन्यू एकाउन्ट्स से खर्च होगा। अनुदान संख्या ४७ में कैपिटल एकाउण्ट से १३ करोड़ २० लाख रुपया खर्च करने की योजना है। हम देखते हैं कि इस अनुदान में थर्मल पावर और हाइडिल से बिजली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

का उत्पादन है और अनुदान २५ में हम देखते हैं कि स्टाइपेंड्स का सवाल है। पहले मैं स्टाइपेंड्स की बात करूं तो हमें ऐस्टीमेट कमेटी की रिकमेन्डेशन का खयाल आता है और दूसरी ओर देखते हैं तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। इस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स ४ के बजाय ३ होने चाहिये लेकिन इसमें १०,११ और १२ तक की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसमें से मैं अनुमान लगाता हूं कि सदन की इच्छा कुछ और है और सरकार की इच्छा कुछ और है। मैंने कहा कि अंधेरा और उजाला साथ-साथ चलता है। बार-बार वही आता है और दोनों तरफ चलता है।

इसके बाद हम देखते हैं कि मिनिस्टीरियल लेबिल की एक पोस्ट पी० ए० के लिये प्रोवाइड की गई है पिछले साल से बढ़ाई गई है। कर्मचारियों की संख्या के संबंध में सरकार का सिद्धांत है और सरकार ने तय किया है कि जितने हमारे यहां टैम्पोरेरी कर्मचारी होंगे उनको धीरे-धीरे परमानेंट करेंगे। अस्थायी कर्मचारियों की संख्या इस वर्ष भी बढ़ाई जा रही है। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म होती जा रही है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होती जाती है। इसमें हम देखते हैं कि अनुदान संख्या ४७ में जो डेवलपमेंट का रुपया है वह कुछ कम कर दिया गया है और उसको द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। इसलिये शायद इसमें कुछ रुपया रखा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखते हुए माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने उसका जिक्र तो किया। उसमें मैं देखता हूं कि ९१६ राजकीय नलकूपों में बिजली देने की योजना है जिसमें ३५० लाख रुपया खर्च करने का गवर्नमेंट का इरादा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में भी कुछ बिजली सप्लाई करने के लिये अनइम्प्लायमेंट रिलीफ आदि के फंड से खर्च करने का इरादा है और इसके लिये ५ करोड़ रुपया रखा गया है जो सन् १९५६–५७ तक खर्च होगा। इसके बाद बुन्देलखंड में एक पाइलट हाइडेल पावर को भी आपने इसमें रखा है और उस पर आपने करीब १५ हजार किलोवाट बिजली झांसी, हमीरपुर, बांदा आदि जिलों को देने का इरादा जाहिर किया है और उसमें ३७७ लाख रुपया खर्च करने को है जो सन् १९६१ तक खर्च होगा। इसके बाद अभी आपने कहा है कि गंगा ग्रिड में बिजली की कमी है। वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके लिये बिजली की कमी है और उसके लिये भी पथरी और मुहम्मदपुर पावर हाउसेज बना दिये गये हैं, लेकिन फिर भी कमी है और इसलिये उसमें आपका इरादा एक और पावर हाउस बनाने का है और उसमें ३ करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इसी प्रकार से गंगा-जल-विद्युत योजना में आप ट्रांसमिशन लाइन बनायेंगे और जमुना विद्युत योजना भी इसमें शामिल कर ली गई है यद्यपि उसके लिये इसमें रुपया प्रोवाइड नहीं किया गया है, यदि भारत सरकार उसमें रुपया दे। मेरे कहने का मतलब यह है कि डाक पाथर पावर हाउस के लिये भी इसमें लिखा गया है। अगर भारत सरकार उसके लिये रुपय देगी तो यह भी बना दिया जायगा। थोड़ा सा प्राविजन इस बजट में कर दिया गया है।

इसके बाद दो नयी योजनायें जो कर दी गई हैं वह हैं एक तो नयार वेली की और एक बाह स्थित योजना है। वहां मैंने देखा है कि नयार में थर्मल प्लाण्ट लगाने का सरकार का इरादा है यद्यपि रुपया उसमें बहुत नहीं है। मैं इस ओर माननीय वित्त मंत्री का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रतिवर्ष मैं कहता हूं और बहुत सी बातें कही हैं, सन् ४६ से आज तक और मैंने वित्त मंत्री महोदय को पिछले साल उनकी स्पीचेज को कोट भी किया था कि जो बात उन्होंने सन् ४६ में कही थी और इस सिलसिले में पिछले साल बहुत सी झड़पें हुईं जो कि पिछले साल की प्रोसीडिंग्स में वर्णित हैं और मैं समझता हूं कि उसको बार-बार कहना

बहुत सुन्दर न होगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं ऐसा कहूं और वह मेरी धृष्टता न समझी जाय कि यह जो नयार वेली की स्कीम तीन खंड में रखी गई है इसके सम्बन्ध में जो खंड ३ में लिखा गया है वह टिप्पणी पढ़ने लायक है और मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय जो पेज ४ पर दिया है उसको देखें। इसमें लिखा है : "इस राज्य में कोयले तथा ईंधन के दूसरे साधनों की बहुत कमी है। किन्तु यहां की नदियों के बहते हुए पानी से जल विद्युत शक्ति के विकास होने की अधिक सम्भावना है। इसलिये इस जिले में बिजली पैदा करने के लिये पहले ही से नयार विद्युत शक्ति परियोजना नामक एक योजना है।" तो इसमें सरकार ने यह माना है क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रकाश के साथ-साथ अंधेरा भी चलता है। यह उन्होंने माना है कि यहां पर्याप्त पानी है और पानी जो है वह सबसे बड़ी ताकत और शक्ति है। अगर पानी है तो वहां पर जनरल ट्रान्सपोर्ट का कोई प्रबन्ध नहीं है। तो वहां आप थर्मल प्लाण्ट लगा कर भाप के द्वारा कोयले को कंज्यूम करके बिजली पैदा करेंगे। तो इससे मैंने अंदाजा लगाया कि शायद प्रकाश के साथ अंधेरा भी है क्योंकि दूसरी साइट देखने में सरकार असमर्थ है, ऐसी मेरी अपनी कल्पना है। क्योंकि जनरल इलेक्शन बहुत जल्द आ रहा है और उस इलाके के सम्बन्ध में आप माननीय वित्त मंत्री महोदय की पिछले तीन साल की स्पीचेज निकाल कर देखें और जो वहां के हमारे गढ़वाल के प्रतिनिधि हैं अगर उनकी स्पीजेज को देखें, तो आप देखेंगे कि सबने माना है और सरकार ने भी माना है कि वह गरीब इलाका है जैसे बुन्देलखंड के बारे में कहा गया कि वहां का गरीब इलाका है। और उन लोगों के विकास के लिये यह बहुत आवश्यक था कि वहां बिजली होती। यह पिछली दफा मांग की गयी थी जब कि हमारे चीफ मिनिस्टर वहां पर गये थे। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री से भी हर समय कहा गया लेकिन जनरल इलेक्शन चूंकि नजदीक आ रहा है इसलिये यह दिखाने के लिये बजट में इस टोकेन ग्राण्ट को रख दिया गया है कि हम डेवलेपमेंट के काम करना चाहते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आयेगा तो उस समय ऐसा कहा जायगा और हमारे भाई उधर के बैठने वाले अक्सर इस पर बोला करेंगे।

एक सदस्य—पथरी पावर हाउस से वहां पर बिजली दी जा रही है।

श्री गंगाधर मैठाणी—अच्छा है अगर वहां से बिजली मिल जाय। कोटद्वारा, दुगड्डा और लैंसडाउन को बिजली वहां से दी जायगी तो यह उचित है, क्योंकि वहां से नजीबाबाद नजदीक पड़ता है और नजीबाबाद को पथरी पावर हाउस से बिजली दी जाती है। पथरी पावर हाउस से वहां पर बिजली दे दी जाय तो अच्छा है लेकिन जब बजट में उसके लिये काफी रुपया नहीं है और इस बात की सम्भावना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में और कमी होगी तो सिर्फ यह बजट में जो रुपया प्रोवाइड किया गया है उसकी वेल्यू इलेक्शन के लिये है। मैं यह समझता हूं कि गढ़वाल के इलेक्टोरेट इस बात को समझेंगे जो कि नीति सरकार ने अपनाई है।

एक दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में आपने अभी कहा और यहां पर दो पुस्तकें एक प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बटी हैं उसमें और दूसरी जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बटी है उसमें जो आंकड़े दिये हुये हैं उनके आंकड़ों में अन्तर है और यह भी कहा है कि यह उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों में पिछड़ा हुआ है। बंगाल, दिल्ली, बम्बई, मैसूर और ट्रावंकोर कोचीन प्रान्तों से यह पिछड़ा हुआ है लेकिन इतना होने पर भी अगर इन दोनों पुस्तकों को देखा जाय तो उनमें यह लिखा है। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट की किताब

[श्री गंगाधर मैठाणी]

है उसमें लिखा है कि १९५५-५६ तक २ लाख ५८ हजार कि० वा० बिजली पैदा की और जो बिजली वह ६०-६१ तक पैदा करने वाली है वह ४,८८,४०० कि० वा० है। इसके बाद जब हम इस बिजली डिपार्टमेंट की पुस्तक को देखते हैं तो उसमें यह लिखा है कि बिजली जो ६०-६१ तक तैयार होने वाली है वह ५ लाख ५२ हजार ३१५ है। शायद माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको देखा हो। इसके अलावा जो इसमें ट्रान्समिशन लाइन्स के विषय में दिया हुआ है उसमें ५५-५६ तक ११२९३.७ लाइन्स हो चुकी हैं और ६०-६१ तक जो पूरी होने वाली हैं वह १७१६७.७ बतलायी गयी हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की किताब में जो दिया हुआ है वह यह है कि ५५-५६ तक ११२६३.७ तैयार हो चुकी हैं और ६०-६१ तक जो पूरी होने वाली है वह १७१७९.७ दिखायी गयी है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मोटी-मोटी बात पर ही मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इन दोनों किताबों के पढ़ने से मालूम होता है कि इन दोनों में अन्तर है। किसकी गलती है यह मालूम नहीं छपने की भी गलती हो सकती है।

एस्टीमेट्स कमेटी में भी जिक्र किया गया है और इसका आयंगर कमेटी की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि पावर और कैनाल का बड़ा भारी सम्बन्ध है। लेकिन यह डिपार्टमेंट अलग अलग है। लेकिन हमारा सुझाव यह है कि इन दोनों को एक ही मंत्री के हाथ में रहना चाहिये जिससे इसमें कोआर्डिनेशन हो। इसके अलावा आयंगर कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी का यह भी सुझाव था कि यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होना चाहिये जिसके द्वारा इसका डेवलपमेंट ठीक से हो। उसमें आपके जो कैनाल के रेट्स हैं वह इतने बढ़ गये हैं कि जिसका ठिकाना नहीं। इसके साथ ही हम यह भी कहते हैं कि बिजली का काम इतना कम क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ६,३२,००००० जनता में से प्रत्येक को फायदा नहीं पहुंच सकता है। लेकिन देखना यह है कि सरकार की नीति क्या है। वह जो उत्पादन करती है उससे गरीब जनता को लाभ होता है या नहीं। लखनऊ में अभी भी कितनी बिजली है। लेकिन फिर भी सरकार उसको बढ़ाती जा रही है लेकिन दूसरे एरिया में बिजली बिल्कुल नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार को गरीबों को भी बिजली देना चाहिये और उसके रेट्स को कम करना चाहिये। यह जरूर है कि यह काम टेकनीकल है। इंजीनियरों को इसमें तकलीफ होती होगी। कुमायूं के अन्दर ट्रान्समिशन लाइन्स गयी हैं। जब हम उनको पहाड़ों के ऊपर जाते हुए देखते हैं तो मस्तिष्क में यह आता है कि उन लोगों को इसमें काफी कष्ट हुआ होगा। वह लाइन बड़ी सुन्दर लगती हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को यह सोचना होगा कि आखिर यह सब किसके लिये। कुछ आइटम्स पहाड़ों पर बिजली के लिये भी हैं। गवर्नमेंट यह भी कहेगी कि हमने बागेश्वर में एक प्लाण्ट लगवा दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि गढ़वाल के अन्दर जहां श्रीनगर, रुद्र प्रयाग, चमोली, पीपलकोटि, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थान हैं, ये स्थान बहुत लोगों के आने जाने के स्थान हैं, वहां पर पचीसों नदियां हैं। पानी भी वहां पर्याप्त है। तो बजाय आपने छोटी-छोटी स्कीमों के लेने के इलेक्शन के प्रोपेगेंडा वेल्यू के कारण एक स्थान पर बड़ा काम लगवा दिया। न तो वहां कोयला ही सप्लाई होगा और न जिले को उससे कुछ लाभ होगा। ऐसी स्कीमें आपकी तरफ से बनती हैं। हम तो कहते ही रहेंगे यह हमारा कर्तव्य है, अब करना या न करना आपका काम है। यह हम जानते हैं कि यह काम टेकनीकल जरूर है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। शारदा पावर हाउस की दीवार टूट गयी, अब तक बन नहीं पायी है। इसलिये इस काम में दिक्कतें होती हैं। टेकनीकल आदमियों को काम करना पड़ता है। उतनी जल्दी काम हो नहीं सकता जितनी जल्दी यहां पर हम बोल लेते हैं लेकिन सरकार को इतना अवश्य देखना है कि गरीब जनता को उससे लाभ

होना चाहिये। उसने जो रेट बढ़ाया था वह कम होना चाहिये। इतना कहते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं और आशा करता हूं कि इससे गरीब जनता को लाभ होगा और सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय वित्त मंत्री जी ने बिजली की योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

आज के निर्माण से युग में चाहे कृषि की उन्नति का प्रश्न हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे उद्योग-धंधों का हो, आवश्यकता इस बात की है कि हमें अधिक से अधिक बिजली और पावर मिले उसके लिए जो हमारे सूबे का बिजली विभाग है, उसने पिछली पंचवर्षीय योजना में जितना प्रयत्न वह कर सकता था, अपने यहां के सीमित रिसोर्सेज के होते हुए, मैं समझता हूं उतना किया तथा उससे अधिक नहीं हो सकता था। हालांकि आवश्यकता उससे कहीं ज्यादा की थी जो कि हमारा वित्त विभाग और माननीय मन्त्री जी भी मानते हैं। परन्तु जो रिसोर्सेज थे और जो स्थिति थी, उसके अनुसार जितना हो सकता था, मैं समझता हूं, उतना किया गया तथा उससे अधिक की सम्भावना नहीं थी। आगे के लिए भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो बिजली की योजना बनायी गयी है उसके लिए जो डैम्स और पावर हाउसेज हैं वे अपने साधनों की दृष्टि से काफी हैं। प्रदेश में हर कोने में बिजली और उद्योग धंधों के लिए शक्ति देने के लिए सरकार ने काफी प्रयत्न किया और विचार किया है। वह चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे पूर्वी, पच्छिमी या मध्य का हो। जैसा कि अभी माननीय मैठाणी जी ने कहा कि कहीं प्रकाश है और कहीं अन्धेरा है। यह तो है ही, अगर अंधेरा न हो तो प्रकाश की अहमियत ही कौन महसूस करे। अंधेरा होने पर ही तो प्रकाश की आवश्यकता और उसकी अहमियत का अनुभव होता है और जब तक अन्धेरा रहेगा तभी तक तो योजनायें आगे के लिए चलेंगी। जब अंधेरा समाप्त हो जायगा और पूर्ण प्रकाश हो जायगा तब तो प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसे ही उधर के बैठने वालों की समझ में इधर के काम नहीं आयेंगे तभी उधर जो प्रकाश की कमी है, वह जनता के सामने आयेगी। मैठाणी जी ने विभाग के कुछ कर्मचारियों को अस्थायी से स्थायी करने की बात भी कही और पी० ए० के स्तर के एक नये इन्जीनियर की बात कही। मैं भी समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है और पी० ए० के स्तर के आफिसर की जरूरत है। जहां तक मैंने बिजली के विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों और उनके कामों को देखा है, मैं समझता हूं वह बहुत मेहनत के साथ और यह न समझते हुए कि वह खाली एक आफिसर ही हैं बल्कि देश के निर्माण में अपने कर्त्तव्य को समक्ष रखते हुए काम करते हैं। सब के बारे में तो मैं नहीं जानता लेकिन अधिकांश जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वह ईमानदारी से अपने फरायज को पूरा करते हैं और इससे जनता का लाभ होता है।

अब मैं कुछ रामपुर के बारे में भी कहना चाहता हूं। रामपुर की तरफ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा, क्योंकि वह रामपुर से काफी वाकिफ हैं और मुझे यह कहने का फख्र है कि उन्होंने अपनी शुरू की तालीम रामपुर में ही हासिल की और वहीं से हाई स्कूल पास किया और वह इससे भी वाकिफ हैं कि रामपुर के लोगों की इक्तसादी हालत पर रियासत के जमाने में और मर्जर के बाद क्या असर पड़ा है। वह जानते होंगे कि इधर वहां पर बेकारी बढ़ी है और वहां की इन्डस्ट्रीज में भी पहले से कमी हुई है, यद्यपि प्लानिंग बजट के अवसर पर बताया गया है कि वहां के लिए दोबारा इन्डस्ट्रीज बढ़ाने की कोशिश सरकार ने की है। मर्जर के बाद वहां के लगभग दस हजार आदमी बेकार हो गये हैं, इस कारण केवल इतने से वहां की बेरोजगारी हल नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि वहां पर काटेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने

[श्री कृष्णशरण आर्य]

के लिए बिजली अधिक से अधिक सहूलियत के साथ दी जाय, जिससे बेकार लोग उन कामों में लगकर अपनी रोजी कमा सकें। वहां जो बिजलीघर पहले से था उसको सरकार ने बढ़ाया है और लोगों को उससे काफी सुविधा भी मिली है, शहरी इलाके में इन्डस्ट्रीज के लिए विजली देने की तरफ मन्त्री जी को खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा देहाती इलाके में जो बिजली देने की बात है और जो २०० गांवों की बात है उसमें से मैं समझता हूं कि कुछ इस साल में भी लिये जायेंगे। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह रामपुर जिले के शाह बाद और मिलक कस्बों में शीघ्र बिजली देने की कृपा करें क्योंकि शाहबाद का वह इलाका है कि जो कम्यूनिकेशन्स की दिक्कत की वजह से हर तरह के विकास के काम में पीछे रहता है और वहां टयूबवेलों के लिए बिजली बदायूं से लायी गयी है, इसलिए अगर इस कस्बे को इलेक्ट्रिफाई करने का प्रबन्ध किया जाय तो वहां पर हर प्रकार के गृह उद्योग और घरेलू धंधे चलाये जा सकते हैं और वहां मकान और सड़कों के लिए रोशनी भी मिल सकेगी। इसलिए मुझे आशा है कि इन कस्बों में मन्त्री जी बिजली देने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का जो बजट इस सदन में पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़े पैमाने पर इस उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली के लिये बहुत बड़ा बजट रक्खा है और इस मुल्क में बहुत से शहरों में बिजली पैदा की गई है और उससे लोगों को फायदा हुआ है। कितनी ही मिलों के अन्दर बिजली दी गई है। मैं उन लोगों की खुशनसीबी पर उनको बधाई देता हूं और जो प्रयास सरकार ने इस बिजली को पैदा करने में किया है उसके लिये मैं सरकार को धन्यावाद देता हूं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक बार फिर गढ़वाल जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। इसी सदन में दो साल पहले मैंने मंत्री महोदय से दरख्वास्त की थी क्या कारण है कि गढ़वाल जिला उनकी नजरों से अछूता रहता है। हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि मनुष्यों के अछूतपन को दूर करने के लिये उन्होंने कांस्टीट्यूशन के अन्दर एक धारा बनाई और सारे मुल्क के अन्दर एक प्रोपेगेंडा किया लेकिन यह सौभाग्य है हमारे गढ़वाल जिले का कि मंत्री महोदय ने उस जिले को अछूता बना कर छोड़ा है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय क्या दलील देंगे या दूसरे भाई जो आंकड़ों में माहिर हैं मुमकिन है कि वह अपने आंकड़ों से गढ़वाल में बिजली चमका दें। परन्तु मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि किसी भी मुल्क ने आंकड़ों को नहीं उठाया है। सरकारी स्ट्रक्ट विजिलेंस और पबलिक एक्सचेकर का सदुपयोग ही है जो किसी मुल्क को उठा सकता है। किसी मुल्क के बड़े आदमी मुल्क को ऊंचा नहीं उठा सकते। मैं स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि मैं गढ़वाल जिले का सौदा पटाने के लिये इस एसेम्बली भवन में दाखिल नहीं हुआ हूं। बराबर पिछड़ जाने से हर जिला या हर मुल्क पिछड़ जाता है क्योंकि प्रगति जो मुल्क की है वह आगे बढ़ती रहेगी और लोगों को और लक्जरीज की जरूरत पड़ेगी, जबकि हमारी नेसेसिटीज जैसी की तैसी बनी रहेंगी। शहरों की जो मुस्कराहट दिखाई देती है उसे अपने मुल्क की इस गरीबी पर आंसू बहाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि वह शोभा नहीं देता, वह किसी भी आदमी के लिए सम्मान की वस्तु नहीं हो सकती। मैं माननीय मंत्री जी से निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर मैं गढ़वाल में बिजली की बात कहूंगा तो वह कह देंगे कि थरमल स्टेशन वहां रख दिया गया है। मैं आपसे कहूंगा कि कानपुर की बिजली को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काट दिया जाय, लखनऊ की बिजली को काट दिया जाय । तब आप महसूस करेंगे कि बिजली क्या चीज है । आप मुल्क के हाकिम जो बनाये गये हैं वह इसलिये कि आप मुल्क के अन्दर इंसाफ करेंगे लेकिन जब आप इंसाफ नहीं करते तो मैं आपके खिलाफ एक चार्ज लगाता हूं । आपको मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये, लोगों को अधिक सुविधायें देने के लिये मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन ऐसा न करके आपने बहुत से जिलों को पिछाड़ दिया और मैं डिक्लेयर करता हूं कि मुल्क के पीछे रहने में आपका बड़ा हाथ रहा है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं । पथरी से ८० से लेकर १५० मील तक बिजली जा सकती है, लेकिन नजीबाबाद से लेकर कोटद्वारा तक बिजली ले जाने के लिये आपने बजट में कोई पैसा नहीं रक्खा है । क्या मैं आपके इन तर्कों को मान सकता हूं । हर्गिज नहीं जिसके चेहरे का रंग काला हो उसे सफेद बनाया जा सकता है इसमें मुझे कतई सन्देह है। इस १९५६ के जमाने में क्या आपको शोभा देता है कि आपने गढ़वाल को अछूता छोड़ दिया है । मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कांग्रेचुलेट नहीं कर सकता जो सर्विसेज उन्होंने की हैं। मैं इस गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जहां उन्होंने कहा कि बिजली पैदा नहीं हो सकती है आप हमें इजाजत दीजिये । हम प्राइवेट कम्पनी के जरिये बिजली पैदा करके बता सकते हैं कि वहां बिजली पैदा हो सकती है। मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रकार का बर्ताव लोगों के साथ नहीं करना चाहिए । क्या आप लोगों को उभारते नहीं कि वह लोग अपनी भावनाओं को इस सदन में जाहिर करें और आप जबदस्ती करते हैं । आप एक इस प्रकार की व्यवस्था पैदा करते हैं कि मुल्क के अन्दर धीरे-धीरे भावनाएं पैदा होती हैं जिससे मुल्क की सद्बुद्धि पर हमें अविश्वास होता है। मैं आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये बातें पं० जवाहरलाल नेहरू के ध्यान में लाना चाहिये वह हमारे राष्ट्र के अगुवा हैं । उनके कंधों पर इस मुल्क के विकास का भार है इस प्रकार से अगर लोग पिछाड़े जायेंगे जानबूझ कर तो किस तरह से हमारे मुल्क की राष्ट्रीयता की बात सफलता से आगे बढ़ सकती है। मुझे महान खेद है कि जहां गांधी जी का यह फोटो टंगा हो और हम अपने को गांधीवादी कहते हैं हमने मुल्क के अन्दर विकास का नारा लगाया । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने कोटद्वारा में जनता को यह आश्वासन दिया था कि डेढ़ साल के अन्दर कोटद्वारा में पीने के पानी की व्यवस्था हो जायगी । आज ६ठां वर्ष दाखिल है । मैंने माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना की कि जनता के सामने लम्बे चौड़े वादे नहीं होने चाहिए। हम लोगों के जनता में जाते ही कान खींचे जाते हैं । हमारे मुंह पर लोग थूकने के लिये तैयार हो जाते हैं कि सरकार ने इसका वादा किया था ।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के ऊपर अभी अभी एक आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने देश को पीछे हटाया है। यह एक व्यक्तिगत भाव हो सकता है। बहुत सारे इस बात से सहमत नहीं होंगे । मेरा व्यक्तिगत खयाल यह है कि यह जो आक्षेप उनके ऊपर है यह गलत है। मंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किया है देश की उन्नति के लिये उसको उठाने के लिये । गलतियां हर एक से होती हैं और मंत्री जी भी उससे अलग नहीं हैं । इसलिये अगर किसी विभाग में कमियां है तो उसमें मंत्री जी

[श्री नौरंगलाल]

का उतना दोष नहीं हैं जितना कि सिस्टम का । इस तरह से डिक्लेरेशन दे देना कि मंत्री जी ने सब कुछ किया हैं उससे देश में धक्का लगा है मैं समझता हूं कि यह जरा इनडिस्क्रीट सा मालूम पड़ता है । इसके लिए मंत्री जी दोषी नहीं ठहराये जा सकते । हमको इतना हेस्टी नहीं होना चाहिये ।

अब मैं बिजली के सम्बन्ध में चूंकि समय थोड़ा है तीन चार सुझाव आपके जरिये से रखना चाहता हूं। पहला सुझाव यह हैं कि इस बिजली के सम्बन्ध में जो रेट्स हैं वह अलग अलग और मुख्तलिफ हैं। लखनऊ में और, बरेली में और, बदायूं में और, रूरल एरियाज में और हैं और अरबन में और हैं कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हैं । मैं समझता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाय कि सारे प्रदेश में यूनीफार्म रेट्स हो जायं। और वह रेट्स जो प्रोडक्शन है उसके साथ कुछ न कुछ मिलते जुलते हों। इस तरह से चीप बिजली मिल सकेगी इसमें एक दिक्कत यह पैदा होगी कि मंत्री जी कह सकेंगे कि यूनीफार्म रेट्स हम इसलिये नहीं कर सकते कि क्योंकि इसके प्राइवेट कंसर्न्स जो हैं वह हमारे बस में नहीं हैं। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सजेशन यह है कि जितनी जल्दी हो सके और अगर हम कर सकते हैं तो कम से कम बिजली की पावर को यू० पी० में नेशनलाइज कर लेना चाहिए और बिजली के बारे में भी जितनी शिकायतें हैं उनका कारण यही है कि प्राइवेट कन्सर्न्स के हाथ में इसका काम है। हमको प्राइवेट कन्सर्न्स के हाथ में नहीं देना चाहिये इससे रोज-रोज के मिल मालिकों के झगड़े तय हो जायंगे और साथ ही साथ हमारा प्राफिट हमारे पास ही रहेगा । इस तरीके से हम यूनीफार्म रेट्स कर सकेंगे । जब प्राफिट की परवाह नहीं होगी बल्कि सर्विस की परवाह होगी तो यूनीफार्म रेट्स सारे प्राविन्स में लग सकेंगे।

इसके साथ ही साथ एक सजेशन और है बिजली का इंडस्ट्री से बड़ा भारी सम्बन्ध है। एक कनफ्यूजन देश के अन्दर पैदा हो गया है एक तरफ कहते हैं काटेज इंडस्ट्री बढ़ाई जाय देहात के अन्दर तेल के दिये जलाये जायं और एक तरफ कहते हैं कि सब जगह इलेक्ट्रीफिकेशन हो तो जरा इन दोनों में विरोधाभास प्रतीत होता है। इसको साफ होना चाहिये । दोनों चीजों को डेवलप करें काटेज इंडस्ट्री को और बिजली को । लेकिन यह तभी हो सकता है जब इंडस्ट्री और बिजली दोनों एक ही मिनिस्टर के पास रहें । इस वक्त इंडस्ट्री दूसरे मिनिस्टर के पास है और बिजली दूसरे के पास । इस तरह से कोआर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत पड़ती है । अगर आपको कोआर्डिनेशन चाहिये तो तभी हो सकता है जब दोनों का नियन्त्रण एक मिनिस्टर के पास रहे । इसके साथ साथ यह भी है कि जो ट्यूबवैल्स हैं वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के मातहत हैं । मेरा पर्सनल खयाल है कि ट्यूबवैल्स को भी बिजली के साथ रहना चाहिये जिससे उनका नियन्त्रण ठीक तरीके से हो सके । मेरा सजेशन है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ट्यूबवैल्स, इंडस्ट्री और बिजली यह तीनों एक ही मिनिस्टर के हाथ में रहें जिससे कि कमाबाइण्ड कण्ट्रोल हो सके ।

मेरा तीसरा सजेशन यह है कि अगर हम प्राइवेट कन्सर्नस को एबालिश नहीं कर सकते किसी वजह से तो इतना तो कर सकते हैं कि हर प्राइवेट कन्सर्न को कम्पेल किया जाय कि पब्लिक की एक ऐडवाइजरी कमेटी रहे जिससे हर बात में सलाह मश्विरा लिया म जाय कि कहां कहां क्या होना चाहिये कहां कनेक्शन लगाया जाना चाहिये और भी इसी किस्म की तमाम बातों के लिये इस बात की जरूरत है कि इन सब बातों पर भी परामर्श ले सके और उसको मानते हुए काम करें ।

इससे काफी सहूलियत पब्लिक को हो जायगी। इस वक्त प्राइवेट कन्सर्न्स वाले मनमानी करते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई इशारा हो सकता है कि इस तरह ऐडवाइजरी कमेटीज बना दी जायं तो उससे पब्लिक को काफी सहूलियत मिल जायगी और बहुत कुछ भार जो पड़ रहा है प्राइवेट कन्सर्न्स पर वह कुछ न कुछ हल्का हो सकेगा।

चौथा सजेश्चन मेरा यह है कि मंत्री महोदय ने अभी जिक्र किया कि हमारी प्रगति उतनी तीव्र नहीं रही बिजली के मामले में प्लान के अन्दर जितनी रहनी चाहिये थी। वजह क्या है हमको सोचना चाहिये। जहां तक मेरा खयाल है हम जो मशीनरी मंगाना चाहते हैं वह अमेरिका से मंगाना चाहते हैं और उतनी वहां से हमारे पास नहीं आ रही है। इस वजह से बिजली के डेवलपमेंट में देर हो रही है। मेरे खयाल से हमको अमेरिका के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अगर अमेरिका हमको मशीन देने को तैयार नहीं है तो हमको और मुल्कों से बातचीत करनी चाहिये जो हमको बिजली की मशीनरी सप्लाई कर सकते हैं। मेरे खयाल से रशिया हमारे साथ में है और उससे इस सिलसिले में बात कर सकते हैं और वहां से हमको लेना चाहिये। तो हमें सोचना है क्योंकि हमें अपनी प्लानिंग तेजी के साथ ले जानी है और प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती जब तक बिजली की तरक्की अपने प्राविन्स में नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा सजेशन है कि जितनी जल्दी हो सके पावर प्लाण्ट्स को डेवलप करने के लिये मशीनरी की आवश्यकता है तो किसी मुल्क से काण्टेक्ट करके हम मंगा सकते हैं और इसके साथ आखीरी शब्द उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जहां तक बिजली का ताल्लुक है यह हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो जिन्दगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है। सारे इन्तजाम के लिये और हमारी सारी भारी इंडस्ट्रीज के लिये यह एक तरह से जिन्दगी है। जैसा कि ट्राटस्की ने जो कि रूस का एक बहुत बड़ा पालिटिशियन हो गया है उसने कहा था कि नोट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और सोशलाइजेशन का वह विर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे देश को इलेक्ट्रिफाइ होना चाहिये और उन्होंने रूस को इलेक्ट्रिफाइड किया और वह जो एक ऐग्रीकल्चरल कंट्री था उसको इंडस्ट्रिअल कंट्री बनाकर दिखा दिया। तो जब वह ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जो दूसरे देशों ने किया वह हम भी कर सकते हैं। हम उनसे अक्ल में कम नहीं हैं हम उनसे शक्ति में कम नहीं हैं, हम उनसे मैन पावर में कम नहीं हैं। हम भी उस चीज को अपने देश में ला सकते हैं और कामयाबी के साथ ला सकते हैं। उसके लिये हमें थोड़ा प्रोपेगंडा भी करना चाहिए जिससे कि हमारे देहात और शहर के लोग इलेक्ट्रिक माइंडेड बन सकें। अगर उनको इलेक्ट्रिक माइंडेड नहीं बनाते हैं तो नतीजा यह होगा कि बिजली वह लेंगे नहीं और वह बिजली बेकार पड़ी रहेगी। तो किसी स्कीम को चलाने के लिये पहले लोगों के माइंड को बदलना चाहिये। जब तक हमारा प्राविंस इलेक्ट्रिक माइंडेड नहीं होता तब तक हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा सजेशन यह है कि हमें पहले अपने प्राविंस में इसका प्रोपेगंडा करना चाहिये और दूसरे यह कि उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए और तब हमें इसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सजेशन मैंने दिये हैं वह कबूल किये जायेंगे।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्युत के व्यय का अनुदान हमारे इस सदन में उपस्थित है। विद्युत की हमारे प्रान्त में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। जहां तक हम देखते हैं सन् १९४७ से लेकर सन् १९५६ तक उसमें जहां पहले ४३ हजार किलोवाट बिजली थी वह आज १,४०,००० किलोवाट है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५,५२ हजार किलोवाट हो जायगी। इसी तरह से जहां सन् १९४७ में १६ पावर स्टेशन्स थे, आज ३४ हैं और आगे चलकर ४५ हो जायंगे। इसी तरह से ट्रांस्मिशन लाइन्स जहां पहले ४,८९९ थीं वह अब ११,२९३ हो गयीं और अगली पंचवर्षीय योजना में १७,१६७ हो जायंगी। इतनी उन्नति और इतना विकास इस बिजली का हमारे प्रान्त में हुआ है। इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इस सम्बन्ध में जहां हम आंकड़ों को देखते हैं तो काफी उन्नति हुई है। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो स्कीमें शेष रह गयी हैं और अगले पंचवर्ष की हैं उनमें १६१ करोड़ का खर्च था। अब इस पंचवर्षीय योजना में हम ७७ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं--२७ करोड़ नयी योजनाओं पर और ५० करोड़ पुरानी पर। ये जितने खर्च हमने और अनुदानों में किये हैं उनको देखते हुए यह हमारा काफी अच्छा खर्चा है और काफी उन्नति हो रही है। जब हम देखते हैं कि इसमें बहुत बड़ी स्कीमें गंगा की ट्रांस्मिशन लाइन, शारदा की ट्रांस्मिशन लाइन, रिहंड डैम और रामगंगा का भी काम शुरू हो जायगा और बहुत से पावर स्टेशन्स का काम भी शुरू हो रहा है इतने बड़े काम हमारे प्रान्त में हो रहे हैं तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि माननीय रावत जी ने बिना समझे हुए इस तरह से कड़ी आलोचना कर डाली। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कोटद्वारा में अभी बिजली पथरी स्टेशन से उनके यहां जाने वाली है। शायद उनको यह मालूम होता तो वह इतनी कड़ी आलोचना इस विभाग की न करते।

मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव दे देना चाहता हूं। हम यह देखते हैं कि बिजली हमारे प्रान्त में जगह जगह मुख्तलिफ रेट पर मिलती है। यहां पर लखनऊ, कानपुर आदि में ४ आने है और देहली में जो हमारे पास ही है वहां ४ आने से भी कम है। मगर हमारे जिले में जहां मार्टिन है वहां पर ९ आने रेट है और ८ आने रेट वह ले रही है। सरकार यह कहती है कि हमारा उनसे कंट्रेक्ट है हम उसमें दखल नहीं देते मगर मैं समझता हूं कि सरकार उनको कर्जे पर रुपया देती है। गत वर्ष भी उनको ३२ लाख का एक कर्जा दिया है। तो ऐसी सूरत में अगर गवर्नमेंट यह कहे तो उनको अपने रेट कम करने होंगे। पहले वह यह कहते थे कि हमारे यहां औसतन खर्चा ज्यादा पड़ता है। चूंकि हमारे यहां कनेक्शन्स कम हैं इसलिये रेट ज्यादा है। मगर जबकि इतने अधिक कनेक्शन लग रहे हैं और गंगा हाइडेल से बिजली बहुत बड़ी मात्रा में रही है तो औसत खर्चा भी कम होने लगा है। इस दशा में यह बिलकुल आवश्यक है कि वहां का रेट कम होना चाहिये। यह एक अनुचित बात है कि एक प्रान्त कुछ हिस्से में ४ आने रेट हो और दूसरे में ९ आने हो। इतना बड़ा फ़र्क होना ठीक नहीं जंचता है। अगर यहां पर कम खर्चे में काम हो सकता है तो वहां पर और भी कम में हो जाना चाहिये। वह अपने खर्चे को इस तरह से मैनुवर करते हैं जिससे कि उसको ज्यादा दिखा दें। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि उनका रेट कम नहीं हो सकता है। उन्होंने जानबूझ कर इतना खर्चा बढ़ा रखा है इसके अलावा उनको और भी बहुत सी शिकायतें हैं कि कनेक्शन लेते वक्त भी बहुत बड़ा चार्ज लेते हैं और बहुत कम परवाह करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह उनको इस बात के लिये विवश करें कि वह अपने रेट को कम करें। जहां तक

मुझे ख्याल है गत वर्ष में उन्होंने इसके लिये कुछ सदन में कहा था कि हम एक कमेटी बैठायेंगे या इस सम्बन्ध में करेंगे। बहरहाल मैं यह समझता हूं कि यह उचित है कि उनको अपना रेट कम कर देना चाहिये। हम यह भी देखते हैं कि मुरादाबाद में आज भी ६ आना रेट है जब कि वे हमारे जिले में आठ आना चार्ज कर रहे हैं। दो वर्ष पूर्व हमारे जिले में भी यही ६ आने का रेट था लेकिन उन्होंने बढ़ा लिया था। अब कनेक्शंस काफी हो गये हैं। मेरे ख्याल में यह उचित है कि वे कमी कर लें। यह अर्ज मैंने किया। इन सुझावों के साथ मैं इस सदन में जो अनुदान उपस्थित हुये हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इन अनुदानों पर कटौती का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बिजली के मुहकमें की बातचीत है। १ लाख किलोवाट जो बिजली थी वह १ लाख ८३ हजार किलोवाट हो गयी है लेकिन बिजली की शरह में कोई फर्क नहीं आया और बराबर बढ़ती ही जा रही है। यहां तक कि कंम्पनियों को जो बिजली दी जाती है वे भी अपने दाम दूने बढ़ाते चले जा रहे हैं। बदायूं शहर की एक मिसाल है जहां ६ आने से ८ आने यूनिट कीमत हुई। यह इतनी गिरां है कि लोगों का काम करना मुश्किल है। कारखानेदारों को भी गिरां बिजली मिल रही है। अगर बिजली बढ़ती है तो उनके भाव में कमी होनी चाहिये। हमें गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देना है तो वह बिजली के द्वारा हो सकता है और उससे असली फायदा तभी हो सकता है जब हम उसके भावों में कमी करें और अगर भाव बढ़ते चले गये और बिजली बढ़ाते चले गये तो उस बढ़ी हुई बिजली से कोई भारी लाभ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको की हाथ में लेती है तो चीजों को सस्ती से सस्ती दें, जनता का हित हो, मजदूरों को सहूलियतें मिलें और सब को ज्यादा उद्योग-धंधे मिलें। यह काम तभी हो सकता है जब कि आप उनको सस्ते तरीके पर बिजली देंगे। मेरे भाई ने बतलाया था कि हमने २३ सौ दरख्वास्तें मंजूर कीं और उनको बिजली दी। बिजली तो दी लेकिन उसके साथ शर्तें रखी गयीं कि इतने रुपये जमा करो तब बिजली मिलेगी। अब उसके पास पैसा नहीं है, तो आपका बिजली देना न देना बेकार हो गया। हजारों दरख्वास्तें आपने मंजूर की हैं लेकिन उन पर अमल इसलिये नहीं हो रहा है। मेरे जिले में बहुत सी दरख्वास्तें आयीं उनमें से एक दरख्वास्त देहन्दा मैं भी हूं, लेकिन सात सौ रुपया मुझसे तलब किया गया है। मैं उस रुपये को न दे सका और बिजली न ले सका। तो जब आप दरख्वास्तें मंजूर करें तो उन लोगों को बिजली पहुंचाने में सहूलियत दी जाय। जब हमारा रुपया दिल खोल कर लिया जा रहा है और उसको बिजली बढ़ाने में खर्च करते हैं तो इस दिक्कत को भी हटा दिया जाय। जो चक्की खोलें उनके जिम्मे डाला गया है कि १ हजार रुपया जमा करो या कुयें के लिये इतना जमा करो, इतना जमा करो तो इस काम के लिये बिजली देंगे। तो इस रुकावट को हटा देना चाहिये। इसकी वजह से जो रुपया जमा करने की शर्त है वह शर्त पूरी न होने की वजह से काम वगैरह बिजली का बढ़ नहीं रहा है।

तीसरी बात यह है कि हमारे जिले में जो बिजली के कुयें बन रहे हैं वहां जहां कुयें बनाने की जगह तय हुई, उसके तय होने के बाद फिर किसानों से कहा जाता है कि तुम्हारे यहां कुयें बनायेंगे, कुछ चन्दा करो और जब तक कि दो सौ रुपया उनका चढ़ावा नहीं है तब तक कूयें नहीं बनते। कुआं एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया। जहां कुओं की तजवीज की जाती है, लालच की वजह से कुंआ हटकर दूसरी जगह चला जाता है। बदायूं से दातागंज बिजली गयी। पांच कुयें रास्ते में बनाये गये। जगह की पैमाइश हुई और उसके बाद कुओं की जगह हटायी गयी और बदली जा रही है आर बदली जाती है। तो

[श्री टीकाराम]

ये चीजें दरमियान में आती हैं और इन बुराइयों की वजह से आदमियों का उत्साह उधर से हटता चला जा रहा है। कुंआ नम्बर ३९ मेरे गांव में मौजूद है। कुएं की गूलें बढ़ रही हैं मेरे पास चिट्ठी आयी है कि पानी बहुत कम है और भराई बहुत गिरां हो रही है। मैं इंजीनियर साहब से मिला और कहा कि इस कुएं को सफ़ाई और बोरिंग दोबारा करा दी जाय ताकि आबपाशी बढ़ जाय। उन्होंने कहा कि करायेंगे तो, मगर जब मौक़ा मिलेगा। साफ़ इन्कार तो नहीं किया, लेकिन कुएं की बोरिंग नहीं हुई। तो जो कुएं पहले के हैं, जिसमें पानी घट रहा है उनकी सफाई और बोरिंग करायी जाय, ताकि पानी बढ़ जाय और लागत ज्यादा न बढ़े और नए कुएं तो आप बना ही रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि आप इंजीनियरिंग महकमे को कहें कि जिन कुओं में पानी नहीं है उनकी सबकी सफ़ाई करा दी जाय ताकि पानी की मेकदार बढ़ जाय और किसान को पानी अच्छी तरह से और कम दर पर मिलें। सरकार जिन योजनाओं को लेकर चल रही है उसमें तरक्की तभी होगी जब आदमी को उससे लाभ होगा। अगर लाभ नहीं होगा तो वह मुर्दा दिल हो जाता है। तो मेरे चार सुझाव हैं। पहला कुओं की सफ़ाई, दूसरा कुओं का हटाया जाना, तीसरा बिजली सस्ते दामों पर दी जाय और चौथा यह कि जो दरख्वास्तें मंजूर की जायं उनको भी बिजली के साधन मोहय्या किये जायं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विद्युत विभाग पर प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी वित्त मंत्री जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमारे प्रदेश ने प्रगति की है उस पर और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा प्लान है उस पर, एक विस्तृत भाषण दिया जिससे यह आशा है कि हमारा यह प्रदेश आगे कुछ तरक्की करेगा। अभी भाई नौरंगलाल जी कह रहे थे कि बिजली के सम्बन्ध में हमारे प्रचार की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आप शहर और गांव और प्रदेश के किसी कोने में भी जायं, सब जगह बिजली की मांग है परन्तु जिस कदर बिजली की आवश्यकता आज लोग महसूस करते हैं उतनी सरकार, चाहे कोई भी कारण हो, दे नहीं पाती है।

इस थोड़े से समय में मैं अपने क्षेत्र की चर्चा कर देना मुनासिब समझता हूं। चार साल हुये तब से बराबर मैं इस सदन में भी और माननीय वित्त मन्त्री जी को समय समय पर लिखित रूप से भी देता रहा हूं और उन्होंने पिछले साल तो मुझे बुला कर विशेष रूप से कुछ स्थान नोट भी किये, परन्तु मुझे आज यह कहते हुये दुःख होता है कि कई दफा उन स्थानों को नोट करने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र में आज तक बिजली का कोई भी काम जारी नहीं हुआ। मैं माननीय कमलापति जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे विशेष आग्रह पर दो, तीन ट्यूबवेल्स स्वीकार किये और वे ट्यूबवेल लग भी जरूर गये हैं, लेकिन आज तक उनको बिजली नहीं मिली। एक कस्बा दादरी है, जिससे हमारे सभा सचिव महोदय बहुत दिनों से परिचित हैं, एक व्यापारिक स्थान है जी० टी० रोड पर, दिल्ली के बहुत नजदीक है। मगर कितने दफ़ा लिखने के बावजूद भी वहां आज तक बिजली लगाने के लिये सरकार की तरफ़ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसा सभी सदस्य कहते हैं, हमारी एक कठिनाई है और मैंने कई दफ़ा कहा कि मेरा क्षेत्र दिल्ली और पंजाब की सीमाओं से मिलता है। पंजाब गवर्नमेंट, जो गुड़गांव का जिला सबसे खुश्क इलाका कहलाता था और जहां रोशनी और पानी के कोई साधन नहीं थे, मेरी सीमा से मिला हुआ इलाका है, वहां पर आज गांव गांव में बिजली के बल्ब लगा दिये गये हैं और सिंचाई के लिये ट्यूबवेल लगा दिये गये हैं। और दिल्ली तो मेरे इलाके से मिला है और दिल्ली की रोशनी हमें चकाचौंध करती है। दूसरी ओर बिजली की कमी है और मेरे क्षेत्र में बिजली का कोई काम तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भविष्य क्या होगा इसको मैं नहीं जनता हूं। मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से शिकायत है कि बार बार याद दिलाने के बावजूद भी वहां कोई काम नहीं किया गया है।

गांव में बिजली दिये जाने के लिये घोषणा की गई है। मेरी जानकारी है भी लेकिन वहां जो शर्तें हैं वह विशेष रूप से शहर में नहीं हैं कि इतना रुपया जमा करें और लाइनिंग का खर्चा शहर से ज्यादा गांवों पर लगा हुआ है। फिर हमारे गांव में बिजली की घोषणा करना दिल्ली दिखाने के समान है। जैसे बच्चे को कान पकड़ कर ऊपर उठाया जाता है। वह दिल्ली देखता तो नहीं है लेकिन मंजूर कर लेता है। मैं समझता हूं कि यह चीज भी वही है। शर्तें इतनी सख्त हैं कि बिला देखे ही बतला दें कि हमने दिल्ली देख ली। योजना तो यह ठीक है लेकिन शर्तें इतनी सख्त लगा दी गई हैं कि गांव वाले बिजली लेने के लिये तैयार नहीं होंगे। मुझे अपने गांव की मालूम है। बिजली के कनेक्शंस मंजूर पड़े हैं लेकिन शायद ही किसी आदमी ने बिजली ली हो, क्योंकि इतना रुपया गांवों में नहीं है लेकिन सरकार का अन्दाजा यही है कि गांव के लोग मालदार हैं और उन पर कितने ही सख्त शर्तें लगा दें, वह दे देंगे।

उद्योगों के बारे में मंत्री जी ने चर्चा की। मेरे करीब में गाजियाबाद है, जब से वहां शरणार्थी आये हैं तब से वहां पर बहुत से लोहे के अत्यन्त उपयोगी कारखाने लग गये हैं और वह उपयोगी सामग्री पैदा कर रहे हैं। ढ़लाई के वहां एक दो कारखाने तो ऐसे हैं जो दक्षिणी भारत या एक जगह और हैं यानी उसका देश भर में तीसरा नम्बर है। यहां के उद्योगपति पंत जी, गुप्ता जी और हाफिज जी से मिले। एक दफ़ा नहीं मिले बल्कि कई दफ़ा मिले और उनकी बराबर यह मांग होती है। पंजाब सरकार उनसे कहती है कि हमारे यहां कारखाने लगाओ और हम आपको जितनी बिजली चाहोगे, देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहां लगाओ, हम बिजली देंगे और सस्ती देंगे। बिजली की दर हमारे यहां पंजाब और दिल्ली से ज्यादा है। हमारे सभा सचिव पधारे उनके सामने भी यह समस्या आई। वायदे हो जाते हैं, मगर गाजियाबाद के लिये बिजली नहीं दे सके। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार के पास भी उनका डेपूटेशन आया और जब कोई मिनिस्टर वहां पहुंचता है तो वह मांग करते हैं, इसलिये यदि सरकार उद्योगों को बढ़ाना चाहती है तो हमारे इलाके की तरफ जहां सरकार की निगाह कम पहुंचती है, वहां बिजली सिंचाई के लिये, उद्योगों के लिये और गांवों को रोशनी देने के लिये बिजली दे सकें, तो दें। यही कहना मैं उचित समझता हूं।

श्री गणेशप्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् सम्बन्धी अनुदानों के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और मैं इन अनुदानों के प्रस्तुत करने के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन एक दो बातें मुझे आप से अर्ज करना है वह यह है कि आज के समय में बिजली एक आवश्यक वस्तु जीवन की बन गई है। कुछ दिन पहले हो सकता है कि उसका शुमार जीवन में 'लक्जरी' में रहा हो, लेकिन आज के जीवन की आवश्यकताओं में से यह एक है। बहरहाल यह देखते हुये कि हमने सारे प्रान्त में बिजली दौड़ाई है उस पर जो कीमत देनी पड़ती है उसकी तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक है। आज शहरों में काफी बेकारी है और वहां खर्च काफी बढ़े हुये हैं, ऐसी हालत में आज उन्हें जब ज्यादा दाम देना पड़ता है तो एक और कष्ट उनको होता है। मैं इस सिलसिले में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[श्री गणेशप्रसाद जायसवाल]

एक तो यह है कि अगर हम बिजली देने वाली कंपनियों को राष्ट्रीयकरण कर लें तो फायदा होगा। यह जो अलग-अलग रेट्स से बिजली का दाम लेती हैं अलग अलग शहरों में वह समाप्त हो जायगा और एक समानता आ जायगी सारी दरों के अन्दर और इसका एक अच्छा असर पड़ेगा।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है और मेरा इलाहाबाद शहर का एक अनुभव है इस बारे में। हमारे यहां मार्टिन कम्पनी की तरफ से बिजली कंपनी का काम होता है। इस क्षेत्र में बीसों गांव हैं जिनको बिजली की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन बिजली कंपनी चूंकि एक व्यापारी की दृष्टि से काम करती है, इसलिये उस तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। वहां सब से ज्यादा आवश्यकता है हमारे हरिजन भाइयों को और दूसरे किसानों को, जो काफी बड़ी तादाद में वहां रहते हैं। वहां ये लोग बिजली नहीं ले जाते और ऐसी जगहों में ले जाते हैं जहां से उनको मुनाफा ज्यादा होता है। मैं यह चाहता हूं कि बिजली जहां जरूरत हो, वहां दी जाय और इसका काफी ध्यान रखना चाहिये।

एक बात और, इस काम में खर्च पड़ता है, नयी-नयी स्कीमें हैं उनमें भी खर्च करना है लेकिन यह जो टैक्स बिजली पर है अगर किसी वक्त उसमें कुछ कमी की जा सके तो शहरों में जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उनके आर्थिक पहलू पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

अन्तिम बात यह है कि रिहेन्ड डैम जो बनेगा वह बहुत बड़ी चीज होगी और उससे तमाम जिलों को बिजली दी जायगी, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि रास्ते में ही यह जिला इलाहाबाद का पड़ता है लेकिन इसके साथ-साथ यह क्यों किया गया कि इसको इस रिहन्द डैम से बिजली न मिलेगी। फतेहपुर, प्रतापगढ़ आदि सब जिलों को बिजली मिलने की बात है। मैं चाहता हूं कि विद्युत् मंत्री जी इसका ख्याल करें और इसको भी उस लिस्ट में शरीक कर लें। वैसे ही इलाहाबाद का जिला हर बात में पीछे किया जाता है, लेकिन इस बात से तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो लाइन चलेगी वह इलाहाबाद जिले को छोड़ कर और सब आस-पास के जिलों से जायेगी और उनको उससे फायदा होगा।

मैं इन सुझावों के साथ एक बार फिर विद्युत् मंत्री जी को उनके इस अनुदान के पेश करने पर बधाई देता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय है वह किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिये कितना महत्वपूर्ण है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है और यह विषय इतना टेक्निकल भी है कि इस पर बहुत ज्यादा टीका-टिप्पणी करने से, मैं समझता हूं कि कोई बहुत ज्यादा लाभ भी होने वाला नहीं है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है कि कौन कितनी बिजली पाता है और कहां क्या है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वह ऐसी बातें हैं जिनको साधारण लोग, जो एक किलोवाट तक को नहीं समझते हैं कि क्या है, उसमें कोई दिलचस्पी उन्हें नहीं होती है। इसलिये मुझे बड़ा दुःख है। कि आज हमारी तरफ से भी कोई आंकड़े पेश नहीं किये जा रहे हैं और माननीय परिपूर्णानन्द जी की सारी पढ़ाई आज बेकार चली जायगी, क्योंकि उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, उन बातों की ओर ही ज्यादा ध्यान दूंगा जोकि हमारे रोज के कामों से संबंधित है।

हमारे प्रदेश के विकास के कार्य में, चाहे हम औद्योगिक विकास करना चाहें, चाहे काटेज इंडस्ट्री का विकास करना चाहें या खेती को बढ़ाना चाहें, या रोशनी की चमचमाहट करना चाहें या किसी तरह हम देश की आर्थिक उन्नति करना चाहें, यह आवश्यक है कि हमारे बिजली के जो साधन हैं वह हमारे प्रदेश के हर कोने-कोने के अन्दर पहुंचाये जायं और इस बात की कोशिश हो रही है।

मुझे आज यह कह देने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि बिजली के मामले में काफी प्रगति हमारे इस प्रदेश में हुई है। आज आप जगह-जगह जाइये, बरेली से नैनीताल को आप जायें, तो वहां दोहना एक जगह है, वहां पर ट्रांस्मिशन लाइन्स का बड़ा स्टेशन दिखायी पड़ेगा। मुझे और जगह तो जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम भी उस वक्त यह महसूस करते हैं कि हमारे प्रदेश में भी औद्योगिक विकास का काम कुछ हुआ है। बम्बई वगैरा तो ऐसे प्रदेश हैं कि वहां बिजली का बड़ा भारी उद्योग है। मैं वहां पर काफी रहा हूं। वहां बिजली से ट्रेन पूना को चलती है, और सारी लोकल ट्रेन्स बिजली से ही चलती हैं। वह इसलिए कि वहां पर बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा है। इस तरह से वहां पर तरक्की काफी हो चुकी है।

अगर हमारे प्रदेश में यह काम इसी तरह से चलता रहा तो मुझे आशा है कि चन्द वर्षों में कुछ न कुछ हमारा प्रदेश औद्योगिक विकास में और काटेज इन्डस्ट्री में उन्नति करेगा और दूसरी सहूलियत भी यहां मिलेगी। जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे टेक्निकल लोग हैं, जब वह मेहनत से अपना काम करते हैं यदि हम उनकी कदर नहीं करते हैं तो हम उनको निरुत्साहित करते हैं। हम चाहते हैं कि जहां पर अच्छा काम हो, हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि वे और उत्साह के साथ अपना काम करें। साथ ही मुझे थोड़ा सा दुख उस समय हुआ जब कि हमारे चन्द्रसिंह जी रावत अपना भाषण कर रहे थे। मुझे इस बात का दुख हुआ कि चन्द्रसिंह जी रावत के गढ़वाल में बिजली का नामोनिशान नहीं है। वह काफी दिनों से कहते रहे लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। जब नजीबाबाद से कोटद्वार को बिजली नहीं जा सकती है, तो फिर ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है। जहां पर मोटर सड़क नहीं है वहां पर बिजली की टरमाइन ले जाना भी मुश्किल है, वहां के लिए कुछ इन्तजाम सरकार को करना ही चाहिए। वहां पर अगर वाटर फाल है और सड़कों के पास है, तो इन पर मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी विचार करने की कृपा करेंगे। उन जगहों में बिजली की योजना की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए ताकि रावत जी और मैठाणी जी की जो शिकायत है कि वहां पर नजीबाबाद से आगे अंधेरा है, वह दूर हो सके। हमारे दारुलशफा के कमरों में जब पंखे चलते हैं और बिजली के बटन दबाने पर रोशनी होती है, तो उनको एक अजीब सी चीज मालूम होती है। तो यह लोग कब तक इसका एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी जो मांग है, वह बहुत उचित मांग है, और जायज मांग है। रामगंगा से हमारे यहां बिजली जायगी या लोहिया हेड से बिजली मिलेगी, यह चीज तो मुश्किल मालूम पड़ती है। इसकी कब तक उम्मीद की जाय यह तो आपको बतलाना ही पड़ेगा। हमारे यहां कब तक बिजली आने वाली है और खास कर पर्वतीय प्रदेश के लिए, जहां बिजली की बहुत ही आवश्यकता है, यह तो पहाड़ी प्रदेश में जहां पर रास्ते हैं, जहां पर एलेक्ट्रिक रोपवेज हैं वहां के रहने वाले अन्दाजा लगा सकते हैं। हमारे पास नैपाल देश है। वहां पर रोपवेज हैं। उनसे उनको बहुत सहूलियत है। अगर आप हमारे यहां इस तरह के यातायात के साधन उत्पन्न नहीं करेंगे और रोपवेज की व्यवस्था नहीं करेंगे तो पहाड़ों में जो खनिज पदार्थ हैं, जहां से आपको लोहे का काम करना है, पीतल का काम करना है यह काम तभी हो सकते हैं जब कि वहां पर ट्रांस्पोर्ट के साधन हों। मोटर का किराया बहुत ज्यादा होता है। अगर सस्ता काम हो सकता है तो रोडवेज से ही हो सकता है। इसलिए जहां तक बिजली का महत्व है और वह भी ज्यादा बढ़ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कभी इस बात की कोशिश करना नहीं चाहते और न कभी करते हैं कि हम क्रिटिसिज्म इसलिए करें कि हमको क्रिटिसिज्म करना है। जहां पर हम समझते हैं कि देश तरक्की करेगा, उन्नति

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

करेगा और उसकी उन्नति के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता है और किसी भी प्रदेश में रहने वाले की सहायता की आवश्यकता है तो हम उस सहायता के करने को सर्वदा तैयार रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक शहरों का भी ज्यादा ख्याल किया गया है। अब ऐसा हमें बताया गया है कि आगे २०० गांवों को लिया जायगा। गांव वालों को अपने घरों को रौशन करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है, और जिस रेट पर आप बिजली दे रहे हैं उस दाम पर वह रोशनी नहीं ले सकते। उनको तो पानी के साधन चाहिए, पहाड़ों पर हम देखते हैं कि नीचे नदियां बहती हैं, और ऊपर गांव वाले पानी पीने के लिए तरसते हैं। अगर बिजली के साधन हमारे यहां हो जायं तो हमारे यहां पीने के पानी की समस्या ही न सुलझ जायगी, परन्तु सिंचाई की व्यवस्था भी हो सकती है। जहां-जहां लाइन बिजली की गयी है, वहां उसको देखकर हमें खुशी होती है। रानीखेत और अल्मोड़ा साइड में बिजली दी जा रही है। वहां जब बिजली लगती है तो कैसी मेहनत से वे लोग काम करते हैं। उस लाइन को लगाते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप किसी समय उनको देख लें, तो मालूम होगा कि कितनी तकलीफ उनको होती है। आज आप देखें और १० दिन बाद देखें तो आपको नक्शा बदला हुआ ही मालूम होगा। माननीय मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि वे रेट्स को कम करें। उद्योग धंधों और सिंचाई के लिए उनके रेट्स में काफी कमी होने की जरूरत है। माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें कि इरिगेशन के लिए, उद्योग धंधों के लिए और लोकल कंजम्पशन के लिए बिजली के रेट्स क्या हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अब गांवों की ओर बिजली को अधिक पहुंचायें, अभी तक तो उनका ध्यान शहरों की ओर ही अधिक गया है। बहुत से शहरों को बिजली दी गयी है, यह भी अच्छा ही काम हुआ है, लेकिन अब गांवों की तरफ भी उनका ध्याना जाना चाहिए। कम्पनियों से बिजली लेकर सरकार कार्मशियल बेसिस पर उसका उत्पादन स्वयं करे और सारे प्रदेश में बिजली के एक ही रेट्स हों। कहीं लाभ भी हो सकता है और कहीं नुकसान भी हो सकता है। सब लोगों को उसके उत्पादन से लाभ होना चाहिए ताकि प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ सकें। उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए लोहियाहेड जैसे प्रोजेक्ट्स बनने की आवश्यकता है, तभी हमारा प्रदेश बिजली से चमक सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं।

*श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शुबहा नहीं कि हमारे प्रदेश में इस थोड़े से अर्से में बिजली की बहुत ज्यादा पैदावार हो गयी है। सन् ४६ से ५६ तक अगर देखा जाय तो आज बिजली की बहुत ज्यादा पैदावार हो गयी है। और मुनासिब तरीके से डिस्ट्रिब्यूशन होता है। लेकिन जनाब वाला, आजकल के जमाने में बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत हो गयी है। हम को बताया गया है कि मुल्क के रोजगार की ओर जराअत की जरूरियात को वह फराहम नहीं कर सकता है। हमारे प्रदेश में इस बात की जरूरत है कि उसको इन्डस्ट्रियलाइज किया जाय। जितनी इसमें तरक्की होगी, उतनी ही बेरोजगारी दूर हो जायगी। जहां तक मेरी याद बताती है कि पंडित जवाहरलाल जी ने भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यह बताया है कि १० साल के अन्दर वे बेरोजगारी को दूर कर देना चाहते हैं और वह उद्योग धंधों के जरिये ही दूर हो सकती है। लिहाजा मेरी गुजारिश माननीय मन्त्री जी से यह है कि इस सूबे के वह हिस्से कि जहां बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, और जो कि उसकी सख्त जरूरत को महसूस कर रहे हैं उनके लिए ऐसा इन्तजाम किया जाय कि वहां भी बिजली पहुंच जाय ताकि वहां के लोगों को रोजगार पाने में सहूलियत हो।

जनाब वाला, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि वहां जिन्दगी की जो मौजूदा सहूलियतें हैं वह वहां दस्तयाब नहीं हैं जैसे वहां रेल या सड़कें नहीं हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन अब जब कि मैंने पी० डब्लू० डी० के माननीय मन्त्री जी से गुजारिश की तो एक सड़क जिसकी सख्त जरूरत थी वह अब जेर तामीर है और पंचवर्षीय योजना के मातहत १४३ मील और सड़क बनने की जिला बदायूं में तजवीज है...

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

जनाब वाला, मैं यह कह रहा था कि बेरोजगारी को इस मुल्क और इस प्रदेश से उस वक्त तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि हम अपने प्रदेश का अच्छी तरह से इन्डस्ट्रियलाइज न कर लें। मेरे क्षेत्र का जहां तक ताल्लुक है मैंने यह अर्ज किया था कि वहां सड़कें भी नहीं थीं और बिजली भी वहां नहीं है और बावजूद इसके कि वहां पिछले साल तक टचूबवेल भी नहीं थे जिनके द्वारा जराअत को तरक्की हो सके। गालिबन माननीय मन्त्री जी जानते होंगे कि सहसवान म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक दरख्वास्त आयी है कि बिजली वहां फराहम की जाय और इसी सिलसिले में मैंने अपने शार्ट नोटिस क्वेश्चन के जरिये माननीय मन्त्री जी की इस तरफ तवज्जह दिलायी थी और उसका जवाब मुझे मिला था कि सहसवान म्युनिसिपैलिटी को बिजली देने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है और चीफ इन्जीनियर के जेर गौर है। अब मुझे अभी नहीं मालूम कि इस सिलसिले में आखिरी फैसला क्या हुआ, आया उस कस्बे को बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहां पर २ वजह से बिजली की बहुत जरूरत है। वहां पर बहुत से छोटे-मोटे कारोबार हैं और वहां गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा है। मैंने पिछले मौके पर भी तकरीर करते हुए कहा था कि उस नवा में गन्ना इस कसरत से पैदा होता है कि अगर वहां मिल लगा दी जाय तो उसके लिए वहां गन्ना बहुत काफी है, लेकिन वहां पर बिजली न होने की वजह से और दूसरी सहूलियतें न होने की वजह से, जो काटेज इन्डस्ट्रीज की सूरत में शकर निकाली जाती हैं उसकी सूरत यह है कि बहुत से मालदार, सरमाएदार आकर काश्तकार का माल खरीदते हैं और काश्तकारों के दरम्यान एक शख्स और होता है जिसके द्वारा माल खरीदा जाता है और वह दरम्यानी आदमी साहूकार से कुछ परसेंट अलग लेता है और काश्तकार से अलग लेता है। अगर वहां बिजली होती, तो मैं यकीन रखता हूं कि बड़े-बड़े काश्तकार जो वहां थे तो वह कशर रखते और उसके जरिये जो उनकी गन्ने की पैदावार थी, उससे रस निकाल कर शक्कर बना सकते।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जगह बताइये।

श्री मुश्ताक अली खां---सहसवान, जिला बदायूं।

अब दूसरी चीज इसके सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि कपड़े के बनाने वाले जिन्हें बुनकर कहते हैं उनकी तादाद भी इस कस्बे में बहुत है। अगर बिजली हो तो वह अपने हैन्ड-लूम को बिजली के जरिये से चलायें जिस से कपड़े की ज्यादा पैदावार हो। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब छोटे-छोटे तिजारत करने वालों की जरूरियात को पेशेनजर रखकर, जो गन्ने की काश्त करते हैं, उनकी जरूरियात को पेशे नजर रख कर वहां बिजली भेजने का इन्तजाम करेंगे।

श्री शिवसहायरण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी खुशी है रावत जी ने यह बताया कि खारे गढ़वाल के लोग अछूते हो गये। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी संख्या बढ़ गयी है, तो मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अगर हमारी संख्या बढ़ रही है, तो बड़ी हमा है। (एक सदस्य---सीटें भी बढ़ जायेंगी।) इस सीटें बढ़ने वाली हैं उनमें रावत जी भी आ जायेंगे।

[श्री शिवनारायण]

उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश की उन्नति के लिए बिजली बड़ी परमावश्यक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल हुई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कदम रख रहे हैं और बिजली पर ही सब कुछ निर्भर है। पहले बिजली हमने शहर को दी, लेकिन अब गांवों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। पीछे नहीं हैं। नैनीताल में भी बिजली पहुंची है। उसके पड़ोस में गढ़वाल है। मान्यवर, मेरे जिले बस्ती में एक बड़ा भारी ताल बखिरा का है, जिसमें वाटर पम्पिंग का प्रबन्ध है लेकिन बिजली न होने की वजह से पानी को नहीं उठाया जा सकता। पिपरा गौतम के पास एक छोटी सी नदी बहती है। बिजली मिल जाय, तो वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। अगर बिजली का प्रबन्ध वहां हो जाय, तो छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज में डेवलप्मेंट हो सकता है और जो हमारे एन्ट्रेंस और मिडिल पास बेकार घूमते हैं उनको छोटे छोटे रोजगार मिल जायेंगे। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में बिजली पहुंचायी जाय। जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा अभी तक हम शहर से चलते थे, अब गांव की तरफ से शहर की तरफ चलेंगे। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हैं। वहां बिजली न होने से हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। बिजली पहुंचायी जाय, तो छोटे छोटे उद्योग पनप सकते हैं और इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का फायदा यह होगा कि हम अपने गांव को ऊंचा उठा सकते हैं गांव वाले भी आज मिट्टी का तेल जलाना पसन्द नहीं करते। वह उसकी बदबू पसन्द नहीं करते। वह भी चाहते हैं कि बिजली जलावें। खरबूजे को रंग बदलते देख कर खरबूजा रंग बदलता है। कोई आदमी बढ़िया चीज पहनता है, तो दूसरे आदमी पर भी असर पड़ता है क्योंकि हर आदमी अच्छी चीज पसन्द करता है। हमारे गांव का किसान आज हमसे क्वेश्चन करता है। वह हम से पूछता है कि हमारे लिए आपने बजट में क्या किया। नत्थू चमार भी पूछता है। रावत जी यहां कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। नत्थू चमार भी पूछता है। तो सरकार सचेत रहे और बिजली पहुंचाये। हम नहीं कहते कि गढ़वाल को इगनोर किया जाय।

रावत जी से मैं निवेदन करूंगा कि देहात में एक मसल है। "माई जी," और "बाप की मेहरी" दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन अगर कहो कि "माता जी पानी दे दो" तो बड़े प्रेम से पानी दे देगी लेकिन अगर उसी को "बाप को मेहरी" कह दिया जाय तो जूता लेकर फाल इन हो जायगी। तो कहने का ढंग होना चाहिए। मैं माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपनी ग्रीवांसेज को रखा। अपोजीशन जरूर होना चाहिए। जहां जरूरत हो गवर्नमेंट के बजट में मांग की जाय। लेकिन ढंग से कहना चाहिए। रावत जी की तरह तैश में नहीं आना चाहिए। हम आप से कम क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप हम को बिजली नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे क्योंकि हमको बेकारी की समस्या और गरीबी को दूर करना है। यह थोड़े ही है कि हम सरकार को छोड़ देंगे। सरकार को तो पैसा देने के लिए हम यहां आये हैं। अगर हमारी जरूरत न होती तो सरकार बैठकर पास कर लेती और गवर्नर से आज्ञा ले लेती। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट को मेम्बरों की राय से काम करना पड़ता है। और मेम्बरों की ड्यूटी है कि वह ठीक ढंग से अपनी बात रखें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। यह सदन कोई प्रीचिंग के लिए नहीं है। यह तो व्यवस्था के ऊपर बात करने की जगह है, न कि प्रीचिंग के लिए। यहां पर क्या प्रीचिंग पर वक्त खर्च करने के लिए सभी लोग आये हैं या व्यवस्था पर बात करने के लिए आये हैं?

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। उनको किसी के भाषण के विषय में अपनी राय देने का पूरा अधिकार है।

श्री शिवनारायण—मैं कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जैनुइन डिमान्ड्स पेश कर रहा हूं। और समझने वालों की बुद्धि पर उनको छोड़ता हूं। आज यह पब्लिक की जैनुइन डिमान्ड है कि बिजली के रेट्स एक होने चाहिए। एक रेट पर रखिये, चाहे वह मैदान हो या पहाड़ हो। जहां कमी पड़ती हो, वहां पर सरकार बरदाश्त करे। सरकार ने जिम्मेदारी ओढ़ी है और जनता को हमने विश्वास दिलाया है कि हम तुम्हारी गरीबी को हल करेंगे। हमने जमींदारी का खात्मा किया और हम कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए कदम उठ रहा है। मिसाल के लिए सरकार ने इंश्योरेंस बिजिनेस को अपने हाथ में ले लिया है जिससे करोड़ों रुपये मिलेंगे और जिससे पंचवर्षीय योजना सफल होगी, बिजली की स्कीम सफल होगी। इसलिए माननीय वित्त मन्त्री का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी मांग वह पूरी करेंगे और बस्ती को इगनोर न करेंगे और हमारी डिमान्ड को पूरा करने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। यह छोटे-छोटे रोजगारी लोग जो दरख्वास्त देते हैं, आफिस वालों से कह दिया जाय कि उन के ऊपर कृपा करें। बड़ी परेशानी होती है। वे लोग आते हैं और हम को घेरते हैं कि चलकर हाफिज जी से, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से कह दीजिये, चीफ इन्जीनियर से कह दीजिये। इस प्रकार न हम पढ़ने पाते हैं और न सुख से रहने पाते हैं। इन चीजों में उनको सुभीता मिलना चाहिए, क्योंकि हर हिन्दुस्तानी की यह ड्यूटी है, चाहे वह आफिसर हो, मिनिस्टर हो, या अन्य कोई सिटिजन हो, हर एक की ड्यूटी है कि पंचवर्षीय योजना को हल करने में वह सहयोग दे, गरीबी, भुखमरी को दूर करने में सहायता करे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

***श्री रामसेवक यादव** (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की ओर से और सरकारी पक्ष की ओर से बातें सुनी गयीं और मंत्री महोदय बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि बहुत बधाई मिल चुकी है। और यह शिकायत होगी कि किसी ने कुछ कहा नहीं, तो मैं उस शिकायत को पूरी करने की कोशिश करूंगा, घबराइये नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय सोशलिस्टिक पैटर्न के मंत्री हैं और साथ-साथ मुसलमान भी। और इस्लाम का तो उसूल मसावात पर है। लेकिन जब हम बिजली के रेट्स जो सारे सूबे में फैले हुये हैं उनको देखते हैं तो इतना बड़ा फर्क है। कहीं पर कुछ रेट है, कहीं पर कुछ रेट है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा सोशलिस्टि पैटर्न है, और किस तरह से हमारे मंत्री महोदय, इस्लाम के अनुयायी हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अब "पैटर्न" नहीं रहा। सिर्फ सोशलिस्ट हैं।

श्री रामसेवक यादव—तो तरक्की कर रहे हैं।

तो इस तरह से चीजें हो रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान और खास तौर से हमारा यह राज्य अधिकतर देहातों में बसा हुआ है, लेकिन मंत्री महोदय ने सिर्फ यह संकेत दिया है कि २५० गांवों में बिजली दी जायगी जिसमें ५० टाउन्स शामिल हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मद्रास में और बम्बई में लगभग २,५०० गांवों को बिजली दी जा चुकी है। लेकिन हमारे बजट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अगर हम चाहते हैं कि गांवों तक बिजली पहुंचे, सिर्फ शहरों तक ही न महदूद रहे और गांवों में रोशनी का फायदा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसेवक यादव]

पहुंच सके, छोटे २ उद्योग धंधे चल सके, हम तरक्की कर सके तो कोशिश बराबर होनी चाहिये कि गांवों की तरफ भी बिजली जाय और इसकी संख्या बढ़े। संख्या बढ़ने के साथ-साथ यह भी कोशिश होनी चाहिये कि बिजली की दरें कम हों ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में एक बात और निवेदन करूं कि मंत्री महोदय का ध्यान बाराबंकी जिले की तरफ बिल्कुल नहीं गया। मंत्री महोदय का विशेष करके आने-जाने में, मुशायरे में, जलसों का उद्घाटन करने में बहुत हाथ रहा करता है, लेकिन जब बजट में कुछ तरक्की की बात उठती है तो शायद ध्यान नहीं जाता। उपाध्यक्ष महोदय, बाराबंकी जिले में एक मुकाम है बहरामघाट, वहां से घाघरा नदी गुजरती है और वह ऐसा मुकाम है कि अगर घाघरा नदी को टेम करके कोई बिजली की योजना बनायें तो हम उससे न कि बाराबंकी के कुछ इलाकों को बल्कि बहराइच, सीतापुर, गोंडा और फैजाबद के सभी इलाकों में सिंचाई का बन्दोबस्त कर सकते हैं और गांव २ बिजली हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, वह स्थान ऐसा स्थान है कि जहां पर काफी लकड़ी का काम और दूसरे किस्म के काम को तरक्की देकर अनाज की मंडी या छोटे मोटे कल कारखाने बना करके, जो पड़ोस के जिलों में बेकारी फैली हुयी है उसको दूर करके सकते हैं। लेकिन मंत्री महोदय का उस ओर ध्यान नहीं गया। मैं निवेदन करता हूं कि वह इस ओर भी ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि जब स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के ग्राम मसौली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक का काम शुरू हुआ तो बाराबंकी शहर के बसने वाले लोगों के दिल में एक खुशी पैदा हुई थी और उनको उम्मीद थी कि अब बाराबंकी जिले को भी हाइड्रो इलैक्ट्रिक के सिलसिले में कुछ फायदा पहुंचेगा और आज जो बढ़े हुये रेट्स हैं उनसे छुटकारा मिलेगा और उनका बोझ बहुत हल्का होगा। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यह आशा निराशा में परिवर्तित हुयी और २५ अक्टूबर को स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के गांव में बिजली गयी, उसके बाद बराबर प्रयत्न जारी है जनता की तरफ से और जहां तक मुझे ज्ञात है वहां की कम्पनी की ओर से भी। लेकिन मंत्री महोदय ने इस ओर शायद कुछ ध्यान नहीं दिया और खास तौर से जो आपका डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियर्स हैं वह पता नहीं क्यों, दिलचस्पी नहीं लेते। उपाध्यक्ष महोदय, बाराबंकी शहर तो यों ही लखनऊ के करीब होने से पिस रहा है और इस तरह से अगर मंत्री महोदय उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मसौली जरा दूर है वहां बिजली पहुंचने से बाराबंकी का सारा रोजगार ठप हो जायगा। तो उपाध्यक्ष महोदय,मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस ओर जो ढिलाई चल रही है उसको जल्द से जल्द खत्म करके बाराबंकी शहर को हाइड्रो इलेक्ट्रिक देने का बन्दोबस्त हो और सस्ते दाम में, जो सस्ते रेट्स हों ताकि वहां की जनता को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके और वह तरक्की कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी ज्ञात हुआ है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो अधिकारी वर्ग इससे सम्बन्ध रखते हैं वह बिजली देने में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को और कम्पनियों को, कुछ वहां पर धांधा-गर्दी चलती है, शायद वह करप्शन की बात होगी। इसीलिये हमारा ख्याल है कि बाराबंकी शहर उसी का शिकार है और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, अब यहीं समाप्त करके मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इन बातों पर ध्यान देंगे।

श्री नेकराम शर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो अनुदान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिये करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि वास्तव में जिस तरह से बिजली विकास ने इस प्रदेश में उन्नति की है उससे हमारे प्रदेश में बहुत उन्नति हुई है और हम और उन्नति करने जा रहे हैं,इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। आज हमने सोशलिस्ट पैटर्न की बात छोड़ करके सोशलिस्ट सोसाइटी यानी समाजवादी व्यवस्था कायम करने की बात की है, अमृतसर कांग्रेस सेशन में, उसको देखते हुये हमारे बिजली विभाग के जो विकास कार्य हैं, योजनायें हैं जिस तरह से उनमें उन्नति

हो रही है, समाजवाद की तरफ ले जाने के लिये, वाकई वह एक सही कदम है। जितने भी बांध बने, जितने भी पावर हाउसेज बने हैं उनसे जो बिजली पैदा की जाती है वह वास्तव में इस प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भाग लेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं देखता हूं कि इस विभाग ने कोई एक योजना ऐसी नहीं बनायी अर्थात् प्लानिंग नहीं है कि हम जितनी भी बिजली पैदा करेंगे उस बिजली का किस तरह से वितरण करेंगे, हमारी आवश्यकता क्या है ? किसको प्राथमिकता देनी है ? मैं बड़े अदब के साथ उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि प्लानिंग की इसलिये आवश्यकता है कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें हम उद्योगों का विकास करेंगे, और उद्योगों के विकास के लिये जरूरी है कि हम काटेज इंडस्ट्रीज की भी तरक्की करें। वह तरक्की तभी सम्भव हो सकती है कि जब जो हमारे प्रदेश में ऐसे-ऐसे कस्बे हैं कि जहां पर घरेलू उद्योग हैं वहां उनको पहले बिजली दें। मैंने विभाग की किताब देखी। इसमें गांवों में बिजली देने की बात कही गयी है। खुशी की बात है। लेकिन इसमें भी यह बात नहीं रखी गयी कि हमारे प्रदेश में जितने हमारे उद्योग के केन्द्र हैं, ऐसे कस्बे हैं कि जहां काटेज इंडस्ट्रीज काफी मात्रा में हैं वहां पर बिजली पहले दी जायगी।

दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ बिजली पैदा की जा रही है उसकी अगर प्लानिंग न की गयी तो इतनी बिजली पैदा हो जायगी कि एक समस्या बन जायगी, तो इसलिये पहले जिस उद्देश्य से यह बिजली पैदा की जा रही है उसको एक प्लानिंग होनी चाहिये। जिसमें कि इंडस्ट्रीज को प्रायटी मिल सके। दूसरी बात मैंने यह देखी कि कई जिलों में, गावों में भी बिजली दी गयी है। हमारे जिले अलीगढ़ में भी आठ दस गांवों में बिजली दी गयी है। हमारे यहां पुलिंदनगर एक कस्बा है जहां कि ग्लास की इंडस्ट्री है, चूड़ियां भी बनती हैं, हैन्डलूम का भी काम है और कई छोटे-मोटे काम काटेज इंडस्ट्रीज के वहां होते हैं, वह जगह सिकन्दराराऊ से एक डेढ़ मील की दूरी पर है। वहां पर टाउन एरिया के चेयरमैन और सारी जनता की ओर से प्रस्ताव पास करके भेजा गया, उन्होंने कहा कि जितना रुपया आप चाहते हैं वह हम देने के लिये तैयार हैं। मैं स्वयं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब धर्म सिंह जी से मिला और उनको प्रार्थना-पत्र दिया। उन लोगों के दस्तखत भी जो कनेक्शन लेना चाहते हैं, वह भी दे दिया गया, लेकिन आज दूसरा साल हो रहा है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मुझे अश्वासन भी दिया गया था कि आगामी साल में उस कस्बे में बिजली जरूर पहुंचा दी जायगी, लेकिन अब तक उसका प्रबंध नहीं किया गया। तो मैं बड़े नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि वाकई विभाग ने काफी उन्नति की है, लेकिन जरूरत आज इस बात की है कि हम एक प्लानिंग के आधार पर चलें ताकि जिस रूप में जिस स्थान के लिये, जितनी बिजली की आवश्यकता हो वहां उतनी बिजली हम पहुंचा सकें, कितनी बिजली पब्लिक सेक्टर तथा कितनी प्राइवेट सेक्टर के लिये आवश्यक है तथा कितनी अन्य कामों के लिये चाहिये, ऐसे आकड़े सरकार के पास हों जिससे प्रदेश का अच्छा विकास हो सके। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जितनी कोआपरेटिव सोसाटियां हैं उनको बिजली पहले दी जाय। इंडिविजुअल्स को जो चक्कियों के लिये या और चीजों के लिये अर्जी देते हैं उन्हें न दी जाय। हमको प्रयत्न यह करना चाहिये कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां हों या ग्राम पंचायतें बिजली मांगती हों, तो उनको बिजली पहले दी जाय। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि गांव में चल रही हैं और उनको बिजली नहीं मिलती है तो गांवों में जहां लाइनें गयी हुयी हैं वहां उनको बिजली देने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से केन्द्र से रुपया लाकर के इस सूबे में जो लाखों किलोवाट बिजली

[श्री नेकराम शर्मा]

इन्होंने पैदा की है उसके लिये वह वाकई बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि आइन्दा भी वह केन्द्र से काफी रुपया लाकर के इस सूबे को ऐसा बना जायेंगे कि इस सूबे में रहने वाले उनके नाम को हमेशा याद करेंगे ।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में, उसके आय-व्ययक का लेखा पेश करते हुये माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्षों के कार्य को और आगे क्या कार्य होने जा रहे हैं, उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा बतलायी । उस रूपरेखा के सुनने के बाद चाहे लोग इधर बैठ रहे हों चाहे दूसरी तरफ बैठे हुये हों, लेकिन सभी लोगों ने आपको बधाई दी और सभी लोगों ने आपके कार्यों की सराहना की । मैं अपनी ओर से और अपने साथ साथ उन व्यक्तियों की ओर से जो इस बिजली के उत्पादन के कार्य में लगे हुये हैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

मेरे सामने एक प्रश्न है और वह यह है कि जहां एक ओर बिजली का उत्पादन बढ़ा करके माननीय मंत्री जी ने साधारण जनता और साधारण जनता से ऊपर के व्यक्तियों के अन्दर ख्याति प्राप्त की है, मेरी इच्छा है कि वही ख्याति आपकी श्रमिकों के बीच भी हो । उसके लिये मेरे छोटे छोटे कुछ सुझाव हैं । यह तो आपको मालूम ही है कि बिजली प्राइवेट सेक्टर में भी बन रही है और पब्लिक सेक्टर में भी उसका उत्पादन हो रहा है । अभी प्रातःकाल आज सदन में सुना कि प्राइवेट सेक्टर में शाहजहांपुर में एक हड़ताल हुयी । उसके कारणों को सुनने के बाद मेरे जैसे आदमी के दिमाग पर असर पड़ा कि वहां पर मालिकों की ज्यादती है । मजदूरों ने मजबूर होकर जो कुछ किया है वह मैं समझता हूं कि ठीक ही किया है । ऐसी दशा क्यों आवे, यह एक प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने है । सदन में मैंने यह भी सुना कि वहां के सारे कल कारखाने बन्द हो चुके हैं । वहां की फैक्टरियां बन्द हैं, वहां की लाइट बन्द है और वहां के लोगों को परेशानी है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सारी जनता परेशान न हो ऐसा कदम माननीय मंत्री जी उठावें और वह यह है कि जितने इस तरह के कल कारखाने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको वे सरकार द्वारा संचालित करें । दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जो कल कारखाने पब्लिक सेक्टर से संचालित हो रहे हैं उनमें एक दूसरे में विरोधाभास है । पहले उन कारखानों को देखें जिनमें एक तरीके से काम हो रहा है । एक तो हैं कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, जिसमें सारे लेबर लाज लागू हैं । वहां के मजदूरों को बोनस मिला है हालांकि मेरी राय में वह बोनस कम है और उसका कारण लेबर डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिश की गयी रिपोर्ट से सुनाता हूं । पीलीभीत में जो बिजली कम्पनी है उसने अपने मजदूरों को साल भर में ६ महीने का वेतन बोनस में दिया । सहारनपुर में एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी है उसने दो महीने की तनख्वाह का बोनस दिया, इसी तरीके से और कम्पनियों ने भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है उन लोगों ने वहां के मजदूरों को बोनस दिया, लेकिन कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो इस प्रान्त में अपने ज्यादा उत्पादन के लिये प्रसिद्ध हैं उसने मजदूरों के बोनस की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना अन्य फैक्टरियों ने दिया है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे । मेरी प्रार्थना है और यह मजदूरों की मांग भी है कि जो आपके पावर हाउसेज खुल रहे हैं, वहां के मजदूरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में होता है, ताकि उन मजदूरों को भी वे सुविधायें प्राप्त हो ताकि आपको भी आसानी हो और मजदूरों को सुविधायें मिलें, काम भी अच्छी तरह से संचालित हो । इसके बाद कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की कुछ उन चीजों को रखना चाहता हूं जैसे कि प्रान्त में सारे जगह मजदूरों के लिये मकान बन रहे हैं, जबकि प्रान्त में छोटे छोटे शहरों में जहां की मजदूरों की संख्या ऊंगलियों पर गिनने लायक है वहां पर भी आप मकान बनवाने जा रहे हैं, जैसा कि अपने भाषण में आपने कहा था, तो कोई कारण नहीं है कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मजदूरों के लिये आप मकानों का प्रबन्ध न करें । मेरी प्रार्थना है कि उन मजदूरों के लिये जहां और सुविधायें आप

देते हैं वहां इस सुविधा की तरफ भी आप अपना कदम बढ़ायें। साथ ही साथ उनकी बहुत सी मांगें पड़ी हुयी हैं। मैं नहीं जानता कि वे लखनऊ और कानपुर के बीच में कहां रुकी हुयी हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप उन पर विचार करें और अपना निर्णय दें।

इसके बाद मजदूरों के बाद मुझे इंडस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में भी कहना है। हमारी यह सूचना है और खासतौर से कानपुर की बाबत कि वहां के कुछ लोगों ने आपकी अपील पर कि हम २५ प्रतिशत मूल्य उनसे कम लेंगे। उन्होंने दरख्वास्तें दीं शायद अगस्त या सितम्बर के महीने में और आज तक उन लोगों को बिजली तो दी ही नहीं गयी बल्कि उनको यह भी सूचना नहीं दी गयी कि तुमको इस रेट बिजली मिलेगी या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि छोटी और बड़ी इंडस्ट्री बढ़े--मैं छोटी और बड़ी इंडस्ट्री के चक्कर में इस समय नहीं पड़ना चाहता क्योंकि लाल बत्ती हो गयी है तो आप कम से कम अपने विभाग के कर्मचारियों को इस बात के लिये तो ज़रूर ताकीद कर दें कि व्यापार के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन फाइलों को निपटायें ताकि लोग आसानी से कारखानों को खोल सकें जिससे अपने प्रान्त की बेकारी कम हो। इन शब्दों में फिर आपको एक बार बधाई देता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत सम्बन्धी जो अनुदान माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के लिये और हमारे देश के लिये विद्युत का उत्पादन बहुत ही महत्व की चीज़ है। हमारे प्रदेश का सारा औद्योगीकरण इस बिजली के उत्पादन पर ही निर्भर है। जब हम उस माने में मैं उसको देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना अनुदान हमसे मांगा गया है वह हमारी आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत कम है। लेकिन आपके सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं जिसके कारण आप मजबूर हैं वरना हम तो यह चाहते हैं कि जितनी तेजी से बिजली का उत्पादन हो सके, उतना अच्छा है। हमारे प्रदेश में ५१ जिले हैं और १ लाख गांव हैं। अच्छा हो और सरकार बधाई की पात्र बने, अगर तमाम शहरों, कस्बों और एक लाख गांवों के अन्दर एक साथ बिजली भेज सकें। मगर यह मुमकिन नहीं है और यदि यह मुमकिन नहीं है तो अपने-अपने जिले और अपने अपने गांव की बात यहां कह कर हम यह साबित करने की कोशिश करें, कि इस विभाग ने कोई काम नहीं किया बल्कि इस प्रदेश को पीछे फेंका तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मेरे पास कुछ पावर स्टेशन्स के आंकड़े हैं, जिन्हें मैं आपकी आज्ञा से सदस्यों के रूमाने रखना चाहता हूं। सन् ४७ में हमारे पास हाइडेल के ७ पावर स्टेशन थे, थर्मल के ३ और डीजल के ६ स्टेशन थे। सन् ५६ में हाइडेल के ११, थर्मल के ६, और डीजल के १७ पावर स्टेशन हो गये। तो कहीं दुगुने हो गये और कहीं तिगुने हो गये अगर हम इन्स्टाल्ड कैपिसिटी को लें, तो ४७ में हाइडेल की १९,९०० किलोवाट, थर्मल की २१,५०० और डीजल की १,८०० किलोवाट थी जो सन् ५६ में हाइडेल की ८६,६५०, थर्मल की ३६,२२५ और डीजल की १७,४४० किलोवाट हो गयी। तो यह हमने ७, ८ साल के अन्दर प्रगति की है। और अगर हम सन् ६१ की बात लें, तो यह कई गुना बढ़ कर लाखों की तादाद में पहुंच जायगी। इसी तरह अगर हम ट्रांसमिशन लाइन्स को लें, तो उनका टोटल सन् ४७ में ४८९९.६ मील था, जो सन् ५६ में ११२९३.७ मील हो गया। यह कहा जा सकता है कि जितनी बिजली हम चाहते थे, उतनी हमारे यहां पैदा नहीं हुई, लेकिन यह कह देना कि हमने कोई प्रगति नहीं की, मैं समझता हूं यह उचित बात नहीं है। अच्छा तो यह होता कि हमारे जिन भाइयों को शिकायत है और सभी को कुछ न कुछ शिकायत है कि अमुक जगह बिजली नहीं पहुंची, उसका मौका न मिलता, मगर जैसा मैंने बताया, हमारा इतना बड़ा प्रदेश है और हमारी सरकार के आर्थिक रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं कि उसमें यह सम्भव नहीं है कि २, ४, ५ साल के अन्दर

[श्री नवलकिशोर]

इतने प्रदेश में हर जगह बिजली भेजी जा सके। इसके अलावा आपने जो घोषणा की कि जो नये उद्योग धंधे खोले जायेंगे उनको सस्ती कीमत पर बिजली देंगे। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं। आपने उद्योगीकरण की ओर अच्छा कदम उठाया है। आपकी घोषणा यह भी है कि आप कई हजार गांवों को बिजली देने जा रहे हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं।

एक दो बातें मुझे और कहनी हैं। आप का बड़ा प्रोजेक्ट रिहन्द डैम का मिर्जापुर में बन रहा है और आशा की जाती है कि वह १९६१ तक तैयार हो जायगा। आप जमुना प्रोजेक्ट भी लेने वाले हैं। लेकिन एक बात अर्ज करना है कि आप इस बात की कोशिश करें कि जो आपका टाइम शिडयूल है वह मेनटेन हो सके तो अच्छा है, क्योंकि इस से दो फायदें होंगे। एक तो वक्त पर बिजली मिल जायगी और दूसरे आमदनी होनी शुरू हो जायगी।

दूसरी बात रेट्स के बाबत यहां कही गयी है। अच्छा तो यह है कि सारे प्रान्त में एक ही रेट हो जाय। हालांकि आपको कठिनाई है, क्योंकि हर जगह उत्पादन का खर्च अलग-अलग है। इसलिए दिक्कत पड़ती है। लेकिन फिर भी, यदि एक हो सके, तो अच्छा है। तीसरी बात यह है कि १९४६ की बिजली के लिए ऐप्लिकेशन पड़ी हुई है, लेकिन लोगों को बिजली नहीं मिली है। इसलिए जिस समय आप बिजली दें, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जिनकी दरख्वास्त पड़ी हुई है, उनको प्रायरिटी दे दें, तो मेहरबानी होगी। मैं फिर वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अनुदान पर वाद-विवाद होता रहा है और जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि इधर काम हुआ है और लोगों ने भी मन्त्री जी को धन्यवाद दिया है। लेकिन शिवनारायण जी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि गढ़वाल में बिजली नहीं दी गयी और अछूत रह गये, यानी वह भी हरिजन हो गये। यह प्रसन्नता की बात है, क्योंकि हरिजन होना कोई पाप की बात नहीं है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि शायद उनका मतलब गढ़वाल के लोगों से नहीं है। वह लोग जैसा कि रावत जी ने कहा चापलूसी करना नहीं जानते हैं। आप देखेंगे कि उनका कैरेक्टरिस्टिक है। वह बोर्डर पर रहते हैं और सोल्जर टाइप होते हैं। वह सीधे सादे ढंग से अपनी बात कह देते हैं। इस युग में जैसा कि आपने कहा कि इस तरह से सरकार को कहना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो उनका कैरेक्टर होगा, उसको वह मेनटेन करेंगे। गढ़वाल ने बड़ी सेवा की है और भविष्य में भी करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके द्वारा इस सरकार से और माननीय सदस्यों के सामने कहना चाहता हूं। गढ़वाल के बारे में और ज्यादा कहना उपयुक्त नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि जब आप उद्योगों को स्थापित करेंगे तो यह देखना होगा कि रा मैटीरियल्स कहां मिलता है और कौन से एरिया है, जो स्केअरसिटी एरिया है और जहां पर डेवेलप्मेंट होना आवश्यक है और रा मैटीयिरल्स मिल सकता है। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि रानीखेत में ट्रांस्मिशन लाइन लगी है। आपने देखा होगा और हम भी देख रहे हैं कि जो काम होता है, वह सब देखते हैं। जो काम करते हैं वह तारीफ की बात है, लेकिन अगर उद्योगीकरण करना है, तो हमें यह देखना होगा कि कहां रा मैटीयिरल्स के रिसोर्सेज हैं और कहां स्केअरसिटी एरियाज है, तो उसके मुताबिक भी एलाटमेंट आफ फन्डस हुआ करता है। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहूं कि गढ़वाल के पीछे की तरफ तिब्बत में चीन सरकार ने काफी एलेक्ट्रिफिकेशन योजना बनायी है, तो वहां पर कोटद्वार से भी दूर तक दो सौ, ढाई सौ मील तक लाइन ले जाना पड़ेगा अगर उस एरिया को आप एलेक्ट्रफाइ करना चाहें। मैं कहूंगा कि इसकी क्या आवश्यकता है, जब कि वहां पर्याप्त पानी है, छोटे-छोटे पहाड़ों में और उसका उपयोग किया जा सकता है? एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां जब इन्डस्ट्रीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बजट चल रहा था तो उद्योग मन्त्री जी ने कहा था कि उनका जो ज्योलोजिकल सर्वे का विभाग है, उन्होंने गढ़वाल के एरिया में जो केदारनाथ के करीब पड़ता है, पता लगाया है कि वहां तांबे की खानें हैं और वहां ड्रिलिंग होगी। तो बिना पावर के तो वह काम नहीं हो सकता। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि रोप लाइन लगाने की बड़ी आवश्यकता है, ताकि चीप ट्रांस्पोर्टेशन हो। तो इसके बारे में मैं बतलाऊं कि जब मैं कोटद्वार स्टेशन पर आता हूं तो बस चार्जेज १२, १३ रुपये देने पड़ते हैं और वहां से जब नीचे आता हूं यहां सात आठ जिलों को पार करके तो मुझे आठ रुपये कुछ आने देने पड़ते हैं। तो तहसील के एक कोने पर जाने पर मुझे १२, १४ रुपये पड़ें, और इतनी दूर आने के लिए कम, यह सोचने की बात है। इस प्रकार आप सोचें, कि बद्रीनाथ जी को जो सीमेंट जायगी, उसकी क्या कीमत पड़ेगी, जो चीनी जायगी उसकी क्या कीमत पड़ेगी, जो वहां अनाज जाता है, वह क्या भाव पड़ता है? आज चीनी वहां ६० रुपये मन बिकती है। वहां की अगर इन सब बातों को देख कर रावत जी ने गुस्से में वह बातें कह दीं तो मैं माननीय शिवनारायण जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने वहां के लोगों की भावना को ही व्यक्त किया है। वह स्केअरसिटी एरियाज और बार्डर एरियाज, जहां अनाज पैदा नहीं होता है, वहां के लिए अगर आप एलाटमेंट आफ फन्ड्स करते हैं तो वह जरूरी है, और होना ही चाहिए। बिजली की वहां बड़ी आवश्यकता है। अगर मैं पिछले सालों की प्रोसीडिंग्स की तरफ माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाऊं तो वह कहेंगे कि पिछली बातें कहता है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा, अपने इन्जीनियरों को भेजूंगा कि वहां लाइन जा सकती है या नहीं। तो मैं उनको फिर यहां दोहराना नहीं चाहता।

इसके अलावा लेबर के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं और यह कहा गया कि यह सोशलिस्ट सरकार है। लेबर के विषय में कानपुर के सदस्य श्री अवस्थी महोदय ने कहा और शाहजहांपुर की बात कही गयी कि लेबर की हड़तालें होती हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती और उनकी जायज डिमांड भी पूरी नहीं होतीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको अपने कन्ट्रोल में नहीं ले आ पाती और उस के द्वारा लेबर की डिमांड पूरी नहीं करा पाती या इस बिजली को पब्लिक सेक्टर में ला नहीं पाती, उस समय तक कम से कम इन गरीब मजदूरों की डिमांड को उसको पूरी करवाना ही चाहिए। अगर मार्टिन कम्पनी का कन्ट्रैक्ट है और ३५ वर्ष तक उसको जब्त नहीं करना चाहते हैं तो लेबर को आवश्यक सुविधायें तो सरकार को दिलानी ही चाहिए।

इसके बाद बहुत सी बातें देहात के बारे में कही गयीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार देहात में बिजली देने जा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सरकार का ध्यान ज्यादा शहरों की तरफ ही है, और देहात की तरफ कम है। इसलिए यह आवश्यक है खास कर जब कि ९ फी सैकड़ा आदमी शहरों में रहते हैं और बाकी उत्तर प्रदेश में आबादी देहातों में हैं, जब तक देहातों में आप बिजलीकरण न करेंगे, और लोगों को सस्ती बिजली न देंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

रेट की बात भी हुई कि एक फ्लैट रेट हो और एक रेट से सब लोगों को बिजली का सुभीता दिया जाय। यह कौन सी बात है कि एक रेट कहीं हो और दूसरा रेट कहीं हो? इसमें तो सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक बात अवश्य कहूंगा कि जो स्केअरसिटी एरियाज हैं या जो बार्डर एरियाज हैं और खासकर जहां मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स नहीं हैं और जहां अन्न का उत्पादन नहीं होता है, उन लोगों की मांग इस बिजली के लिए जायज है और वह मांग पूरी होनी चाहिए। उपाध्याय जी ने भी उसका समर्थन किया है और रावत जी तो

[श्री गंगाधर मैठाणी]

प्रतिवर्ष कहते रहते हैं। अगर मेरी बात पर वह कह दें कि मैं विरोधी दल से खड़ा हुआ हूं और मेरा काम माननीय वित्त मन्त्री जी की बातों को क्रिटिसाइज करना ही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बात नहीं है। हमारे रावत जी उनके दल के सदस्य हैं। वह इस सदन में यह कहते रहते हैं और परिपूर्णानन्द जी भी हर समय वित्त मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करते रहते हैं और अपने आंकड़े भी पेश करते रहते हैं। मैं उनके लिए बहुत से आंकड़े लाया था कि उनके सामने रखूंगा। लेकिन अब तो मैं अपने आंकड़ों को पेश करना उचित नहीं समझता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन फिर सदन के सामने रखता हूं।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मेम्बरों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज की बहस में बिजली के मुहकमे के काम की कदर की और मुबारकबाद दिया। मेरे लिए और मुहकमे के लिए यह बात बहुत खुशकिस्मती की है। जो बातें यहां पर कही गयीं, उनके लिए गालिबन इतना वक्त नहीं है कि उन सबका जवाब दिया जा सके। इसलिए मैं चन्द बातों का जवाब हाउस के सामने रखूंगा। उनमें से पहले गढ़वाल की बाबत अर्ज किया चाहता हूं।

मुझको अफसोस इस बात का नहीं कि मेरे भाई रावत जी ने इस किस्म की तकरीर की। मुझको इसका अहसास है कि उनके दिल में एक दर्द है और उनका दिल दुखी हुआ है, उसकी वजह उसे उन्होंने अपने उस इलाके की मांग को जोर के साथ इस सदन के सामने रखना जरूरी समझा। मेरे नजदीक यह कुछ अनुचित बात नहीं है। मगर मैं जनाबवाला के जरिये से अपने भाई रावत जी और उन सबसे जिन्होंने गढ़वाल की तरफ से इस वक्त कुछ यहां पर कहा, यह बतलाना चाहता हूं कि बावजूद इस के कि इस बजट में, जिस पर यह बहस है, किसी को किसी जगह पर यह लिखा हुआ नहीं मिला है कि कोटद्वार में बिजली इस साल के अन्दर लगेगी जिस साल का यह बजट है या और जगहों में लगेगी, जिनका नाम इसमें दिया हुआ हो, लेकिन १९५६–५७ में कोटद्वार, दुगड्डा और पौड़ी में यकीनन बिजली लग जायगी। उसके लिए मैं हुकुम जारी कर चुका हूं और उनका काम ऐक्टिव तौर पर लिया जाना शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि मेरी बदकिस्मती थी, मैं इसको गढ़वाल की बदकिस्मती नहीं कहूंगा या अपने दोस्त के मुताल्लिक कुछ नहीं कहूंगा। बल्कि उसको मैं अपनी ही बदकिस्मती करार देता हूं कि गढ़वाल के मुताल्लिक मैंने जितनी कोशिश की और जितनी तवज्जह बिजली देने के लिए जब से यह काम मेरे हाथ में था, उस वक्त से आज तक की, मैं आपके जरिये से, यह मेम्बरों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी और जगह के लिए मैंने नहीं की। लेकिन बदकिस्मती से बावजूद उस कोशिश के मैं कामयाब नहीं हुआ। यह मालूम है कि नयार डाम की तहकीकात मैंने करायी, कितनी ही दफा मैं उस इलाके में गया, जहां पर कि वह नयार डाम बनने वाला था और उस तहकीकात में खुद शिरकत की जो कि उस के मुताल्लिक हो रही थी। एकाध उसमें ऐसे नुक्स निकले, एक्सपर्ट ने उसको एक्जामिन किया कि जिनकी बिना पर उस वक्त उस स्कीम को उस जगह के ऊपर ठहरा देना पड़ा। हमने नयार डाम को छोड़ नहीं दिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उसे शरीक करके प्लानिंग कमीशन को भेजा। ४९ करोड़ उसका खर्चा है। वहां जो उस पर बहसें हुईं तो आखिर प्लानिंग कमीशन ने यह तय किया कि इस डैम को इस योजना में न लिया जाय। मैंने उनसे बहुत कुछ कहा मगर उन्होंने मजबूरी जाहिर की। तब मैंने कहा कि अच्छा चूंकि वहां के लोगों को बिजली की बहुत जरूरत है तो आप वहां के लिए कम से कम एक स्टीम स्टेशन ३० हजार कीलोवाट का इसमें शामिल कर दें। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि वह मंजूर हुआ या नहीं, बल्कि अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि वह मिल जाय। लेकिन दूसरी तरफ मैंने सोचा कि नयार डाम अभी नहीं बन सकता, तो कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने फैसला किया कि कोटद्वार, दुगड्डा और पौड़ी को बिजली अब देनी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––डीजेल से देंगे क्या ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मेम्बरान बीच में न बोलेंगे तो पूरी बात उनकी समझ में आजावेगी। मैं अपनी बात वही कहूंगा जहां मेरे लिए फिट बैठेगी। एक मुस्तकिल डिवीजन रखकर हमने इस बात की तहकीकात करायी कि गढ़वाल में कोई ऐसी जगह है जहां हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्टेशन बन सकता हो। मगर हो सकता है कि मेरी बदकिस्मती से उन लोगों ने ठीक काम न किया हो, लेकिन उनकी रिपोर्ट यह आयी कि वहां कोई ऐसी जगह नहीं है सिवाय उस नयार डाम के।

श्री गंगाधर मैठाणी––पिन्डर नदी से बिजली बन सकती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––जरा सुनें तो सही। वहां नहीं बन सकती है। आपने उतनी गढ़वाल स्टेट नहीं देखी, जितनी मैंने देख रखी है। वहां एक जगह तिनावली है जिसके बारे में उन्होंने मुझे बतलाया कि वहां बन सकती है। चुनांचे मैंने उसके हाइड्रो एलेक्ट्रिक स्टेशन की तहकीकात का काम जारी करा रखा है। जहां तक बजट में रुपया रखने की बात है, मंजूर शुदा स्कीमों में उसका नाम है और उसके अलावा और भी रुपया हमारे पास है। हमने मसलन कहा कि ३०० या २०० गावों में बिजली देनी है। तो हम और भी रुपया रखते हैं और तहकीकात का सिलसिला जारी रहता है। कोटद्वार के ऊपर तो बिजली पथरी के पावर स्टेशन से जा रही है, दुगड्डा और पौड़ी में आयल से हम बिजली बना रहे हैं। पौड़ी के ऊपर पावर स्टेशन बनेगा। मैं समझता हूं कि वह मायूस नहीं रहेंगे मगर वह तो रहेंगे ही। लेकिन दुनिया देख लेगी कि ५६–५७ में वहां बिजली आ गयी है या नहीं ?

श्री चन्द्र सिंह रावत––कोटद्वार में पानी नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मैं सक्का नहीं हूं। मेरे पास तो बिजली है। नवलकिशोर साहब ने कहा कि सन् ४६ की अर्जियों को प्रिफरेंस देना चाहिए। मगर मैं उन की खिदमत में अर्ज कर दूं कि जब मुहम्मदपुर का पावर स्टेशन बन गया तो बिजली बांटने के समय एक इस ऐवान की कमेटी बनी, यहां के मेम्बरों की, जिसने यह सिफारिश की कि फिर से नयी दरख्वास्तें मंगायी जावें और उसके मुताबिक अमल किया जाय। चुनांचे लाखों दरख्वास्तें आयीं और उनमें उन पुराने लोगों की भी थीं। यह हमने अखबारों में इसके बारे में दे दिया था। पुराने लोगों को भी बिजली मिली। एक भाई ने लेबर की बाबत कहा। अगर वह यह बात लेबर के बजट में कहते तो ज्यादा मौजूं होती। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं बतलाता हूं कि शाहजहांपुर के पावर स्टेशन का मामला एक लाइसेंसी और मजदूरों के दरमियान है। मगर हम उसमें जरूर यह कोशिश कर रहे हैं कि वह तय हो जाय और उम्मीद है कि एक या दो दिन में तय हो जायगा। "कैसा" के बारे में उनकी जो मांगे हैं, उनके बारे में यह हो सकता है कि उनको अगले हफ्ते में या १०, १५ दिन में गौर करके फैसला कर लिया जाय। मुझे उस में देर लगाने में कोई खुशी नहीं है।

एक बात कही गयी है कि बिजली की कीमत मुख्तलिफ हैं। इसकी मुख्तालिफत नहीं होनी चाहिये। हो सकता है इतनी वाकफियत या मालूमात मुझको न हों, लेकिन इतनी बड़ी स्टेट के अन्दर बिजली की कीमत का एक होना मुमकिन है या नहीं। खुद अपनी जगह पर यह मसला गौरतलब है, फर्क इसलिए होता है कि बिजली जहां बनती है और जिस तरीके से बनती है उसकी वजह से फर्क पैदा होता है। अब मान लीजिये स्टीम ऐंजिन से बिजली तैयार की गई। एक लखनऊ में की गयी और दूसरी १०–१५ हजार की आबादी वाले कस्बे में की गयी। तो जहां बिजली कम बनेगी वहां खर्चा उसका

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

औसत ज्यादा आयेगा और जहां प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होगी। इसी वजह से जितनी लाइसेंसीज हमारी स्टेट में काम कर रहे हैं उनके रेट्स में अन्तर नजर आता है और इसकी वजह यही है, जो अभी मैंने बतलायी। इसी वजह से कहीं साढ़े तीन आने हैं, कहीं ४ आने, कहीं ५ आने, कहीं ६ आने, तो कहीं ९ आने। अब जहां तक उस को बलदने का सवाल है, उसके लिये मैं बतला चुका हूं कि कानून मौजूद है, वह केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ है और उसी के मुताबिक हमें किसी लाइसेंसी के रेट्स घटाये जाने का हक़ हासिल है। रेट को जो जांच करने के लिये कमेटी बिठाई जाती है, वह जांच कर के यह बतला देती है कि वह रेट ज्यादा है या नहीं, तब वह रिकमन्ड करती है।

बाराबंकी की बात भी कही गयी। अगर बाराबंकी वाले वे माननीय सदस्य होते तो उसके सामने यह बात हो जाती। लेकिन और साहबान भी समझ लें इस वजह से उसको बता देना चाहता हूं। दूसरे साहबान भी उससे सबक ले सकते हैं। बाराबंकी में एक लाइसेंसी ने लाइसेंस लेकर बिजली सप्लाई करना शुरू किया और उसने ६ आने के हिसाब से बिजली बेचना शुरू किया। बाराबंकी के साहबान ने कंज्यूमर सोसाइटी के नाम से मेरे ऊपर जोर डालना शुरू किया कि इसकी कीमत को घटाया जाय। मैंने कहा कि कानून में मुझे कोई अख्तियार इस बात का नहीं है। इसके लिये कमेटी बैठानी होगी। मैंने उनको हिसाब समझाया और बताया कि उसके हिसाब से घटा नहीं सकते। चुनांचे उन्होंने उसको भी नहीं माना और कमेटी-बैठाये जाने के लिये मजबूर किया। कमेटी बैठी। कमेटी की रिपोर्ट यह आयी कि रेट १२ आना से कम नहीं होना चाहिये। अब मैं उस लाइसेंसी को १२ आना लेने से नहीं रोक सकता और अब १२ आना कीमत दी जा रही है। अब जहां तक सरकार की बनायी हुई बिजली का तल्लुक है, उसके मुताबिक अर्ज यह है कि वह भी पावर स्टेशन पर मुन्हसिर करती है कि किस जगह वह बिजली बनती है। हर पावर स्टेशन की जनरेशन कास्ट मुख्तलिफ होंगी। हाइडिल में हमने मुख्तलिफ़ पावर स्टेशन की बिजली की क़ीमत जरूर एक कर रक्खी है। जब खटीमा पावर स्टेशन बना तो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा बैठी। लेकिन फिर भी हमने यह कोशिश की कि वहां भी वही रेट रक्खा जाय जो दूसरी जगह पर बिजली का है। इसलिये जहां तक सरकार की बिजली का तल्लुक है हमने यह कोशिश की है कि जहां तक हो सके रेट्स यूनीफार्म रक्खे जायं, लेकिन अब लाइसेंसीज पर यह चीज लागू नहीं होती। सब जगह एक सी क़ीमत हो जाय, मेरे ख्याल से यह नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है, मेरे जमाने तक यह क़ीमत नहीं हो सकती। किसी जमाने में कोई खुशकिस्मत मिनिस्टर यहां आये और आप का यह काम पूरा करें। हां, मैं काग़जात में यह लिखता चला जाऊंगा कि मेरे जमाने में लेजिस्लेचर की यह राय थी कि क़ीमत को कम कर दिया जाय। लेकिन मेरे लिये कम करना मुमकिन नहीं है।

एक बात और राष्ट्रीयकरण की कही गयी। मैं तो चाहता हूं अगर मुमकिन हो तो सारी बिजली सरकार की हो जाय, तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इस मामले में एक चीज को नजर के सामने रखना चाहिये कि हमने अपना एक संविधान बनाया है, उस से चाहे हममें से किसी एक आदमी को इखतलाफ हो लेकिन हमारे जो मुल्क का संविधान है, उसमें लिखा है कि जब हम किसी का कुछ लेंगे तो उसको कुछ देंगे और मुफ्त किसी का कुछ नहीं छीनेंगे। इसलिये जब हम बिजली वालों का राष्ट्रीकरण करें तो उस के लिये हमें पहले से रुपया भी चाहिये। तो एक तरफ तो वह कह रहे थे कि हमें बिजली की जरूरत है और वह ठीक ही कह रहे थे, मसलन बिजली की इतनी जरूरत है कि मेरे नजदीक आज जो बिजली है वह जरूरत का दसवां या बीसवां हिस्सा भी नहीं है, जो कि हमने बना लिया है। हम तो इसी से मुकाबला कर सकते हैं कि सन् ४६ से पहले हमारे यहां कितनी बिजली थी और अब कितनी है, पहले के बारे में मुकाबला करना बेकार है, लेकिन हमने जितनी बिजली सन् १९४६

से आज तक पैदा की है उसका मुकाबला आप बंगाल से या मद्रास से कर लीजिए, कि क्या काम यहां हुआ है हमारे यू० पी में। लेकिन कोई यह कहे कि पहले से ही किसी के पास बिजली ज्यादा थी। और हम एक दम से उनके बराबर पहुंच जायं, तो उसके लिये हमें अभी टाइम लगेगा, और तब तक वह भी और आगे बढ़ेंगे। तो जहां तक राष्ट्रीकरण की बात है उस में अभी वक्त लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में वह होगा, जिस कम्पनी की मियाद गुजरती जायगी तो उसकी जगह फिर कोई शायद ही लाइसेंस पाये, मिलेगा ही नहीं। हमारे माननीय दोस्त जो बाराबंकी से नये आये हैं उन्होंने इस नजर से देखा कि गोया इस मुल्क में सोशलिस्टिक पेटर्न पहले से ही कायम है। वह तो हमने अभी २ साल हुए शुरू किया है लेकिन उन्होंने सारी दुनिया की पुरानी चीजें कह डालीं।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

हम तो अपने पुराने घर को ही भला बना रहे हैं अगर उसको तोड़ डालें तो वह भी खत्म हो जायगा। हम तो आहिस्ता-आहिस्ता सोशलिस्टिक पेटर्न को अब लाना चाहते हैं। बस अब वक्त खत्म हो गया।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४–लेखा शीर्षक ४१, के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४––विद्युत् योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक : ४१) के अन्तर्गत २,४८,४२,६०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५––लेखा शीर्षक ४१ और ८१––क के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५––विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ४१ और ८१––क के अन्तर्गत १,३५,०४,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७–लेखा शीर्षक ८१–क के अधीन १ रुपए की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७––विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर) (लेखा शीर्षक ८१–क) के अन्तर्गत १३,२०,४७,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

श्री धर्मसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--व्याज वाले ऋण और अग्रऋण (लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण) के अन्तर्गत ९,५२,१४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इसमें मुझे अधिक कुछ भी नहीं कहना है । इसमें बहुत सी सूरतें हैं जिस पर पैसा दिया जायगा । इसका ब्योरा बजट में है।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। इस अनुदान में कुल ९ करोड रुपये और कुछ के लगभग रखा गया है । इसमें १ करोड़ ७३ लाख रुपये तकावी पर , कुछ रुपये ऋणों पर और बाक़ी ५ करोड और कुछ रुपये विकास योजनाओं के लिये निर्दिष्ट किये गये हैं । सब से पहले मैं किसानों को ऋण और तकावी वगैरह में जो ऋण दिया जाता है उस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । तकावी विभिन्न जिलों में इस प्रकार से दी जाती है जैसे बनारस के कुछ हिस्सों में कुएं के लिये १,५०० रु०, आजमगढ़ में ४०० रु०, प्रतापगढ़ में २०० रुपये--इस तरह से विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार से तकावी दी जाती हैं। तकावी किसान लोग ऋण के रूप में लेते हैं, लेकिन तकावी मिलने का जो तरीका है --बार-बार कई वर्ष से मेरा खयाल है इस सदन में लोगों ने जोर दिया कि तकावी के मिलने में लोगों को कितनी दिक्कत होती है, किस तरह से कर्मचारी लोग परेशान करते हैं वह सब को विदित है। बार-बार नारा लगाया गया कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग बेहतर इन्तजाम कर रहे हैं, लेकिन किसान बेचारा उसी तरह से परेशान है । दूसरे कर्मचारियों और नीचे के पब्लिक के कुछ लोगों में एक एजेंसी सी कायम हो गई है और कुछ परसेंट काट कर तब तकावी किसानों को दी जाती है और इस तरह से वह परेशान किया जा रहा है । इसीलिये तकावी लेने से बहुत से किसान भाग जाते हैं। इसी वजह से हमने देखा कि विकास योजनाओं में, जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वहां सिंचाई का काम बहुत आगे नहीं बढ़ा है । वह क्यों नहीं बढ़ा ? इसकी खास वजह यह है कि किसानों को जो तकावी दी जा रही है उसमें तरह-तरह की परेशानियां हैं, मैं जानता हूं कि एक हरिजन भाई को १०० रुपये तकावी दी गई और ५० रुपये तहसीलदार साहब ने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में काट लिये। इस तरह से तकावी दी जा रही है । कलेक्टरी से लेकर तहसील तक और गांव सभाओं तक जो कमीशन लगा हुआ है उससे किसान बहुत परेशान है । इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । यह करप्शन दूर होना चाहिये ।

दूसरे किसानों को जो तकावी दी जाती है उस पर साढ़े ५ फीसदी सूद लिया जाता है जब कि साढ़े चार फीसदी कोआपरेटिव से सूद लिया जाता है । तो तकावी का सूद बहुत अधिक है । सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

इसके बाद बोरिंग का मामला आता है और बोरिंग के लिये बहुत दिन से प्रयत्न हो रहा है । मेरा ख्याल है कि नलकूप और नहरों की वजह से इधर लोगों का ध्यान कम हो गया है और कुएं के लिये लोग तकावी बहुत कम लेने लगे हैं । चकबन्दी की वजह से भी क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता कि कुआं किस के चक में पड़े । इसलिये लोगों का उस ओर कम ध्यान है । लेकिन जो लोग तकावी लेने के लिये आवें उनको सुविधापूर्वक तकावी मिलनी चाहिये और उनको किसी प्रकार का घूस न देना पड़े, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये । किसान इस देश की रीढ़ है । जो सुविधा किसान को मिल रही है वह उसे आसानी के साथ मिलना चाहिये । तीसरी चीज जो है वह पम्पिंग

प्लांन्ट के सम्बन्ध में है। जब कभी सूखा पड़ जाता है और पानी निकालने के लिये पम्पिंग प्लान्ट की जरूरत होती है, तो चार रुपया फी घंटा क़ीमत देनी पड़ती है। एक तो उसका मिलना मुश्किल होता है, पम्पिंग प्लांट को जहां पर एग्रीकल्चरल स्टोर्स हैं वहां पर जल्दी पम्पिंग प्लांट मिलता नहीं है। जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हीं को जल्दी से मिल सकता है। लेकिन अगर मिल भी गया तो चार रुपये फी घंटा कीमत देनी पड़ती है। यह क़ीमत बहुत ज्यादा है। आसानी से पम्पिंग प्लांट्स मिल सकें और सस्ती क़ीमत पर मिल सकें, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

कुछ बात मुझे माननीय मंत्री जी से विविध ऋण जो यहां दिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना है। यह जो नया बजट का भाग विकास योजनाओं के सम्बन्ध में बना है उस में मैं पढ़ रहा था कि रामतीर्थ प्रतिष्ठान ने २० हजार रुपया मांगा है जो वह दस वर्षों में देना चाहते हैं। उस पर भी जब पांच प्रतिशत व्याज देंगे तब वह रुपया दिया जायगा। मेरा ख्याल है कि वहां इस देश में सारनाथ और अन्य स्थानों में बुद्ध शताब्दी के मनाने के लिये इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, इतना रुपया खर्च किया जा रहा है तो स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ जैसे जो हमारे देश के रहनुमा थे जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया, नौजवानों को अनुप्राणित किया था उनके लिये कोई प्रतिष्ठान संस्था उनके लेखों को प्रकाशित करना चाहती है और उसके साथ यह शर्त है कि उस से जो मुनाफा होगा, वह सारा का सारा प्रशासन में लगेगा तो उनको बिना सूद के रुपया देना चाहिए।

सब से बड़ी योजना जो विकास योजना है, उस पर पांच करोड़ से ऊपर रुपया खर्च हो रहा है। इस योजना में जो सबसे बड़ी रक़म है वह ३ करोड़ ७० लाख रुपये के करीब है, जो कि राजकीय उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये है, । इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि २५ प्रतिशत बिजली की दरों में कमी की जायगी। लेकिन अभी से जो मैंने उसमें पढ़ा, उद्योगपतियों की खोज होने लगी है कि वह लोग तैयार हों और नये उद्योग खोलें। मेरा कहना यह है कि गृह-उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये और जो बिजली मिले उसको उस में खर्च करना चाहिये और कम से कम कीमत पर जहां तक हो सके, बिजली देना चाहिये। इसमें से रुपया अधिकांश लोगों को उद्योग के लिये दिया जा रहा है और उस में लिखा हुआ है कि कितना रुपया व्यक्तिगत लोगों को दिया जायगा, यह तय नहीं है। अगर मालूम हो जाता कि किस हिसाब से ऋण मिलेगा, तो बहुत से लोग तैयार हो जाते और व्यक्तिगत उद्योग खोलते। मेरा ख्याल है कि इस मद का जितना रुपया है गृह-उद्योगों के लिए खर्च करना चाहिये। कुछ रुपया इसमें गुड़ विस्तार योजना के लिये भी दिया गया है। गुड़ का धंधा हमारे देश में बहुत पुराना है। हमारे देश में काफी गुड़ पैदा भी होता है। इस गुड़ के और खांडसारी के उद्योग को काफी ऋण दे कर आगे बढ़ाना चाहिये। कल जैसे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की ओर से मार्केटिंग फेडरेशन और कुछ गोदाम वगैरह खोलने की योजना पर रुपया मंजूर हुआ, वह गुड़ के लिये भी होना चाहिये और गुड़ गोदामों में रख कर जो गुड़ किसानों का तैयार होता है, उसको अच्छी कीमत पर खरीदना चाहिये ताकि व्यापारियों और मनीलेंडर्स के हाथ न बिक कर उनको अधिक दाम मिले और जितना पैसा हो सके वह इसके लिये देना चाहिए।

एक और मद जो है उस में गृह-निर्माण के लिये खासतौर से रक़म रखी गयी है। जो कम आय वाले नौकर लोग हैं उनको इसमें से कर्जा दिया जायगा। यह बड़ी अच्छी बात है। कर्जा देना चाहिये। लेकिन कर्जा ऐसे लोगों को ही मिलेगा जो छः हजार से अधिक आय वाले नहीं हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि सब से कम इनकम वालों की तरफ ध्यान अधिक होना चाहिये। कई स्थानों पर मेहतरों और दूसरे लोगों के लिए नगरपालिकाओं में कम हुए हैं। और जगह भी होना चाहिये। आजमगढ़ नगरपालिका

[श्री विश्राम राय]

को कुछ धन दिया गया है । वहां मैंने देखा कि वहां मार्केट बनायी गयी । वहां मार्केट में घरों के देने का जो रेट है वह बहुत ज्यादा है । शहर लखनऊ में भी विस्थापितों के के लिये मकान बने हैं । यहां भी वही निकालना और ज्यादा किराया लेने की बात जारी है । तो जो इस के लिये क्वार्टर वगैरह बनाये जा रहे हैं वे वाजिब किराये पर मिलने चाहिए ताकि जिस काम के लिये गवर्नमेंट ने यह रुपया दिया है, करोड़ों रुपया दे रही है, उस काम के लिये जो नीचे की श्रेणी की जनता है, जो दबी हुई जनता है, जिसके लिए मकानों की व्यवस्था नहीं हो सकती ताकि उससे वह लोग फ़ायदा उठा सकें और रक़म जो ऋण में दी जाती है ५ हजार रुपया अधिक से अधिक दिया जा रहा है, इसके लिये अच्छे से अच्छा इन्तजाम हो ।

एक और जो इंतजाम हो रहा है वह है जल-निकासी, और शौचालय वगैरह के सम्बन्ध में बहुत कुछ रुपया रखा गया है और यह अच्छी बात है । लेकिन इसमें देहातों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये । अब तक ७२ नगर हैं जहां पर जल-निकासी की योजना कामयाब नहीं हो सकी हैं तो इस तरफ़ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये । और सीवेज सिस्टम की जानकारी की लोगो को ट्रेनिंग दे करके रखना चाहिये नहीं तो बहुत बड़ी बीमारियां फैलती हैं, गांवों की हालत इस सम्बन्ध में बहुद ख़राब है । महा-मारी आदि प्रकोप बहुत फैल जाते हैं । बाढ़-इलाके जो हैं वहां पर अक्सर महामारी फैला करती है और बाढ़ के वक्त कोई ऐसा काम वहां नहीं हो पाता जिससे स्वच्छ पानी और शौंच का काम चल सके । बाढ़-इलाके और जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर खास तौर से ध्यान देना चाहिये । देहातों मे शौचालयों का प्रबन्ध करना चाहिये । टीका लगाने और रोकथाम तथा दवाइयों का अधिक काम होना चाहिये तथा शौचालय बनाये जाने चाहिये । मैं तो आजमगढ़ में जिस मुहल्ले में रहता हूं वहां पर स्त्रियों के लिये शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है । अभी बहुत कमी है । जो आंकड़े दिये गये हैं वह बड़े जरूरी हैं लेकिन फिर भी आवश्यकता को देखते हुये बहुत बड़ी कमी है । इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

*श्री अवधेश प्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, इस तकावी के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जितनी भी तकावी इस प्रदेशीय सरकार द्वारा दी जाती है उसकी प्राप्ति में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वास्तविकता तो यह है कि जिसको तकावी की जरूरत है वह नियमों से पीड़ित हो कर, हमने देखा कि इन नियमों की कठिनाइयों का सामना करने का साहस न रख कर, वह तकावी नहीं लेता है । यदि उसने साहस किया जिसको मैं साहस कहूं और वह लेखपाल महोदय तक पहुंचा तो पहले नजराना लेख-पाल महोदय का जरूरी है । उसके बाद अगर तहसील में पहुंचता है तो वासिलबाकी नवीस महोदय हाजिर हैं । तो नतीजा यह होता है कि तकावी की उम्मीद नहीं पायी जाती मैं श्रीमन्, यह नहीं कहता कि हर जगह ऐसा है लेकिन अधिकांश में यही परिस्थिति है । श्रीमन्, उनके लिये जो तकावी लेने जायं जिनको कुछ ही समय के बाद वापस करना है और सूद के साथ तो यह क्यों रखा जाय कि जो कुछ वह पाता हो उसका आधा दूसरों की जेब में जाय ? इस प्रकार के नियमों से मैं समझता हूं कोई फायदा नहीं और जो परपज है तकावी का वही डिफीट होता है । यह व्यवस्था अनुचित है । यही नहीं श्रीमन्, यहां पर देखा गया है कि यह तो तकावी है बल्कि सरकार की तरफ से जहां मुफत बांटा जाता है उस जगह भी इस तरह की हरकतें हुआ करती हैं और आपने यह देखा है कि बहुत से जिलों में जिन चीजों की जरूरत है और जिसके लिये तकावी होनी चाहिये और उसके लिये हर प्रकार की सहायता देना सरकार द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वांछनीय है। देखा यह जाता है कि उन जिलों में वह चीज नहीं पायी जाती है। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां ट्यूबवेल हैं या नहरे हैं। उस जगह अगर आप सिंचाई के लिये तकावी देते हैं तो यह लाजिमी है कि वह रुपया न उठ पावेगा। लेकिन बहुत से जिले हैं, मैं उदाहरण के लिये बतलाये दे रहा हूं फैजाबाद है, जिसके लिये आज तक कोई तकावी का प्रावीजन नहीं है। मान्यवर, उस जिले में मंत्री जी ध्यान से सुने लें और नोट कर लें और देखें कि आज भी तकावी के लिये कोई प्रावीजन नहीं है और लोगों के लिये मजबूरी है। जिले में अगर वह ट्रैक्टर से काम लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं जब तक स्वयं उनके पास ट्रैक्टर न हो।

श्रीमन्, यह नहीं, देखा यह गया है आज भी आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसान के लिये सही मुसीबत क्या है। वह यह है कि देहातों में हर जगह बहुत थोड़ी सी तादाद ऐसी है जो कि भूमिधर हो पाये हैं। बकिया लोग सीरदार हैं और जब तकावी के लिये वह जाते हैं तो उस सीरदारी की मालियत जो है वह सिर्फ दस गुना लगायी जाती है नतीजा यह है कि एक तो आराजी कम, खेत उनके पास कम, दूसरी मुसीबत यह कि उसकी मालियत जो है वह दसगुनी है जब कि भूमिधरी की मालियत ६० गुनी लगायी जाती है। लिहाजा अगर माल मंत्री महोदय, उसको बढ़ायें, तकावी रूल्स में संशोधन किया जाय तो यह आसानी होगी कि गरीब किसान जो कि अभी नहीं तकावी पा सकते हैं, उनको मिल सकेगी और दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान के होते हुए यह जब हम कहते हैं कि किसी तरह का भेदभाव नहीं इस प्रदेश में, तो आश्चर्य के साथ यह देखना पड़ता है कि एक्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स से हर जिलाधीश के पास या तहसीलदारों या डिप्टी कलेक्टरों के पास इस तरह के इंस्ट्रक्शन्स दे दिये जाते हैं या माननीय मंत्री महोदय, दौरे पर गए तो उनसे कह दिया कि इसमें यह देखो कि छोटों को दे दो, बड़ों को मत दो। श्रीमन्, हम चाहते हैं कि छोटों और बड़ों का सवाल ही न पैदा हो और यदि पैदा भी हो तो मैं देखता हूं कि भारतीय संविधान के होते हुए आप यह अनर्थ कर रहे हैं। एक तरफ जब यह कह दिया कि भेदभाव हमारे देश में नहीं है तो यह छोटे और बड़े का भेदभाव क्यों? अब वह जिनको आप बड़े कहते हैं रह कितने गए हैं? पूंजीपति अपने को भले ही बड़े कहला लें लेकिन और श्रीमन्, देहातों में कोई बड़ा अब नहीं है। परिस्थिति तो श्रीमान्, यह है आपके द्वारा अर्ज करूंगा जनाबवाला गौर करें कि तकावी उनको दी जाय कि जिनको जरूरत है। अगर आप बड़े छोटे के पैमाने से देखेंगे तो कोई न कोई तो दूसरे के मुकाबिले में छोटा या बड़ा निकल ही आयेगा। मैं आपको बताऊं पुराने जमीदारों को खाने के लाले हैं। पूंजीपति कानपुर में हैं, लखनऊ में हो सकते हैं, बनारस में हो सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में हो सकते हैं, देहातों में कहां हैं बड़े आदमी? अब तो एक तरफ जब सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की पुकार हो, जब आप यह कहते हों कि जमींदारी तोड़कर हमने बहुत हद तक वह लक्ष्य पूरा कर लिया तो दूसरी जगह यह छोटे बड़े की बात करना और यह चिल्लाना कहां तक उचित है? एक तरफ आपका यह कांस्टीट्यूशन है, एक तरफ आप दुनियां में चिल्लाते हैं कि हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं है और दूसरी तरफ कलेक्टरों को हिदायत देते हैं कि छोटों को दो और बड़ों को मत दो। आप सोचिए तो कि जहां पर आपके आर्डर्स जाते हैं कि छोटों को दे दो और बड़ों को मत दो तो यह कहां तक उचित है? आपके मिनिस्टर साहबान दौरे पर जाते हैं या कोई भी पहुंचा तो उनसे कहा कि छोटों को पहले दे दो तो यह चीज ठीक नहीं है। इस नुक्ते नजर से देखना चाहिये कि जिसको जिस चीज की

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

जरूरत हो वह उसको दी जाय। असल में देखने की बात यही है कि जिसको जरूरत हो उसको दी जाय। बहुत सी तकावियां ऐसी हैं कि जिन पर आप सूद लेते हैं, लेकिन जैसे फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको घर बनाने के लिए तकावी दें तो जब तक कि वह तकावी लांग रेंज की न हो और वह बिना सूद की न हो तब तक उसको वह ले नहीं सकते। अगर तीन साल के लिए उनको तकावी देते हैं और सूद लेते हैं तो वह क्या घर बनायेंगे, और क्या आपसे तकावी लेंगे? तीन साल तक तो वह सम्भल ही नहीं पायेंगे, इन सब चीजों को देखते हुए यह जो कि फल्ड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आज आप इसका खयाल रखें कि उनको जो तकावी मिलनी चाहिये वह तकावी इस शर्त पर मिलनी चाहिए कि लांग रेंज की हो। मुझे इसके मुताल्लिक एक बात और कह देनी है कि तकावी जो दी जाती है उसमें इस बात का खयाल रहे कि वह वक्त से दी जाये। आप अपनी तरफ से सब कुछ कर देते हैं लेकिन वहां नतीजा क्या होता है? किसान जब पहुंचता है तो उससे कह दिया जाता है कि अब दरख्वास्त की मियाद खत्म हो गई और तुमको तकावी नहीं मिल सकती। लिहाजा इसके लिये कुछ इंतजाम होना चाहिये और सबसे बड़ी बात श्रीमन्, यह है कि यहां बावजूद इसके कि तकावी रूल्स में संशोधन हुये हैं लेकिन वे भी काफी नहीं हैं। जब कि डेवलपमेंट करना है, जब कि विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना है तब इन नियमों के झगड़े में अधिक पड़ने से आप अधिक लाभ नहीं उठा सकते। नियमों में सरलता होनी चाहिये जिससे हर आदमी तक तकावी पहुंच सके। मुझे फैजाबाद के मुताल्लिक खास शिकायत थी जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। सरकार उस पर गौर करे। आज भी वहां ट्रैक्टर का कोई प्राविजन नहीं है। जिस चीज की जरूरत है उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है. और जिनके लिये जरूरत नहीं है वे मौजूद हैं। यह थोड़ी बातें थीं जिन्हें मुझे निवेदन करना था, मुझे उम्मीद है कि सरकार इन पर गौर करेगी।

श्री शिवनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो अनुदान तकावी का गरीबों को बांटने के लिये उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन के लिये उपस्थित हुआ हूं। माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी ने कहा कि गवर्नमेंट के ऐसे इंस्ट्रक्शन्स हैं कि बड़े लोगों को न दो और छोटे लोगों को दो, यह बात बिलकुल ठीक की गई है। अगर सब लोगों के लिये खुले आम हो जाय तो बड़े लोग निकाल लेते हैं और छोटे रह जाते हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा भी कि जब छोटे लोग पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि समय बीत गया। यह बात बिलकुल सही है हमारे यहां की एक मिसाल है। हमारे यहां मझौआलाला गांव के भग्गल चमार को तकावी मिलने को थी, जब वह तहसीलदार साहब के पास गया तो वे कहने लगे कि हां १० हजार रुपया आया था और १०,१० रुपये फी आदमी पड़ता है। तो इस देने और न देने से क्या फायदा? १० रुपया अगर किसी आदमी को मिलेगा तो क्या करेगा? १० रुपया उसके आने जाने में ही खर्च हो जायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुनासिब रुपया सौ, दो सौ दिया जाय जिससे कम से कम उसका छप्पर तो सीधा हो जाय। इसके अतिरिक्त आपके जो फार्म हैं वे इतने मुश्किल हैं कि किसान बेचारे तो क्या भर पावें उनसे मुख्तार और वकील दो, दो रुपया ले लेते हैं, उनके मुंशी दो एक रुपये ले लेते हैं। उसके भरवाने में और शिनाख्त करवाने में चार-चार और पांच-पांच रुपया उनका लग जाता है। इससे तो अच्छा है कि आप सीधे ही पटवारी के पास गांव में ही भेज दें वहां पटवारी उनसे सोलह आने ले ही तो लेगा या गांव पंचायतों को भेज दें। यह मैं सही नक्शा आपके सामने रख रहा हूं जो दिक्कत है वह आपके सामने रख रहा हूं। जैसा माननीय मित्र

ने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार लोग गड़बड़ी करते है । मैं तो कहता हूं कि जब तक गरीबों के बेटे हुकूमत में नहीं होंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है । जिनके दिल में दर्द होगा वही जान सकता है कि दर्द क्या होता है। ये मोटे-मोटे लोग एकदम किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आप देते हैं वह उसके पास तक पहुंचते-पहुंचते आधा हो जाता है। जो आपके काम करने वाले हैं वह आधा कर देते हैं और बाकी पैसा अपने जेबों में भर लेते हैं। इसके अतिरिक्त मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार अपने क्वार्टर्स बनवा दे तो बड़ी कृपा होगी। आपने सस्ते क्वार्टर्स बनवाये हैं, लेकिन हरिजनों के लिये क्वार्टर्स नहीं बनबाये हैं। इसलिये सरकार से यह कहना है कि हरिजनों के लिये भी कुछ क्वार्टर्स आप बनवा दें।

हमारे पास मेहतर हैं, चमार हैं जो सड़कों पर बसे हुये हैं। राजा साहब बस्ती का डंडा रोज चलता है कि तोड़ देंगे तुम्हारे छप्पर । तो कम से कम उनके मकान तो बनवा दे सरकार। ये गरीब आपके साथ हैं उनकी हमें ऐक्चुअल मदद करनी चाहिये ताकि आपका रुपया देना सफल हो । मैं सरकार से इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि ऐक्चुअल नक्शा सामने है। और यह जो आपने रुकावट डाली है कि बड़े लोगों को न दी जाय, छोटों को दी जाय तो यह तो बहुत सुन्दर चीज है । सरकार तो चाहती है कि जेनुईन लोगों को मिले । हम यह नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण गरीब नहीं है। ब्राह्मण भी गरीब है, ठाकुर भी गरीब है, चमार भी गरीब है आज दुनियां में अमीर और गरीब की लड़ाई है । गरीबों की लिस्ट बनवा लीजिये । अगर चमार अमीर हो तो उसको न दीजिये। लेकिन वहां तो डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की सरकार कोशिश करे ।

हम तो जैसा हमारी कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का एलान किया है उसके मुताबिक करने जा रहे हैं । हमारे विरोधी दल के लोग परेशान हैं कि सारा काम तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं हम क्या करेंगे ? मेरे मित्र ने गुड़ की बात कही । अरे कहां गुड़ की बात और कहाँ मकान की बात । गुड़ तो जब उस विभाग का अनुदान हमारे सामने आये तब उसकी बात कहनी चाहिये । हमारे एक मित्र ने ट्रैक्टर की बात कही, ट्रैक्टर तो बड़े-बड़े लोगों के पास हैं । सरकार लकड़ी वाले हल से जो जरा अच्छा हल हो वह हमारे किसानों को दे तो हमारे गरीब किसानों को बड़ी सुविधा हो। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि गांव के डेवलपमेंट की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिये क्योंकि यह गवर्नमेंट गांव की है, गांव के लोगों ने इस गवर्नमेन्ट को बनाया था । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय श्री विश्राम राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है सम्भवत : इस अनुदान को उन्होंने ठीक नहीं समझा । ९ करोड़ ५२ लाख रुपये का यह अनुदान है। इसमें सब मद अलग-अलग कर दिये गये हैं कि किस काम के लिये कितना रुपया चाहिये । उसमें एक तकावी की भी मद है । २ करोड़ १ लाख से वह घट कर, जो लोन है ऐग्रीकल्चरिस्ट के नाम, वह १ करोड़ २७ लाख के करीब हो गयी है। वह इसलिये घटी है कि और बहुत से कामों के लिये जो रुपया दिया जाता है वह काम डेवलपमेंट स्कीम्स के अन्तर्गत आ गया है। इसलिये वह रुपया उनमें ट्रान्सफर हो गया है। अब चूंकि वह रुपया उनमें ट्रान्सफर हो गया इसलिये इसमें लाने की जरूरत नहीं समझी गयी । डेवलपमेंट

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

स्कीम्स की जो बहुत सी योजनायें हैं उनमें १९ लाख २० हजार रुपये की भी एक रकम है। इसी प्रकार से और बहुत-सी रकमें अलग-अलग मदों में डाल दी गयीं । इसके सम्बन्ध में कुछ लोगों ने तकावी बांटने के तरीके के बारे में भी आलोचना की है । मैं निवेदन करूंगा कि तकावी के बांटने के तरीके से और इस अनुदान से कोई सम्बन्ध नहीं है । फाइनेन्स मिनिस्ट्री सिर्फ इतना करती है कि यह रकम लेकर अमुक विभाग को दे देती है। जैसे ६० लाख रुपये इसमें से वह लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को दे देगी लोन देने के लिये, इसी तरह से यह मिनिस्ट्री १२ लाख रुपया ऐग्रीकल्चरल इंजीनियर को ट्यूबवेल्स के लिये देगी और साढ़े पांच लाख रुपया केन कमिश्नर को देगी। इस प्रकार से हर मुहकमे को अलग-अलग रुपया दे दिया जायगा ताकि किसानों की सहायता के लिये इसका उपयोग किया जाय । बस इतना ही काम फाइनेन्स मिनिस्ट्री का है । अब वह विभाग कैसे उस रुपये को बांटता है, उसमें क्या दिक्कत होती है यह तो उस विभाग का जब बजट आये तो उसके सिलसिले में इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है। इससे कोई और सम्बन्ध नहीं है।

दूसरी बात अभी राजा साहब एक तकरीर करके चलते बने। उन्होंने यह कह दिया कि साहब यह कर्ज तो बड़े आदमियों को नहीं मिलता है और छोटे आदमियों को ही मिलता है इसलिये इसमें कोई भेदभाव न किया जाय । लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि रूरल क्रेडिट की जो जांच की जाती है और जो रूरल क्रैडिट की रिपोर्ट निकली है वह इससे उल्टी बात कहती है कि इसमें बड़े आदमियों को डेवलपमेंट का रुपया ज्यादा मिल जाता है और छोटों को नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट तो यह चाहती है कि जहां तक हो सके छोटे आदमियों को मिले । लेकिन मौजूदा प्रणाली में ऐसा ही होता है कि छोटे आदमी सिक्योरिटी दे नहीं पाते हैं । श्रीमन्, यह ऐसा ऋण है जिसमें लैंडेड प्रापर्टी की सिक्योरिटी होती है। ऋण लेने और देने वाला दोनों एक दूसरे की शकल नहीं देखते हैं और एक बीच की एजेन्सी कर्जा दे जाती है और ले जाती है। इस आधार पर जो लोगों को ऋण मिलता है तो जिसके पास छोटी जमीन है उसको तकाबी कम मिलेगी और जिसके पास बड़ी जमीन है उसको ज्यादा मिलेगी । उनको शिकायत तो यह होनी चाहिये थी कि छोटे आदमियों को कम मिलता है और बड़े आदमियों को ज्यादा मिलता है।

श्रीमन्, कटौती के प्रस्तावक महोदय ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेन्ट जो तकावी दे रही है उसके लिये अफसोस होना चाहिये । वह कम दे रही है किसानों की टोटल बारोइंग और प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहां कम है। जैसे कि रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट है कि यहां ०.९ है। यह परसेन्टेज यह है कि उत्तर प्रदेश में किसान अगर १०० रुपया लेता है तो गवर्नमेंट ०·९ लेती है, इसी तरह देश भर में ऐग्रीकल्चरल कामों के लिये यदि १३.३ लेता है तो गवर्नमेंट से २.८ लेता है, ऐसा ही हमारे प्रदेश के किसानों का बारोइंग स्ट्रक्चर है। इसमें उत्तर प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में कम है । कल पैप्सू की बहुत तारीफ की गई थी । वहां और राजस्थान में यह रकम हमारे यहां से कम है । यह सही है कि हमें ऐग्रीकल्चरल कामों के लिये और रुपया चाहिये और इतना ही दे पाते हैं कम है, सही है लेकिन बंटवारे में भेदभाव होता है यह चीज गलत है।

अभी हमारे मित्र विश्रामराय ने यह कहा था कि रामतीर्थ प्रतिष्ठान के लिये क्यों रुपया दिया जा रहा है?

श्री अधिष्ठाता--उन्होंने यह कहा कि दिया जा रहा है बड़ी अच्छी बात है लेकिन उनसे ५ प्रतिशत का सूद लिया जा रहा है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--श्रीमन्, जो रेट है गवर्नमेंट की तकाबी के लिये वह साढ़े पांच प्रतिशत है। जो रेट गवर्नमेंट को निश्चित करनी पड़ती है उसका कोई न कोई आधार हुआ करता है। लेकिन यह भी माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि लांग टर्म लोन और शार्ट टर्म लोन में हमेशा डिफरेन्स हुआ करता है। रामतीर्थ मिशन इस लोन से किताबों को पब्लिश करेंगे और उनकी बिक्री करेंगे। इसलिये उनके प्रकाशन के लिये जो रुपया उनको दिया जा रहा है उसका रिटर्न भी तो कुछ न कुछ होगा। अगर डेड डेट होता और फिर गवर्नमेंट इतना सूद लेती तब तो शिकायत की बात होती।

उद्योगों के बारे में जो लोन गवर्नमेंट से दिये जा रहे है उनके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें गुड़ इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज की कोई बात ही नहीं है. और इसका इस से कोई संबंध ही नहीं है। यह चीज तो जिस समय इंडस्ट्रीज विभाग का बजट पेश हुआ था उस समय आनी चाहिये थी इसमें तो केवल यह है कि जो उद्योग-धंधे हमारे प्रदेश में नहीं हैं और जिनके लिये कंज्यूमर्स का रुपया बाहर भेजना पड़ता है और जिन चीजों की बदौलत हमारा रुपया बाहर भेजा जा रहा है, उनके लिये हम इंडस्ट्रीज खोलने जा रहे है। उसके लिये काफी रुपया चाहिये और जिनको यह रुपया दिया जा रहा हैं उसमें पूंजीपतियों का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उन्हीं को यह रुपया दिये जाने का प्रबंध किया जा रहा है जो इन कारखानों को चला सकते हैं और जिनको इन कारखानों के चलाने का अनुभव है। इसमें न तो कहीं गुड़ की इंडस्ट्री आती है और न काटेज इंडस्ट्रीज आती हैं। यह तो शुद्ध की इंडस्ट्रीज के खोले जाने की ही बात है।

मान्यवर, आज हमारे उत्तर प्रदेश को इस बात की शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार ने कल कारखाने प्रदेश में खोलने के लिये हमें कुछ भी नहीं दिया है इसलिये हमें आगे अपने बल बूते पर ही बढ़ना है और अपने बूते पर अपने प्रदेश में कल कारखाने खोलने पड़ेंगे। जब केन्द्रीय सरकार रुपया नहीं देती है तो हमें ही प्रबंध करना है। इस साल हम साढ़े पांच प्रतिशत का प्रबंध कर पाये हैं। ईश्वर करे कि हम अगली योजना में इससे ज्यादा कर पायें। किन्तु यह प्रबंध भी जो कुछ है वह बहुत कम है और काटेज इंडस्ट्रीज की वृद्धि के अनुपात से इनमें और वृद्धि होनी चाहिये। हमें आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, देहातों में लोग कई प्रकार से ऋण लेते देते रहते हैं आपस में, पहले यह व्यवहार बहुत था और वह सालाना ब्याज पर और छमाही ब्याज पर ऋण लेते थे, लेकिन जमींदारी समाप्त होने के बाद लोगों को आपस का कर्जा मिलना बन्द हो गया, और सरकार की ओर से तकावी मिलने लगी तो लोग अमूमन सोचने लगे कि हमें तकावी मिल जाय तो उससे हमारा कल से काम चल जायगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो तकावी मिलती है, उसका एक बांड होता है, एक फार्म होता है जो भरवाया जाता है और उसमें जो बातें होती हैं वह भरवाकर तसदीक करायी जाती हैं। उसके तस्दीक करने की कार्यवाही में गांव का लेखपाल, सभापति, कानूनगो, तहसीलदार, अन्य कई आदमी तस्दीक करते हैं, उसके बाद वह तहसील में तस्दीक होता है। लेकिन इस काम में, तसदीक करने के, इतनी अव्यवस्था है कि जिनको जरूरत होती है वह अपने समय पर रुपया कभी भी नहीं पाते हैं। और जब पाते हैं तो जो सूद उनको देना है, उसका चार पांच गुना या जो तकावी उन्होंने ली उसका आधा तक इस तसदीक कराने में लग जाता है। लोग जब कागज

[श्री रामसुभग वर्मा]

लेकर जाते हैं तो पहुंच नहीं पाते हैं और पहुंचते हैं तो तस्दीक कराई दीजिये, इस तरह की बड़ी अव्यवस्था है। इसमें माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। तकावी जो बांटी जाती है, जैसा माननीय शिवनारायण जी ने बताया कि वह १० रुपये और २० रुपये तक भी होती है और इस तकावी को लेने के लिए भी उन लोगों को १५ और १६ मील से आना पड़ता है और काफी पैसा अपना खर्च करना पड़ता है, जैसे किसी को १० रुपया तकावी पानी थी तो उसका ५ रुपया खर्च हो गया आने जाने व तसदीक कराई में। इस तरह की अनेक परेशानियाँ हैं। जो तकावी उसको मिलती है, उसका परसेंटेज तहसील में बंधा हुआ है कि इतना परसेंटेज दोगे तो तकावी मिलेगी। बाढ़ग्रस्त लोगों को कुछ तकावी दी गयी। वह लोग अनेक मुसीबतों से परेशान रहे, लेकिन सरकार थोड़ी-थोड़ी तकावी उनको देती रही। वह लोग खाने-पीने के लिए परेशान थे, लेकिन जब वह तकावी के लिए आते थे तो उनको बार-बार लौटना पड़ता था और बहुत थोड़ी मात्रा में उनको तकावी मिलती थी। कुछ लोगों के घर नदी के कटाव से बह गये थे, उनको दो-दो, तीन-तीन मर्तबा एक जगह से दूसरी जगह बसना पड़ा, लेकिन उनको भी सरकार ने १० और १५ रुपया तकावी दी, जिस से न वह आसानी से अपना घर बना सकते थे और न एक छप्पर ही छा सकते थे, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो सरकार को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इसमें कोल्हू वाली तकावी भी शामिल है। कोई भी सरकार जो कर्जा बांटती है वह कर्जा समय से किसान को नहीं मिल पाता। अभी-अभी कोल्हू के लिए तकावी मंजूर होकर मिली है। अब वह तकावी ले कर कोल्हू ले जाये और अपने यहां लगाये जब कि गन्ने का सीजन खत्म हो गया। वे कोल्हू खरीद कर रखते हैं, उनको सूद देना पड़ता है, उन को समय पर तकावी नहीं मिलती है। सरकार को चाहिए कि जो भी उनको पैसा दे वह समय से दे। जो लोग खेती करने वाले हैं और जो जिस काम के लिए पैसा लेते हैं उनको समय से मिलना जरूरी है। नहीं तो वह काम उनका समय से नहीं होता है। कुओं के लिए जो तकावी लेते हैं वे कुआं खोदते हैं, वह खुदा पड़ा रहता है लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। वह बराबर आते जाते रहते हैं लेकिन उन को समय के भीतर पैसा नहीं मिल पाता है। या कोई और तरह का काम है, जिस के लिए वह रुपया लेना चाहते हैं। मान लीजिये कि बैल उनको खरीदना है उसके लिए वह तकावी लेना चाहते हैं। जब बैसाख या क्वार, कार्तिक के महीने में खेती का समय आता है तो उस समय उनको बैल की जरूरत पड़ती है। बैल खरीदने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तब वह बार-बार तहसील में जाते हैं लेकिन उनको समय से पैसा नहीं मिलता है, खेती का समय निकल जाता है। इसलिए मेरा मन्त्री जी से निवेदन यह है कि किसानों को समय के भीतर रुपया मिलना चाहिए। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि उनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसानों को समय पर जिस काम के लिए वह पैसा लेना चाहते हों, उसके लिए उनको समय पर तकावी मिल जाय।

श्री विश्राम राय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था, वह समझ कर रखा था। माननीय परिपूर्णानन्द जी की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मैं उनको समझा नहीं। मैंने इसको कुछ पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बारोइंग कैंपिसिटी बहुत कम है। यह किताब गेंदासिंह जी के पास थी और अगर मुझको कुछ पहले मिल जाती तो मैं इसको पढ़ लेता। मगर हाफिज जी ने कहा कि टैक्स देने की उनकी कैंपिसिटी बढ़ गयी है। इन दोनों बातों को कैसे समझा जाय? आप तकावी वसूली को देखिये, वह बढ़ी है। तो फिर बारोइंग कैंपिसिटी भी कम हो गयी, यह बात नहीं है। उनकी बारोइंग कैंपिसिटी कम थी और आज भी कम है लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कम हो गयी हो।

अब मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में २, १ बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--आप कोई नयी बात नहीं कह सकते।

श्री विश्रामराय--अभी गुड़ के सम्बन्ध में कहा गया कि इसमें ४ लाख रुपया गुड़ विकास योजना के लिए दिया हुआ है। वह अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई नयी बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव फिर सदन के सामने रखता हूं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जो बातें यहां पर कही गयी हैं वह तकावी की बाबत कही गयी हैं। वह जिस तरह की हैं और जो उनकी मेरिट है वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बतला दी जायगी, कि यह इसके मुताल्लिक यहां पर कहा गया और कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कि जवाब दिया जा सके।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक त--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण) के अन्तर्गत ९,५२,१४,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२० मार्च, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९० पर)

जिला	तहसील	ग्राम	जिला	तहसील	ग्राम
दोहरी घाट मुख्य नहर					
आजमगढ़	घोसी ..	रोंधा भगवानपुर			नाथुपुर
		सरैंया			मुंगेसर
		पाटनों बुजुर्ग			सिकरोल
		जोनराचौरा			बेला सुल्तांपूर
		बसियाराम			दरयाबाद
		गौठा			मिहवारा
		मुरादपुर			खिरामुन्मदपुर
		कुसमाहा			महलेरी
		हसनपुर			लखानी मुबारकपुर
		जमीनकुसुमाहम	बलिया	रसरा ..	बरोली रहालपुर
		बिसारदपुर			हैबतपुर
		अहरानी बुजुर्ग			तिरनई
		सरनगुआह			औनरईकलां
		मेहदुपार			किरहेरापेढ
		गौफा			आनन्दपट्टी
		नरहरपुर			मझवा
		रैवती नरहरपुर			जमलोली
		बैहरामपुर			हसनपुर
		कैलवार खालसा			मुकलिसपुर
		जमीन कालोबार			हारपर
		मानिकपुर हरोवन			बिकारया
		बंगावां			भीमपुर
		धोबाड़ी			करामापरा
		खर्रीपार			दाफारपुर
		बड़ागांव			लोहटा
		मानिकपुर असवां			भुजहैनी
		मुबारकपुर			तिवारीपुर
		सराय का कुलत			बीगहा जमीन
		सराय बारी			बीगहा
		नन्दवल			चरौन
		डंडनपुर			दरियापुर
		अहिरौली			चिटकियां
		अरंयासन			खांडवा
		घाउपुर			सपापाली
		चौबाल रामपुर			गैव्वापार
		पिरहवाल			मालीपुर
		भरितियाकादीपुर			गव्वापुर

जिला	तहसील	ग्राम	जिला	तहसील	ग्राम
		चिट्टाना			हजौली
		टिकनपुर			अंनकौलाही
		कमरौली			बिलासरा
		इन्डास			धाधानपुर
		ककारी			पाकुरेजी
		नरैही			आमोताहा
		इनामपुर			भालमती
		नरैही			करेजी
		मैहरांव			जोगापुर
		व्योरिया			कल्यानपुर
		सोनवानी	बलिया	बलिया	रामपुर असली
		विश्वनाथपुर			नवादा
		खारी			पैपरसांडा
		चकपंडित			गढ़वार
		औरसारा			मैमनोली
		सलेमपुर			तिरकालपुर
		चारा कोलहा			नगावा पांडे
		सरैयां			नराइनपाली
		अधारी पटी			बड़वान
		पकरी हलख			घुसौटी
		बहौरापुर			चन्दौकी
		बीराभटी			करनई
		गढ़वालपुर			गुरवा
		रतसी महिमापुर		कुकरौली माइनर	
		इन्दरपुर आराजी माफी]	आजमगढ़	घोसी ..	अहीरानी बुजुर्ग
		इन्दरपुर			सरनगुवा महद्- पार
		चौबेपुर			
		पंडापुर			अवहोरयरपारा
		मिस्फनारी			रेवतीनरहरपुर
		छिब्बी			सकरपुरपीरा
		पाहछिम्मी			कसीलाबेला
		मलकोली			बन्धनपुर
		दुमदारपुर			हातियाखाल
		आसनवर			चकहसन
		बासनवर			चकैब
		आलमपुर			विनायकपुर
		कुकराहा			जमनीपुर

जिला	तहसील	ग्राम
नैथपुर डिस्ट्रिब्युटरी		
आजमगढ़	घोसी ..	मोहम्मदपुर
		छपारा
		चकमुस्तफा
		चमरियनवा
		भरोपुरखास
		अनकानी मुबारकपुर
		दरयाबाद
		परवाजपुर
		बलभद्रपुर
		कुन्डाशरीफपुर
		दरौदामाधवपुर
		वालदापुर
		अलापुर
		कुशा
		नासिरपुर
		कलानापा
		रसूलपुर गौतम
		सुल्तानपुर गौतम
इन्दारा डिस्ट्रिब्युटरी		
आजमगढ़	घोसी ..	भरतियाकादीपुर
		लिलारीखास
		किवालापुर
		बेलाबांध
		हसाउपुर
		लैरौबिरवारे
		लैरो डोनवार
		इन्दारा
		मेहवार
सिकन्दरपुर डिस्ट्रिब्युटरी		
बलिया	बन्सदीह ..	चितौना
		पारसडांजोरन
		करीमपुर
		देवकली
		लौहार
		महारोन
		गाजीपकड़

जिला	तहसील	ग्राम
		बलीदापुर
		बैलातारी
		हजियामचक
		सिकन्दरपुर
पुर डिस्ट्रिब्युटरी		
बलिया	बंसदीह ..	गढ़मालपुर
		साहुला आई दोपट्टी
		पहराजपुर
		चकजलालपुर
		पुर
रतसर डिस्ट्रिब्युटरी व सुखपुरा माइनर		
बलिया	बंसदीह ..	राजसीमहिमापुर
		उकछी
		छिटपाली
	रसरा ..	सावन
		पखानपुरा
	बलिया ..	नदौली
		दिलावरपुर
		सिकरायाकलां
		अलीपुर
		ममराजपुर
		सिकारियाखुर्द
		हाथाउरी
		आराजीइंगलस
		तुरकीबारी
		पिपराकाला
		पचखोरा
	बांसदीह ..	कारामाइनर
		दुर्गीपुर
		बिरवारबारी
		जानपुर
		अगेसा

जिला	तहसील	ग्राम	जिला	तहसील	ग्राम
सुखपुरा माइनर					अपैल
					बसंतपुर
बलिया	बलिया ..	किरतपटी		नाथुपुर डिस्ट्रिब्युटरी	
		पडवार			
		सिकतौती			
		जनाउपुर	आजमगढ़	घोसी ..	गौफा
		जोगनएम रतसर			पिंडसुई आहलास-
		जगदेवपुर			पुर
		अरइपुर			दादानपुर अलुपुर
		टकोर			बदरा बुजुर्ग
	बांसदीह ..	हारपुर			सुलताँपुर
		भोजपुर			कपरयादीह
		सुखपुरा			इबराहीमाबाद
		पीरकपुर			सुल्तांपुर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुलियों पर वाटर-वे के विस्तार की योजना के अधीन लिये जाने वाले प्रत्येक वाटर-वे के लिये व्यय की तालिका

क्र० सं०	जिलों के नाम	सड़कों के नाम	मील	प्रस्ताव		लगभग लागत
				नये का	विस्तार	
१	२	३	४	५	६	७
						रु०
१	फर्रुखाबाद	छिवरामऊ बिधूना रोड (नवनिर्मित एम० डी० आर)	१०·११	२ १/२ फुट व्यास के ह्यूम पाइप कलवर्ट	फर्रुखाबाद डिवीजन	२,१००
				फर्रुखाबाद जिले का योग	..	२,१००
२	हमीरपुर	कानपुर-हमीरपुर-सोगोर रोड	४३	२ १/२ फुट व्यास की पुलिया	..	३,०००
		हमीरपुर-मुस्कारा रोड	१६	५ फुट की चौड़ाई के वर्तमान ३ पाये में २ अन्य पाये का विस्तार		८,०००
		बेतवा फेरी	..	सन् १९५४ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त बेतवा पिचिंग का विस्तार		२०,०००
		यमुना फेरी स्प्रोच रोड		पुलियों की रिटेनिंगवाल और आउटफाल		८,०००
		हरपालपुर-पनवारी रोड	६	२ पुलियां १० फुट के पाये की		२०,०००
				हमीरपुर जिले का योग	..	५९,०००
३	बहराइच	बहराइच-बहरामघाट रोड	१४	एक १० फुट चौड़ी पुलिया	गोंडा डिवीजन	७,५००
			१६	एक ५ फुट चौड़ी पुलिया	,,	३,५००
			२१	,, ,,	,,	३,५००
			२२	,, ,,	,,	३,५००
			२२	दो १० फुट ,,	,,	१५,०००
			२६	एक ५ फुट ,,	,,	३,५००
			२७	पाँच ५ फुट ,,	,,	१७,५००
		बहराइच-देवरिया रोड	५	एक ५ फुट चौड़ी पुलिया	,,	३,५००
		बहराइच-बलरामपुर रोड	७	एक ५ फुट ,,	,,	३,५००
			२०	एक ३० फुट ,,	,,	२,९००

१	२	३	४	५	६	७
						रु०
		२३	दो ५ फिट चौड़ी	पुलिया	गोंडा डिवीजन	७,०००
		२४	एक ५ फुट	,,	,,	३,५००
		२६	दो २० फुट चौड़ी	पुलियां	,,	३०,०००
		२७	एक ५ ,,	,,	,,	३,५००
		२८	दो ५ फुट	,,	,,	७,०००
		२९	एक ५ फुट और ४ फुट चौड़ी	चौदह पुलिया	एक पुलिया को ३ फुट से ५ फुट चौड़ा करना	४५,५००
			बहराइच जिले का योग		..	१,५९,५००
४	बस्ती	लखनऊ-गोरखपर रोड (नें० हा०)	९६	एक ७ १/२ फुट पुलिया	गोंडा डिवीजन	६,०००
			९८	,,	,,	,, ६,०००
		बस्ती--बांसी रोड	३२	एक १० ,,	,,	,, ७,५००
		बस्ती डोमरियागंज	२८	दो १० ,,	,,	,, १५,०००
			३१	दो १० ,,	,,	,, १५,०००
		डोमरियागंज-वरहम रोड	४८	दो १० ,,	,,	,, १२,०००
		खलीलाबाद-मेंहदावल रोड	८	एक १० ,,	,,	,, ७,०००
			बस्ती जिले का योग		..	५९,०००
५	गोंडा	बलरामपुर--तुलसीपुर रोड	२	दो पुलिया १०·१० फुट	गोंडा डिवीजन	१५,०००
			५	२ ,, ५·५	,,	,, ७,०००
			९	१ ,, ३	,,	,, २,०००
			११	२ ,, १०	,,	,, १५,०००
			१३	१ ,, ५	,,	,, ३,५००
			१६	१ ,, ५	,,	,, ३,५००
		बहराइच-बलरामपुर रोड	३०	१ ,, १०	,,	,, ७,५००
		उतरौला-बलरामपुर रोड	१३	३ ,, १०	,,	,, २२,५००
		गोंडा-उतरौला रोड	३	१ ,, ५	,,	,, ३,५००
		,,	२३	१ ,, १०	,,	,, ७,५००
			गोंडा जिले का योग		..	८७,०००

१	२	३	४	५	६	७
						रु०
६	इलाहाबाद	मूरतगंज-राजपुर रोड	१५	२ पाये १५१ के	गोंडा डिवीजन	३०,०००
		इलाहाबाद-फैजाबाद रोड	११	१ ३ फुट पुलिया	,,	३,०००
		इलाहाबाद-उन्नाव रोड	१२	१ ३ ,,	,,	३,०००
		,,	२२	१ ५ ,,	,,	५,०००
		भरतगंज-प्रतापपुर रोड (एम० डी० आर०)	१	३ १५ फुट छोटे पुल	,,	५०,०००
		,,	४७	३ १५ ,,	,,	५०,०००
		इलाहाबाद-बांदा रोड	२०	२ ह्यूम पाइप पुलिया	,,	६००
		,,	२१	,, ,,	,,	६००
		,,	२६	२ एक १ फिट की पुलिया	,,	४००
		,,	२७	२ फुट ह्यूम पाइप पुलिया	,,	६००
		,,	२८	,, ,,	,,	६००
		,,	२९	,, ,,	,,	६००
				इलाहाबाद जिले का योग	..	१,४४,४००
७	जौनपुर	लखनऊ–बनारस रोड	१५३	.. ..	,,	१०,०००
		,,	१७१	.. ..	,,	१०,०००
		लखनऊ–बलिया रोड	१२८	एक ५ फिट चौड़ी पुलिया	..	५,०००
		शाहगंज–तारकौतिया रोड	४	,, ,,	,,	५,०००
				जौनपुर जिले का योग	..	३०,०००
८	फैजाबाद	इलाहाबाद–फैजाबाद रोड	८१	एक पुलिया ३ फिट के पाये की	,,	२१,५००
			८३	,,	,,	
			८६	,,	,,	
				फैजाबाद जिले का योग	..	२१,५००

१	२	३	४	५	६	७
						रु०
९ आजमगढ़	इलाहाबाद-गोरखपुर रोड	१०२	(१) एक पुलिया १० फुट के पाये की (२) १० फुट चौड़े ५ पायों की पुलिया			४८,०००
	लखनऊ–बलिया रोड	१७०	एक पुलिया १० फुट चौड़े ६ पायों की			४८,०००
	बनारस–आजमगढ़ रोड	..	एक पुलिया १० फुट के २ पायों की दो पुलिया ५ फुट के २ पायों की			३२,०००
			आजमगढ़ जिले का योग		..	१,२८,०००
१० गाजीपुर	गोरखपुर–गाजीपुर रोड	६५	एक पुलिया १० फुट चौड़े ५ पायों की			३०,०००
			गाजीपुर जिले का योग		..	३०,०००
११ बलिया	लखनऊ–बलिया रोड	१९९	टी० बीम ब्रिज २० फुट पाये का			२०,०००
	,,	२०८	१० फुट पाये की पुलिया		,,	६,०००
	,,	२१०	५ फुट पाये की पुलिया		,,	३,०००
	,,	२१४	३ फुट	..	,,	१,८००
	,,	२१५	७ १/२ फुट	,,	,,	४,०००
	सिकन्दरपुर–बिल्थरा रोड	५	५ फिट	,,	,,	३,०००
			बलिया जिले का योग		..	३८,३००
१२ गोरखपुर	गोरखपुर–महाराजगंज रोड	१४	२ १/२ फुट व्यास की पुलिस		,,	२,५००
	केप्टेनगंज–तमकोही रोड	१.७	२० फिट पाये की पुलिया		,,	२५,०००
	फरेंदा–महाराजगंज रोड	१०.६	१० ,,	,,	,,	७,५००
	,,	११	पुलिया जो पिछली बार टूट गई थी उसका विस्तार		,,	१५,०००
	निचलौल–तूतीबारी सड़क	५.६	१० फुट पाये की पुलिया		,,	७,५००
	,,	६.०	१० ,,	,,	,,	७,५००
	,,	८.०	८० फुट लम्बे काठ का पुल		,,	३०,०००

१	२	३	४	५	६	७
						रु०
	सिसवा–हाता सड़क	११·१	१०	फुट स्पेन कलवर्ट	डिवीजन	१०,०००
	,,	११·३	५	,,	,,	५,०००
	,,	१२·६	३	,,	,,	३,०००
	,,	२९·३	५	,,	,,	५,०००
	,,	३१·८	५	,,	,,	५,०००
	सिसवा–निचलौल रोड	९·०	५	,,	,,	४,०००
	,,	१०·०	३	,,	,,	२,५००
	,,	११·०	३	,,	,,	२,५००
				गोरखपुर जिले का योग	..	१,३२,०००
३ देवरिया	गोरखपुर–कसिया–तमकोही सड़क	५०·०	५	फुट पाये की पुलिया	,,	४,०००
	,,	५१·०	५	,,	,,	४,०००
	कप्टेनगंज–सिकता रोड	३·७	२ १/२	व्यास ह्यूमपाइप कलवर्ट		१,०००
				देवरिया जिले का योग	..	९,०००
गाजीपुर	बलिया–गाजीपुर रोड	५			,,	४,२०,०००
४ सीतापुर	सिधौली–महमूदाबाद लोकल सड़क	७·६	एक ५	फुट पाये की पुलिया	,,	४,०००
	,,	८·४	३	,,	,,	३,०००
	,,	९·१	३	,,	,,	३,०००
	,,	१२·८	३	,,	,,	३,०००
	,,	१३·४	३	,,	,,	३,०००
	,,	१८·८	३	,,	,,	३,०००
	सिधौली–विस्वां लोकल रोड	२·२	३	,,	,,	३,०००
	,,	२·५	५	,,	,,	४,०००
	,,	३·२	५	,,	,,	४,०००
	,,	५·२	दो ५	फुट चौड़े पाये की पुलिया	,,	७,०००
	,,	५·१	एक ५	फुट चौड़े पाये की पुलिया	,,	४,०००
	,,	८·३	,,		,,	४,०००
	,,	८·७	एक ३	फुट चौड़े पाये की पुलिया	,,	३,०००
	,,	१३·२	एक ५	फुट चौड़े पायों की पुलिया	,,	४,०००
	,,	१७·२		,,	,,	४,०००

१	२	३	४	५	६	७
						रु०
		सीतापुर–बहराइच रोड	१३.५	एक ५ फुट चौड़े पायों की पुलिया	डिवीजन	४,०००
		,,	२०.५	एक ३ ,,	,,	४,०००
		सीतापुर–बहराइच रोड	२९.६	दो १० फुट चौड़े पाये की पुलिया	,,	१०,०००
		सीतापुर–मिसरिख–बेनीगंज रोड	५·५	,,	,,	५,०००
		,,	१०·६	,,	,,	५,०००
		,,	११·८	,,	,,	५,०००
		,,	१५·५	,,	,,	५,०००
		,,	१५·६	,,	,,	५,०००
		,,	१७·२	,,	,,	५,०००
		हरगांव-वारागांव रोड	२·४	एक २ फुट चौड़ा ह्यूम पाइप	,,	५,०००
				सीतापुर जिले का योग	..	१,०९,०००
१४	खेरी	लखीमपुर–ऐरा रोड	६·२	३ स्पेन्स २ फुट चौड़े ह्यूम पाइप	,,	३,०००
		,,	६·६	,,	,,	३,०००
		,,	६·८	,,	,,	३,०००
		,,	१२·२	,,	,,	३,०००
		,,	१५·२	पुलियां ५ फुट चौड़े दो पाये	,,	९,२५०
		मंगलीपुरवा-निघासन सड़क	१९·७	३ फुट चौड़ी पुलिया	,,	४,०००
		,,	२०·५	१ फुट व्यास एच० पी० पुलिया	,,	१,२००
		गोला सिकन्दराबाद सीट सी० ट्रैक	१·०	३ फुट चौड़े पाये पुलिया	,,	१,५००
		,,	२·०	,,	,,	१,५००
				खेरी जिले का योग	.. ..	२९,४५०
				गोरखपुर जिला	..	१,३२,०००
				देवरिया जिला	..	९,०००
				गाजीपुर जिला	..	४,२०,०००
				सीतापुर जिला	..	१,०९,०००
				खेरी जिला	..	२९,४५०
				कुल योग		६,९९,४५०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय के तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ के उत्तर

उत्तर—१

पंचायतों अदालतों द्वारा किये गये निर्णयों के विरुद्ध जनवरी ५३, से जनवरी, ५५ तक विभिन्न परगनाधीशों के यहां निम्नलिखित निगरानियां दाखिल हुईं :

प्रश्न-संख्या	नाम परगनाधीश	जनवरी ५३ से जनवरी ५५ तक जो निगरानियां दाखिल हुईं	
		माल	फौजदारी
१	लालगंज	४० ..	२२९
	सदर	१८ ..	६६
	फूलपुर	७० ..	२१८
	घोसी	८८ ..	२६२
	सगड़ी	१९ ..	१६५
	मुहम्मदाबाद	३४ ..	१३६
	योग ..	२६९ ..	१,०७६

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

उत्तर—२

सम्बन्धित परगनाधीशों के यहां निम्नलिखित निगरानियां बहाल एवं खारिज हुई हैं :

प्रश्न-संख्या	नाम परगनाधीश	संख्या निगरानी जो बहाल रही		संख्या निगरानी जो खारिज हुई	
		मा०	फौ०	मा०	फौ०
२	लालगंज	२१	१८३	१८	२६
	सदर	१३	३५	५	३१
	फूलपुर	५०	१५०	१३	६८
	घोसी	७८	१६४	१०	७७
	सगड़ी	६	१३४	१३	३१
	मुहम्मदाबाद	२३	१०३	११	३३
	योग ..	१६८	७६६	७०	२६६

नोट—लालगंज में १ माल तथा १७ फौजदारी मुकदमे बाकी रहे।
घोसी में २१ फौजदारी के मुकदमें बाकी रहे।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६ एल० ए०—१६५६—७६६।